हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 को अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

17.03.2016/1100/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2941

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना का शुभारम्भ आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर एल0ई0डी0 बल्ब बांटने के लिए किया है। यह प्रश्न इसी माननीय सदन में पिछली बार भी लगा था और आपने उत्तर दिया था कि यह एक स्वैच्छिक योजना है। । पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो स्वैच्छिक योजना है, इसको लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या हिमाचल प्रदेश के जो 19 लाख 66 हजार के लगभग उपभोक्ता हैं, क्या उन्होंने आपको लिखकर दिया है कि हम प्रदेश के अंदर एल0ई0डी0 के बल्ब लगाना चाहते हैं और उसके उपरांत आपने यह स्वैच्छिक योजना हिमाचल प्रदेश में चालू करने की कोशिश की? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया है, आपके इस उत्तर में और जो आपने पहले उत्तर दिया था, उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। क्या यह सत्य है कि एच.पी.एस.ई.बी.एल. ने एक एम.ओ.यू. EESL के साथ किया कि आपने हिमाचल प्रदेश के अन्दर एल.ई.डी. बल्ब लगाने हैं? उसके उपरांत फिर EESL ने अगला एम.ओ.यू. दिस्कॉम कम्पनी के साथ कर दिया। उसने फिर अगला एम.ओ.यू. मैसर्ज क्रॉप्पटन ग्रीव्ज़ और मैसर्ज़ एन.टी.एल. के साथ कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो 19 लाख 66 हजार उपभोक्ता हैं, जिनके मीटर लगे हैं, जब उन्होंने आपकी इस स्वेच्छिक योजना के लिए आवेदन ही नहीं किया तो फिर आपने कैसे तीन स्टेजिज़ में एग्रिमैंट कर दिए। जैसे मैंने कहा कि आपने पहली कम्पनी के साथ किया, उसने दूसरी के साथ, दूसरी ने तीसरी के साथ एग्रिमैंट किया। पहली ने भी मुनाफ़ा कमाना है, दूसरी ने भी और तीसरी ने भी मुनाफ़ा कमाना है। अच्छा होता अगर ऐसी स्वैच्छिक योजना आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर चलानी थी तो क्यों बिजली बोर्ड ने अपने तौर पर इस प्रदेश के अंदर एल.ई.डी. बल्ब लगाने की योजना स्वयं शुरू नहीं की?

17.03.2016/1100/केएस/डीसी/2

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्रीय स्कीम है और उन्हीं की एजैंसी है। वे एक को देते हैं, दूसरे को देते हैं या तीसरी को देते हैं इसके साथ हमारा कोई कन्सर्न नहीं है। हम तो सिर्फ डिस्ट्रिब्यूशन में इन बल्बों को लोगों तक पहुंचाने में उनकी सहायता करते हैं बाकी इसमें हमारा कुछ भी लेन-देन नहीं है।

महेन्द्र सिंह जी, अ0व0 की बारी में--

17.3.2016/1105/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 2941--------- क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान प्रश्न संख्या 2440 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह प्रश्न यहां हाउस में इसी विषय पर लगा था। आपके लिखित उत्तर में है कि यह केंद्रीय स्कीम नहीं है और आप कह रहे हैं कि यह केंद्रीय स्कीम है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह केंद्रीय स्कीम है या प्रदेश की स्कीम है या फिर किसी की स्कीम नहीं है? क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अगर यह किसी की स्कीम नहीं है तो आप इसको लागू क्यों कर रहे हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एंव ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा कि यह केंद्रीय स्कीम नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपने आज ही कहा है कि यह केंद्रीय स्कीम नहीं है। यह केंद्रीय स्कीम है और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का ई0ई0एस0एल0 के साथ एम0ओ0यू0 हुआ है। एल0ई0डी0 भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी स्कीम है तथा यह सारे देश में चल रही है। यह केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं चल रही है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के अंतर्गत 7 वॉट के 3 एल0ई0डी0 बल्ब ई0एम0आई0 स्कीम के अंतर्गत बांटे जा रहे हैं और दो बल्ब कैश पेमैंट के आधार पर बांटे जा रहे हैं। जो बल्ब बांटे जा रहे हैं इसके लिए आपने कहा कि यह एक केंद्रीय स्कीम है। मगर मैं हाउस के बीच में कह रहा हूं कि यह केंद्रीय स्कीम नहीं है। यह एक स्वैच्छिक योजना है और जो स्वैच्छा से लगाना चाहे लगा सकते हैं। जिस बल्ब की कीमत आप 100 रुपये, 105 रुपये और 130 रुपये ले रहे हैं यही बल्ब मार्किट में इससे भी कम राशि में उपलब्ध हो रहे हैं। आपने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि आज तक लगभग 44 लाख बल्ब बांट दिए हैं। आपने तीन स्टेजों पर एग्रीमैंट किया है। पहले आपने ई0ई0एस0एल0 को काम दिया फिर उसने आगे डिस्कॉम को दिया और डिस्कॉम ने बाद में क्रॉम्प्टन ग्रीव्ज

लिमिटिड को दे दिया। तीन जगह नफ़ा कमाया जा रहा है और उस पैसे की रिकवरी हिमाचल प्रदेश के उन उपभोक्ताओं से हो रही है जो इन पांच बल्बों को ले रहा है। यह बोझ उनके सिर के ऊपर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को जो 100 रुपये, 105 रुपये और 130 रुपये के हिसाब से 7 वॉट के एल0ई0डी0 बल्ब दे रहे हैं क्या आप ओपन मार्किट में इसका वास्वतिक रेट पता करवायेंगे? आपके द्वारा दिये जा रहे बल्ब का रेट अगर ओपन मार्किट के हिसाब से गलत होगा तो क्या आप इस बारे में छानबीन करवायेंगे? कुछ उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिन्होंने बल्ब नहीं लिए हैं मगर उनके बिजली के बिल में दस-दस रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से काटे जा रहे हैं। क्या आप इस बारे में भी छानबीन करवायेंगे?

अध्यक्ष : यह जवाब तो आ गया है कि जो बल्ब दिए जा रहे हैं यह किसी कॉस्ट पर दिए जा रहे हैं और इसमें प्रोफिट के सम्बंध में, the Government is not concerned about it.

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो बल्ब लोग कैश में खरीद रहे हैं उसकी कीमत तो 100 रुपये हैं तथा तीन बल्ब जो किश्तों पर ले रहे हैं उसमें दस रुपये प्रति बल्ब की कीमत के हिसाब से काटे जा रहे हैं तथा उस बल्ब की कीमत 105

रुपये है। यह एक केंद्रीय स्कीम है तथा प्रधान मंत्री द्वारा इस स्कीम का निरंतर रिव्यू किया जाता है। यह स्कीम हिमाचल प्रदेश की नहीं है। हम तो केंद्र सरकार की इन बल्बों को बांटने में सहायता कर रहे हैं, असली बात यह है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न प्रदेश के लगभग 19.50 लाख उपभोक्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न के 'क' भाग में जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है,

टीसी द्वारा जारी

17.03.2016/1110/TCV/AG/1

प्रश्न संख्याः 2941 -- क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह ----- जारी

इसमें इन्होंने कहा है कि LED बल्ब वितरण की योजना M/s Energy Efficiency Services Ltd. जोकि केन्द्र सरकार का उपक्रम है के माध्यम से विद्युत बचत के उद्देश्य से स्वैच्छिक उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। एक तरफ माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में ये बात कही है। दूसरी तरफ ये खुद कह रहे हैं कि हमारा जो MOU है वह EESL के साथ साईंन हुआ है। इस प्रश्न का जवाब जो आपने लिखित रूप में दिया है और जो आपने अनुपूरक प्रश्न का जवाब दिया हैं इनमें अन्तर है। दूसरे, माननीय मंत्री महोदय, ये कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई लेना-देना नहीं है जबकि अध्यक्ष महोदय यह MOU M/s Energy Efficiency Services Ltd. और Managing Director, HPSEBL, विद्युत भवन शिमला के साथ हुआ है, फिर सरकार कैसे अपने आपको इसमें पीछे हटा रही है। यह सही है कि केन्द्र द्वारा LED बल्ब के ऊपर प्रदेश को उपदान दिया गया है और मेरी जानकारी के अनुसार जो 7 मैगावाट का बल्ब है, उसकी कीमत भारत सरकार ने 62 रूपये से 65 रूपये तक आंकी है। लेकिन यहां पर आप उपभोक्ताओं को 100,105 और 130 रूपये के हिसाब से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें धांधली हुई है और हो सकता है न हुई हो। लेकिन ये जो सारे प्रश्न उठ हैं ये आपके जवाब में से ही प्रश्न उठे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, भारत सरकार हमें इसके ऊपर कोई भी उपदान नहीं दे रही है। हम भारत सरकार की जो स्कीम है,उसको लागू करने में सहायता कर रहे हैं। This scheme is reviewed by the Prime Minister regularly. क्या विपक्ष चाहता है कि प्रधान मंत्री द्वारा रिव्यूड की जा रही स्कीम जिसमें हम उनकी इम्दाद कर रहे हैं, उसको हम बन्द करवा दें?

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री जी की मंशा बड़ी साफ है। प्रधान मंत्री जी ने इस योजना को इस देश के अन्दर इसलिए लागू करने के लिए कहा कि यह स्वैच्छिक योजना है। इसके जो

17.03.2016/1110/TCV/AG/2

उपभोक्ता इस प्रदेश या देश के अन्दर जिन-जिन राज्यों में हैं, क्या वह उपभोक्ता चाहते हैं कि LED के बल्ब लगांए और LED के बल्ब लगाने से उनके बिजली के बिल कम हों? लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी हिमाचल प्रदेश में पहले ही हमारे पास सरप्लस पॉवर्ज़ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारा जो संदेह है कि जो LED के बल्ब हैं, इनकी कीमत ओपन मार्किट में कम हैं और जो रिक्वरी उपभोक्ताओं से की जा रही है वह ज्यादा है। इसके MOU की कापी हमारे पास है ये पिछले सैशन में प्रश्न लगा था उस समय ले की गई थी। इसके अतिरिक्त वह आपसे 2 परसेंट एनुवल मैंटेनेंस चार्जिज वसूल करेंगे। दूसरे, वह आपसे 8 परसेंट डैविट इंट्रेस्ट वसूल करेंगे। इसके साथ-साथ रिटर्न ऑन-इक्विटी वह 23.48 परसेंट रिक्वर करेंगे। इस तरह एक भारी भरकम बोझ आप हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? माननीय प्रधान मंत्री जी की जो योजना है, वह बीच में 3-3 बिचौलियों को शामिल करने के लिए नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यह जो बाजार की कीमत है और जो आप कीमत वसूल कर रहे हैं, उसमें जो अन्तर है, उस अन्तर को EESL से वसूल करके उन उपभोक्ताओं को जिनको आपने 44 लाख बल्ब दे दिए हैं, उनको आप वापिस करेंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माल रोड के ऊपर एक जुता खरीदने गया और उसने मुझे उसकी कीमत 12 हजार रूपये बताई। वहां से

निकलकर मैं दूसरी दुकान पर गया तो उसने मुझे जुते की कीमत 3 हजार रूपये बताई । मैंने कहा इतना फर्क क्यों है?

श्री आर0के0एस0 द्वारा --- जारी।

17.03.2016/1115/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2941...क्रमागत

बहुदउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ... जारी

उसने मुझे जवाब दिया कि यह चीन का बना हुआ है। जिन बल्बों की कीमत 60 रुपए या 62 रुपए बताते हैं वे चीन के बने हुए बल्ब हैं। उन बल्बों को हम अपने उपभोक्ताओं को नहीं देंगे।

अध्यक्षः आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, जो ये बल्ब दो अलग-अलग कंपनियों से लिए गए हैं, इनमें आधे से ज्यादा एल.ई.डी.बल्ब चाईना के बने हुए हैं। क्या आप इसकी जांच करवाएंगे? साथ ही जिन उपभोक्ताओं से, इन बल्बों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, क्या उसकी रिकवरी EESLसे करवाकर उपभोक्ताओं को पैसा वापिस करवाएंगे?

बहुदउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः जो बल्ब हमने उपभोक्ताओं को दिए हैं अगर वह चाईना के बने हुए पाए गए, तो हम पैसा वापिस देंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने किस कंपनी से बल्ब खरीदे हैं, कोस्ट प्राईज क्या है, किस कीमत पर उपभोक्ता को दिए जा रहे हैं और हैंडलिंग चार्जिज कितना लिया जा रहे है?

बहुदउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, हम बल्ब नहीं खरीदते हैं। हम केवल डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी सहायता करते हैं। हम बल्ब नहीं खरीदते हैं।

17.03.2016/1115/RKS/AG/2

अध्यक्षः माननीय धूमल जी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, फिर खरीदता कौन है? आप कहते हैं कि हम सर्विस में मदद करते हैं। इन बल्बों को खरीदता कौन है? कितने में खरीदता है, कितने में देता है, कितना हैंडलिंग चार्जिज ले रहा है? प्रदेश सरकार क्या उपभोक्ता का हित करने के लिए है, या उसकी सेवा करने के लिए है जो सप्लायर है? खरीदता कौन है, बांटता कौन है, हैंडलिंग चार्जिज कौन लेता है और प्रदेश सरकार क्या सर्विस कर रही है?

बहुदउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष जी, एल.ई.डी. बल्ब वितरण योजना मैसर्ज एनर्जी एफिशियंसी सर्विसिज लिमिटिड, कम्पनी की है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः यह जो मैसर्ज एनर्जी एफिशियंसी सर्विसिज लिमिटिड है यह भारत सरकार की है। इन्होंने तो केवल योजना बनाई है। आपके पास यदि उत्तर इस समय नहीं है तो क्या आप इसकी जानकारी हाऊस में देंगे कि इन बल्बों को परचेज कौन करता है, किस रेट पर परचेज हो रहे हैं, किस रेट पर उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं, इसमें हैंडलिंग चार्जिज कितने हैं?

मुख्य मंत्रीः इसके बारे में कोई कन्फयूजन है। वास्तविकता यह है जो एल.ई.डी.बल्बज बिजली बोर्ड को सप्लाई किए गए हैं, उन बल्बों को EESL जो कि भारत सरकार की पब्लिक सैक्टर कम्पनी है, सप्लाई करती है और उनके द्वारा ही ये बल्ब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर कोई उपभोक्ता इन्सटॉलमेंट में पेमेंट करना चाहता है तो उस केस में 10 रुपए प्रति माह जिस उपभोक्ता ने बल्ब लिया है उससे पैसा कलैक्ट करके भारत सरकार के उपक्रम EESL को भेजा जाता है। हिमाचल सरकार या बिजली बोर्ड का एल.ई.डी. बल्ब परचेज

करने में कोई हाथ नहीं है। इसे EESL के द्वारा परचेज किया गया है। अगर इसकी निर्धारित कीमत उसी वक्त दे दी जाए तो ठीक है, अगर कोई इन्सटॉलमेंट में देता है तो हर महीने 10 रुपए इन्स्टॉलमेंट का जमा करके बिजली बोर्ड उस पैसे को EESL को भेजता है।

17.03.2016/1115/RKS/AG/3

अध्यक्षः भारत सरकार की जो कम्पनी है वह इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देती है और इसमें जो रेट वह लगाएंगे वही आगे इम्पलीमेंट कर रहे हैं। अब इममें क्या है?Answer is very clear.

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी

17.03.2016/1120/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 2941 .. जारी

माननीय अध्यक्ष...जारी

महेन्द्र सिंह जी, अब आप और क्या पूछना चाहते हैं?

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ई.ई.एस.एल. कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है, इसलिए वह इन बल्बों को दे रही है। बिजली बोर्ड ने जो MoU किया वह ई.ई.एस.एल. के साथ किया और ई.ई.एस.एल. ने आगे डिसकॉम के साथ किया। डिसकॉम ने आगे क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटिड और एम.टी.एन.एल. से किया। मेरा प्रश्न है कि जो ई.ई.एस.एल.के साथ MoU हुआ है, इसमें Agreement के Clause 1.2 Scope of Work में जो है, (1) Cost of LED Bulb (2) Distribution Cost (3) Awareness Cost (4) Transportation Cost (5) Storage Cost (6) Annual Maintenance Cost (7) Debit Interests (8) Cost Return on Equity and Applicable Taxes, इस सारी कॉस्ट को डालकर बल्ब खरीदे गए हैं। मैं सरकार, मंत्री

और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस 7 वाट के बल्ब की कीमत ओपन मार्किट में 62 रुपये है और आप हिमाचल के उपभोक्ताओं से 100 रुपया प्रति बल्ब, 105 रुपया प्रति बल्ब और 130 रुपया प्रति बल्ब के हिसाब से रिकवरी कर रहे हैं। क्या यह न्यायोचित है?

माननीय मुख्य मंत्री : आपका प्रश्न अनुचित है। आप हर चीज में गलती ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले कह चुका है, सही स्थिति यह है कि यह बल्ब हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को भारत सरकार के उपक्रम ई.ई.एस.एल. के द्वारा सप्लाई किए गए हैं और उन्होंने ही इनकी बिक्री की कीमत निर्धारित की है। उसी के मुताबिक उपभोक्ता पैसा दे रहे हैं। जो उपभोक्ता इसका पैसा एक साथ देता है वह आगे जाकर बिल में नहीं कटता। लेकिन अगर कोई इनस्टालमैंट में देता है तो उससे 10 रुपये प्रति मास के हिसाब से कीमत काट कर वह पैसा वापिस ई.ई.एस.एल.को भेजा जाता है। So where the HPSEBL has

17.03.2016/1120/SLS-AS-2

come into picture. They are only doing distribution on their behalf. और दूसरी बात यह है कि English केवल हिमाचल में ही नहीं है। The Scheme is being implemented on a uniform basis all over the Country. हिमाचल में ही नहीं है they are distributing in the entire Country. There is no separate method by which the bulbs have been supplied in Himachal Pradesh वह कंपनी ही प्रोक्योर करती है और वही बेचने की कीमत निर्धारित करती है। बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं से उसके पैसे बसूल कर कंपनी को देता है। यही बात है।

17.03.2016/1120/SLS-AS-3

प्रश्न संख्या : 2942

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उसके मुताबिक फोरैस्ट लैंड डाईवर्सन का केस रिजनल ऑफिस देहरादून को 10 मार्च, 2015 को भेजा गया था। उत्तर में आगे लिखा है कि 27.08.2015 को रिजनल एम्पॉवर्ड कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कुछ क्वैरीज रेज हुई थीं। उन क्वैरीज का रिप्लाई दिया गया है लेकिन उसकी तारीख नहीं लिखी है। जो प्रश्न का उत्तर है वह बड़ा अस्पष्ट (vague) है। इसके साथ-साथ मुझे बड़े दुख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि

जारी ...गर्ग जी

17/03/2016/1125/RG/AS/1

प्रश्न सं. 2942---- क्रमागत

श्री कृष्ण लाल ठाकुर----क्रमागत

लगभग तीन वर्ष पहले प्रदेश सरकार ने जो इण्डस्ट्रीयल एरियाज़ घोषित किए थे उसमें दभोटा नालागढ़ में था,कन्द्रोडी कांगड़ा में था और तीसरा पंडोगा ऊना में था। कन्द्रोडी का एरिया लगभग एक वर्ष पहले स्वीकृत हो गया और हरोली का तो स्वीकृत होना ही था क्योंकि माननीय मंत्री जी का यह चुनाव क्षेत्र है। जबकि माननीय मंत्री जी से अपेक्षा की जाती है कि ये पूरे हिमाचल को एक नजर से देखें, लेकिन पूरे हिमाचल की बात तो अलग है ये तो पूरे जिले को भी एक समान दृष्टि से नहीं देखते हैं और ऊना जिले को भी हरोली तक ही सीमित कर दिया है। तो यह बड़े दुःख की बात है और इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत घाटा होने वाला है। चलिए, यह तो बाद की बात है।

Speaker: Please, ask your question.

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अभी तो मेरा इस प्रश्न से संबंध है। अतः माननीय मंत्री जी बताएं कि 10 मार्च और 27 अगस्त के बीच इन्होंने इसके लिए क्या-क्या प्रयत्न किए? क्या कोई

रिमाइन्डर दिया गया या इसको हल करने के लिए वन विभाग से कोई देहरादून गया और 27 अगस्त के बाद जो रिप्लाई दिया है वह किस डेट को दिया है? यहां माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि जल्दी-से-जल्दी इसको स्वीकृत करवा दिया जाएगा।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विधायक बनने से पहले सरकारी अधिकारी रहे हैं और किस ढंग से कार्य होता है, उस सारे तौर-तरीकों को ये जानते हैं। मैं इनकी चिन्ता से तो वाक़िफ हो सकता हूं कि इनकी चिन्ता क्या है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, इस बात की चिन्ता करने की इनको जरूरत नहीं है। वह हम स्वयं देखे लेंगे। लेकिन जहां तक यह प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हरोली भी इसी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और उसी ढंग से है जिस ढंग से ये पिछले समय में सोलन के लिए किया करते थे। अगर मैं हरोली से विधायक हूं तभी मैं मंत्री बनकर यहां सदन में जवाब दे रहा हूं। अगर मैं विधायक नहीं होऊंगा, तो जवाब कैसे दूंगा?
अध्यक्ष महोदय, जहां तक इण्डस्ट्रीयल एरियाज़ का सवाल हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन इण्डस्ट्रीयल एरियाज बनाने का फैसला किया जिसमें एक कांगड़ा, दूसरा ऊना और तीसरा सोलन में है। क्योंकि कन्द्रोडी में environment

17/03/2016/1125/RG/AS/2

clearance नहीं लगती थी, तो सबसे पहले कन्द्रोडी का इण्डस्ट्रीयल एरिया स्वीकृत हो गया। उसको 25 करोड़ रुपये की राशि जा चुकी है। माननीय सदस्य यहां बैठे हैं इनके क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये जा चुके हैं। पंडोगा और दभोटा में environment clearance attract होती है। पंडोगा के लिए environment clearance आ गई है और वहां के लिए भी 25 करोड़ रुपये की राशि जारी हो गई है। जहां तक दभोटा का सवाल है, तो माननीय सदस्य को स्वयं भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि विधान सभा में ही सवाल उठाना है। वहां इण्स्ट्रीयल एरिया के लिए जितना एरिया लगना है, जितना एरिया उसमें आएगा उसकी एवज़ में उतनी ही जमीन, निजी भूमि नहीं, सरकारी भूमि ढूंढकर उस पर पेड़ लगाए जाने हैं। माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र या अपने जिले में वह भूमि आईडैन्टीफाई करवा दें। जितने पेड़ वहां से कटने हैं और उसके एवज में जितने पेड़ वहां पर लगने हैं। अभी 27-8-2015 को हमारी सरकार हमारा विभाग देहरादून में मीटिंग में मसला लेकर गए थे। पहले हम इसको भारत सरकार के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि

इसकी पॉवर देहरादून के पास है। तो हम उसके बाद 27-8-2015 को देहरादून में भी केस ले गए। उन्होंने कहा कि आप इसकी एवज में लैण्ड आईडेंटीफाई करके हमें दें। तो जैसे ही आप लैंड आईडेन्टीफाई करवा देंगे, हम उनको बता देंगे कि यह लैंड हमने आईडेन्टीफाई की है। आप हमारा केस क्लेयर करवा दें। इण्डस्ट्रीय एरिया खोलने के लिए पूरी सजगता से मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देशों के अनुसार हम प्रयासरत हैं।

अध्यक्ष : अब क्या बात है?

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अभी इसका 'सी' पार्ट रह गया है। माननीय मंत्री जी ने आज बताया कि इक्यूवैलेंट लैण्ड उपलब्ध करवानी है, तो यह तो सरकार की डियुटी है। अगर इसके बाद भी मेरी सहायता की आवश्यकता है, तो I am always at your disposal but basically यह सरकार ने करना है। एक तो बताएं कि क्या यह लैंड जिले के अंदर उपलब्ध करवानी है उसके लिए कौन हमें बताएगा और कौन अधिकारी आपके विभाग की तरफ से जाएगा?

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1130/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2942क्रमागत----श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी-------

मैं प्रश्न के "सी" पार्ट की भी बात करूंगा। हालांकि काम तो नहीं हुए परन्तु जवाब भी इसका बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा अदूवाल में बायो टैक्नोलोजी पार्क बनाने के बारे में प्रश्न था। इसके बारे में मैंने पिछली बार जब पूछा था तो उस वक्त मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इंट्रस्टिड पार्टी कोई नहीं आ रही है इसलिए यह डिले हो रहा है। आज कोई और ही जवाब दे दिया कि इसमें फॉरेस्ट डायवर्शन की बात है। मुझे जहां तक जानकारी है उसके अनुसार यह फॉरेस्ट लैण्ड नहीं है और न ही यह आई0टी0 डिपार्टमैंट की लैण्ड है। माननीय मंत्री जी बताएं कि यह लैण्ड किस विभाग की है?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, जहां तक अदूवाल का सवाल है इसके बारे में पूर्व सरकार के समय में, जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने वर्ष 2011 में यह फैसला किया था कि यह लैण्ड साइंस एण्ड टैक्नोलोजी डिपार्टमैंट के नाम पर हो। अब जो बायो टैक्नोलोजी पार्क का काम करना था वह उस विभाग ने करना था। बाद में उस वक्त की केबिनैट ने डिसाइड किया कि यह लैण्ड उद्योग विभाग के नाम कर दी जाए। जब उद्योग विभाग के नाम जमीन करने का फैसला किया तो यूजर एजैंसी बदल गई। हमने लगातार एन0ओ0सीज0 लेने के लिए कोशिश की। ग्राम पंचायत भोगपुर के एन0ओ0सी0 दिनांक 24-11-2014 और 27-11-2014 को लिए गए। इसी तरह से आई0पी0एच0 का एन0ओ0सी0 हमें दिनांक 31-1-2015 को प्राप्त हुआ। हमें साइंस एण्ड टैक्नोलोजी डिपार्टमैंट का एन0ओ0सी0 हमें नहीं मिला था लेकिन अब इसी सप्ताह साइंस एण्ड टैक्नोलोजी डिपार्टमैंट ने भी एन0ओ0सी0 दे दिया है। अब इसकी यूजर एजैंसी उद्योग विभाग होगा। अब इसके बाद भी यह केस मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरनमैंट एण्ड फॉरेस्ट को जाएगा। पहले तो ऐसा था कि इसकी यूजर एजैंसी चेंज होनी थी क्योंकि उनके रिकॉर्ड में साइंस एण्ड टैक्नोलोजी डिपार्टमैंट यूजर एजैंसी थी और जब आपके मत्रि-मण्डल ने फैसला कर दिया कि इसको उद्योग विभाग करेगा तो यूजर एजैंसी बदल गई। हमने उनसे यह मसला उठाया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब उद्योग विभाग ही हमारे पास आए। क्योंकि अब साइंस एण्ड टैक्नोलोजी डिपार्टमैंट का अंतिम एन0ओ0सी0 हमें मिला है इसलिए अब हम इसको आगे भेजेंगे।

17/03/2016/1130/MS/DC/2

मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरनमैंट एण्ड फॉरेस्ट को तो यह केस जाना ही है। वहां पर अट्रैक्ट होता है-(व्यवधान)- यह आपकी सूचना अलग है लेकिन वहां पर यह केस जाएगा और वे इसको डिसाइड करेंगे। जहां तक इसके आगे का सवाल है। -(व्यवधान)-ऐसा नहीं है। यह तो आपकी सोच है। आप विपक्ष में बैठे हैं इसलिए जैसा मर्जी सोचते रहें। हंस राज जी इससे आपका तो कन्सर्न भी नहीं है। यह पर्टिकुलर चुनाव क्षेत्र का सवाल है।

अध्यक्षः कृपया बीच में व्यवधान मत डालिए।

उद्योग मंत्रीः बायो टैक्नोलोजी पार्क के लिए आपके समय में भी प्रयास हए हैं लेकिन कोई कम्पनी सामने नहीं आई। अब हम भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही लैण्ड का केस सोल्व हो जाएगा और केन्द्र सरकार उसको कर देगी तो फिर अगर कोई बायो टैक्नोलोजी पार्क के लिए आगे आ गया तो हम उनको दे देंगे, नहीं तो फिर इसको इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए इस्तेमाल करेंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह केस एफ0सी0ए0 के लिए भेज दिया है या कब भेजेंगे?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष जी, अभी कल-परसों ही साइंस एण्ड टैक्नोलोजी डिपार्टमैंट का एन0ओ0सी0 आया है।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः आपने इसमें दो-तीन साल लगा दिए हैं।

उद्योग मंत्रीः हमने थोड़े न लगाए हैं। ऐसा नहीं है। जब से यह केस चल रहा है, आपकी सरकार भी चार साल रही तो तब यह बन जाता। एक तो हम प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से आप दोषा-रोपण कर रहे हैं। यह राजनीति का विषय नहीं है। आपका एक-एक एन0ओ0सी0 हमने खुद प्रोक्योर किया है। आपका कोई सहयोग है? सिर्फ प्रश्न लगाने के सिवाय कोई सहयोग आप कर रहे हैं? लेकिन यह कोई राजनीतिक का विषय नहीं है। यह विकास का सवाल है। हमें फॉरेस्ट क्लीयरैंस लेनी है और उसके लिए आप अपने गुड ऑफिस का भी इस्तेमाल करें। हम केस शीघ्र ही दिल्ली भेज देंगे।

अगला प्रश्न श्री जे0के0 द्वारा---

16.03.2016/1135/जेएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2943

श्री पवन काजलः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि ये जो दो पुलों के प्रश्न वर्ष 2013-14 में लगे थे, एक गग्गल में मांझी पुल और दूसरा मनूनी मटौर में। इनमें से एक पुल का काम तो शुरू हो गया है उसके लिए आपका धन्यवाद। दूसरा पुल जो मटौर में बनना है वहां पर घंटों

ज़ाम लगा रहता है। तीन किलो मीटर एयर पोर्ट है और 12 किलोमीटर वहां से क्रिकेट स्टेडियम है। यह अति महत्वपूर्ण पुल है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी डी0पी0आर0 जब यह डबल लेन बनना था तब भारत सरकार को भेजी थी। भारत सरकार के वहां दो साल तक यह पड़ी रही। अब आपने रिप्लाई दिया है कि यह रोड़ फोर लेन बनना है। फोर लेन बनने के लिए इसकी डी0पी0आर0 भारत सरकार को भेजी जाएगी। मैं इसमें इतना जानना चाहता हूं और आपसे आश्वासन भी चाहता हूं कि यह अति महत्वपूर्ण पुल है इसका जल्दी से जल्दी स्पेशल केस बना करके क्या अगले वित्त वर्ष में इसे शुरू करवाने की कृपा करेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका उत्तर बड़े विस्तृत रूप से यहां पर दिया है। अब जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि सारी की सारी सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और जो दो पुल उसमें आतें हैं उनका भी उसी आकार में निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सड़क भी बनें और उन दो पुलों का निर्माण भी हो।

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि यह जो पुल का मुद्दा पवन काजल जी ने उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुल से कई लोग नीचे गिर चुके हैं। पिछले साल एक व्यक्ति जैसे ही बस निकल रही थी वह थोड़ा सा पीछे निकला, नीचे गिरा और चट्टान पर गिर कर उसकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद पी0डब्ल्यू0डी0 ने इसमें छोटी सी नाममात्र की वॉल लगाई और अब वह वॉल भी गिर चुकी है। मैं यह चाहती हूं

16.03.2016/1135/जेएस/डीसी/2

कि चाहे यह नेशनल हाई वे का पुल है, लेकिन इसमें थोड़ी-बहुत रेलिंग और इसकी रिपेयर की जाए ताकि वहां पर कोई दूसरे व्यक्ति की गिर कर मृत्यु न हो। मेरे ध्यान में लाया गया कि दिव्य हिमाचल में भी इसका एक ऐडिटोरियल छपा है, क्योंकि वहां से गिरने से पिछले साल ही एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके इसमें थोड़ी सी रिपेयर करवा दें जब तक वह पैसा नहीं आ जाता। यहां से गाड़ियां भी गिरती हैं और व्यक्ति भी नीचे गिर जाते हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि अभी पुल बनेंगे और उनकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। मगर फौरी तौर पर अगर किसी पुल में गाड़ी गिरने का खतरा है, जो कि मेरे पास दर्शाया नहीं गया है,**अगर ऐसा है तो उसकी मुरम्मत कर दी जाएगी।**

16.03.2016/1135/जेएस/डीसी/3

प्रश्न संख्याः 2944

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें केवल घोड़े वाले, खच्चर वाले जो रेता-बज़री निकालते हैं उन पर कार्रवाई हुई है। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मामले पकड़े गए उन मामलों को पकड़ने के लिए कौन-कौन अधिकारी अधिकृत थे, जिन्होंने ये मामले पकड़े हैं।

दूसरे, पकड़े गए मामलों में क्या सरकार ने न्यूनतम/अधिकतम जुर्माना राशि तय की है। जुर्माना राशि को तय करने के क्या मापदण्ड हैं?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

17.03.2016/1140/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 2944 क्रमागत

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो एरिया है वह थोड़ा-सा सैंसटिव एरिया है क्योंकि वहां सड़क वगैरह उस तरीके से नहीं है इसलिए लोग घोड़े-खच्चरों से खनन करने की कोशिश करते हैं। अमूमन प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को परेशान न किया जाए। जहां तक कांगड़ा जिला का सवाल है वहां पर 1862 केस खनन के पकड़ में आए और 85 लाख रुपया फाइन किया गया। इसमें से ट्रैक्टर के 1381 केस थे। ट्रक के 388 थे और जे0सी0बी0 का एक केस था। स्टोन क्रशर 22 थे और घोड़े-खच्चर वाले जिनके चालान हुए हैं वे 70 केसिज़ थे। अधिकतम केसिज़ तो ट्रक और ट्रैक्टर के थे। इसमें जहां तक जुर्माने का सवाल है अब ट्रैक्टर के लिए 4500 रुपया, ट्रक-टिप्पर के लिए 7 हजार रुपया, 10 मीट्रिक टन के ट्रक के लिए 15 हजार रुपया और 10 मीट्रिक से ज्यादा के लिए

25 हजार रुपया का प्रावधान जुर्माने के तौर पर किया गया है। अगर कोई इल्लीगल तौर पर काम करेगा तो एक साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया बहुली कोठी का और जवाब मिल रहा है कांगड़ा का। बहुली कोठी जगह जो है वहां पर सड़क है और वहां पर खनन जे0सी0बी0 के माध्यम से हो रहा है तथा जुर्माना खच्चर-घोड़े वालों का करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो छोटे-छोटे घोड़े-खच्चर वाले हैं ये तो पेट भरने के लिए गुज़ारा करते हैं और जो जे0सी0बी0 से माल निकालते हैं उन्होंने तो हमारी कुहलों के हैड का भी बेड़ागर्क कर दिया। पीने के पानी के स्त्रोत खत्म हो रहे हैं। क्या सरकार उनके खिलाफ कोई शिकंजा सकेगी?

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकंजा तो ऑलरेडी कसा हुआ है। प्रदेश में 11 करोड़ 40 लाख रुपया जुर्माना हो चुका है। अब पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने फैसला किया है कि माइनिंग के लिए ऑक्शन का रास्ता अपनाया जाए। तो पूरे प्रदेश में ऑक्शन का फैसला हुआ है। पहले कांगड़ा, सिरमौर और हमीरपुर के माइनिंग प्लान तैयार थे उनको ऑक्शन के लिए लगा दिया गया है। **जहां तक ये अपनी बहुली कोठी की बात करते हैं माननीय सदस्य जो भी हमें साइट बतायेंगे कि यहां पर प्रॉब्लम आ रही है तो हम वहां पर अपने ऑफिसर को भेजकर जैसे भी ये कहेंगे हम ऐक्शन करवा देंगे।** घोड़ों के लिए हम

17.03.2016/1140/SS-AG/2

लगातार कह रहे हैं कि लिबरल रहें जोकि अपने मकानों के लिए खनन करते हैं। लेकिन अधिकारिक तौर पर हम यह घोषणा नहीं कर सकते कि किसी भी गैर-कानूनी काम को कहें कि हम होने दें। हमने वैसे अधिकारियों को कह रखा है कि घोड़े और खच्चर वालों के प्रति नरम रवैया अपना कर रखें। **मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से वाकिफ़ हूं और इस प्रश्न काल के बाद जो भी ये कहेंगे मैं उसके लिए निर्देश दे दूंगा।**

श्री रिखी राम कौंडलः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से अभी उत्तर दिया कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि सारे प्रदेश के अंदर सारी जगह ऑक्शन करेंगे। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिला बिलासपुर उस ऑक्शन में आयेगा या नहीं आयेगा?

मुख्य मंत्रीः वह भी हिमाचल का ही हिस्सा है।

श्री रिखी राम कौंडलः सारे हिमाचल का हिस्सा तो है लेकिन every land is notified as forestland in Bilaspur. हर एक इंच जगह फॉरैस्ट लैंड नोटिफाइड है।

मुख्य मंत्रीः उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि सारे हिमाचल में ये माइन्ज़ ऑक्शन होंगी तो निश्चित है कि बिलासपुर में भी होंगी। --(व्यवधान)--

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में फॉरैस्ट एंटरी है। क्या आप उसको रिलैक्स करेंगे? बाकी हर जगह ऑक्शन होती है लेकिन पहले बिलासपुर में क्यों नहीं हो रही है?

अध्यक्षः कौंडल जी, आप बैठिये। This question doesn't pertain to Bilaspur. This question pertains to Paprola. This is not a relevant question. This is not a question.

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूरे प्रदेश का उत्तर दिया है। उसमें यह सप्लीमैंटरी राइज़ होती है।

Speaker: No, no. I have to work according to the question. . . . (Interruption) . . . This information pertains to Paprola (Baijnath) only.

उद्योग मंत्री जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1145/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2944 जारी-----

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिलासपुर का सवाल है, वहां पर भी हम प्लेसिज़ आईडैंटिफाई कर रहे हैं और उसमें पूर्व निर्धारित शर्त होगी कि अगर भारत सरकार का फोरैस्ट डिपार्टमैंट उसके लिए स्वीकृति दे देगा तो उन साईट्स को भी हम ऑक्शन पर लगा देंगें।

17.03.2016/1145/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 2945

डॉ0 राजीव सैजलः माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मुख्य मंत्री जी से बहुत गिला है कि वर्ष 2012 में माननीय धूमल जी ने जो कॉलेज हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया था, 2013 में जब आपकी सरकार आ गई तो आपने उसको बन्द कर दिया । जब हमने इसका कारण इस माननीय सदन में जानना चाहा तो आपने कहा था कि यह कॉलेज तीन कमरों में चला हुआ है, बिल्डिंग का प्रावधान नहीं किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दोबारा फिर से उन्हीं तीन कमरों में कॉलेज क्यों शुरू किया गया जबकि आपने कहा था कि तीन कमरों में कॉलेज नहीं चल सकता इसलिए इसको बन्द किया गया है? दूसरे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए भारत सरकार को केस भेजने में इतना विलम्ब क्यों हो गया? 10 मार्च, 2016 को आपने भारत सरकार की वैबसाइट पर फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए इसको अपलोड कर दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करेगी कि यह फोरैस्ट क्लीयरैंस जल्दी आ जाए और इस कॉलेज का भवन निर्माण जल्दी हो जाए?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है और फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए इस मामले को देहरादून भेजा गया है। वहां पर इसको परस्यू कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही वहां से उसकी फोरैस्ट क्लीयरैंस हमें प्राप्त होगी और उसके बाद वहां पर भवन निर्माण होगा। वैसे इस कॉलेज के भवन निर्माण के लिए सरकार ने पांच करोड़ रु0 आवंटित कर दिए हैं और जेसे ही फोरैस्ट क्लीयरैंस आएगी उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा

17.03.2016/1145/केएस/एजी/3

प्रश्न संख्या : 2946

श्री बलदेव सिंह तोमरः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जवाब में कहा गया है कि तीन साल में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, शिलाई में सात कूहलें स्वीकृत हुईं जिनमें से चार कूहलों का निर्माण हो चुका है और तीन कूहलों का कार्य अभी प्रगति पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 की बहाव सिंचाई योजना ओकल क्यार, ग्राम पंचायत, शिलाई पिछले दो साल से बन रही है, यह कब तक बन कर तैयार होगी? दूसरे, बहाव सिंचाई योजना डिम्टी जिसका कि ऐस्टिमेट पिछले तीन-चार साल से विभाग के पास लम्बित है और बहाव सिंचाई योजना भुगियाड़ी, इनके लिए कब तक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ओकल क्यार बहाव सिंचाई योजना ग्राम पंचायत शिलाई जो है, इस कूहल का ऐस्टिमेट 9 लाख 28 हजार का है और 8 लाख 27 हजार रुपया खर्च किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। यह कार्य दो-तीन महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा।

श्री बलदेव सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी जानना चाहा था कि बहाव सिंचाई योजना डिम्टी और बहाव सिंचाई योजना भुगियाड़ी का ऐस्टिमेट पिछले चार साल से आपके विभाग के पास है, अभी तक राशि स्वीकृत नहीं हुई है। इनको कब तक राशि स्वीकृत की जाएगी?

मंत्री जी, अ0व0 की बारी में-

17.3.2016/1150/av/as/1

प्रश्न संख्या : 2946--------- क्रमागत

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहाव सिंचाई योजना डिम्टी वर्ष 2015-16 में सैंक्शन कर दी गई है।

17.3.2016/1150/av/as/2

प्रश्न संख्या : 2947

श्री राम कुमार :अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 54 शेष विचाराधीन मामले हैं इनको कितने समय में निपटा लिया जायेगा? इसके अतिरिक्त, क्या माननीय मंत्री जी निपटाये गये 122 मामलों की कॉपी मुझे उपलब्ध करवायेंगे?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रम एवं रोजगार विभाग का सवाल है यह केवल दोनों पक्षों की सहमति और मध्यस्थता का काम करता है। मालिकों और मज़दूरों में जो डिसप्यूट हो जाता है विभाग उसमें मध्यस्थता करके मामले को हल करने का प्रयास करता है। बाकी मामले हम लेबर कोर्ट को भेज देते हैं। प्रीजाइडिंग ऑफिसर, लेबर कोर्ट धर्मशाला और शिमला में है। प्रदेश के आठ जिले धर्मशाला के अंडर है और चार जिले शिमला के अंडर है। जहां तक मामलों का सवाल है तो हमने 25 मामले कोर्ट को भेजे हुए हैं और दूसरे में भी मामले भेजे हुए हैं। जो मामले विभाग ने सैटल करवाये हैं उसकी सूची तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे मगर जो लेबर कोर्ट ने फैसले किए हैं या वहां पर लम्बित हैं; वह तो अदालती मसला है। इसलिए विभाग की मध्यस्थता से जो सॉल्व करवाये गये हैं हम आपको केवल उसकी सूची उपलब्ध करवा सकते हैं।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये जो 54 मामले लम्बित हैं वह कितने समय में निपटा दिए जायेंगे?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो विभागीय होगा उसमें तो हम मध्यस्थता करवाते हैं। अगर मध्यस्थता से हल नहीं होगा तो उसको हम लेबर कोर्ट को भेज देंगे और उसके लिए मैं कोई समयावधि निर्धारित नहीं कर सकता।

17.3.2016/1150/av/as/3

प्रश्न संख्या : 2948

श्री गोविन्द राम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें प्रश्न के 'ख' भाग में सायरीघाट-नेरी सड़क की मैटलिंग-टारिंग के बारे में लिखा है जी, हां। प्रश्न के 'ग' भाग में कहा है कि जो 200 मीटर सड़क की मैटलिंग/टारिंग होनी थी उसमें स्थानीय लोगों ने कलवर्ट लगाने के लिए एन0ओ0सी0 नहीं दिया। एन0ओ0सी0 तो उस वक्त दिए जाते हैं जब सड़क बनती है और पहले ही एन0ओ0सी0 दे दिए हैं। इस दो सौ मीटर सड़क के पक्की न होने के पीछे क्या कारण है? फिर विभाग ने यह कहा कि कलवर्ट लगाने के लिए एन0ओ0सी0 नहीं मिला तो कलवर्ट तो केवल दस मीटर की जगह पर लगना है और बाकी सड़क पक्की हो सकती थी। मुझे लगता है कि जो सूचना विभाग से आई है वह ठीक नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से इस बारे में आश्वासन चाहता हूं कि यह दो सौ मीटर सड़क कब तक पक्की कर दी जायेगी?

टीसीद्वारा जारी

17.03.2016/1155/TCV/AS/1

प्रश्न संख्याः 2948-- क्रमागत

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में विस्तृत उत्तर देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य को वस्तुस्थिति पता चल सके Mr. Speaker, Sir, the metalling and tarring work of Syrighat-Neri road has been completed by contractor on 4.4.2013 except 200 meter portion of road located in built-up area of Village Bakeshu. There are reverse slopes on both sides of the road and water gets stagnated on the road due to non-allowing of construction of pipe culvert at this point by the owners of land. As and when owners of the land agree to allow construction of culvert the 200 meter left out kaccha Road shall also be made pucca by PWD. मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य वहां पर जो संबंधित किसान है, उनसे बातचीत करके इस कलवर्ट को बनाने के लिए जो भूमि चाहिए उसको उपलब्ध करवाएं। यदि वह इसके लिए कम्पंसेशन मांगते हैं तो वह भी हम देने के लिए तैयार है। लेकिन बिना इस कलवर्ट को बनाए यह सड़क मैटल नहीं की जा सकती है।

17.03.2016/1155/TCV/AS/2

प्रश्न संख्याः 2949

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सभापटल पर रखी है इसके मुताबिक चम्बा में जो सीमेंट प्लांट लगना था उसका समझौता 2007 में श्रीयुत जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 के साथ हुआ था और 2014 में यह समझौता रद्द कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो नया नियम है उसके मुताबिक अब यह मामला सरकार के विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या यह सत्य है कि श्रीयुत जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 हाईकोर्ट में गए हैं और अगर गये हैं तो क्या हाईकोर्ट से इनको कोई स्टे प्राप्त हैं? अगर नहीं है तो इस समझौते को निरस्त किए हुए 2 साल का समय निकल चुका है और 2 साल में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक यह ग्लोबल टैण्डर होगा और ग्लोबल टैण्डर करने में ही 2 साल और लग जाएंगे।

उद्योग मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बा के सभी माननीय विधायकों के हाथ इस सदन के अन्दर उठ रहे हैं और इसलिए मैं इस बारे में सरकार की ओर से यह बताना चाहता हूं कि 2007 में यह कारखाना जे0पी0 इंडस्ट्रीज़ को मिला था क्योंकि MOU के मुताबिक काम नहीं हुआ और 2014 में राज्य मंत्रिमंडल ने इसको रद्द कर दिया। हमने नई एप्लीकेशन्ज इन्वाइट कर ली थी और उसमें 8 कम्पनीज़ ने पार्टीस्पेट किया था। हम इसकी फाईनल स्टेज पर थे। इन-दा -मैन टाईम केन्द्र सरकार ने कानून में परिवर्तन कर दिया। केन्द्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब एप्लीकेशन्ज़ पर कोई भी कारखाना नहीं दिया जाएगा जो पास्ट प्रैक्टिस रही है और अब ऑक्शन होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें चम्बा में सीमेंट कारखाना लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए श्री शांता कुमार जी ने भी आग्रह किया है। हमारे चुराह के जो माननीय विधायक है, जहां यह कारखाना लगना है ये भी आग्रह कर रहे हैं। माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि श्रीयुत जय प्रकाश एसोसिएट्स लि0 कोर्ट में गई थी। आज ही हमें सूचना मिली है कि वह कोर्ट से इस केस को विड्रा कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई स्टे नहीं था लेकिन हाल ही में ऑक्शन का प्रोसीजर आया है और हम इसको ऑक्शन करने जा रहे हैं।

प्रश्नकाल समाप्त

श्री आर0के0एस0 --द्वारा जारी

17.03.2016/1200/RKS/DC/1

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति, सदन में उपस्थापित करता हूं तथा सभा पटल पर भी रखता हूंः-

i. समिति का 133वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 134वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्बन्धित है ।

17.03.2016/1200/RKS/DC/2

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 56वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्याः 4) के पैरा संख्याः4.6 की संवीक्षा पर आधारित है तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सभा पटल पर भी रखती हूं।

17.03.2016/1200/RKS/DC/3

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 8वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं तथा सभा पटल पर भी रखता हूं।

17.03.2016/1200/RKS/DC/4

<u>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री द्वारा स्पष्टीकरण</u>

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अपना स्पष्टीकरण देंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16 मार्च, 2016 को बजट अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कर्नल इन्द्र सिंह ठाकुर, माननीय विधायक जी ने कहा कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के संदर्भ में हाल ही में भारत में एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि हिमाचल पद्रेश में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के सबसे ज्यादा पद खाली है। जिसकी प्रतिशतता 57 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी यह प्रतिशतता 40 प्रतिशत है। यह चिन्ता का विषय है। अतः माननीय विधायक ने चिन्ता व्यक्त करते हुए तुरन्त सुधार करने

का सुझाव दिया। I need to clarify. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशालय महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत 78 बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के 808 पद स्वीकृत हैं। 1 जनवरी, 2013 को विभाग में सुपरवाइजरों के 344 पद भरे थे। मई, 2013 में 16 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई। वर्ष 2015 में 87 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक पद पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी गई है। जनवरी, 2016 में 88 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनका हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा एल.डी.आर. भर्ती से चयन किया गया है को पर्यवेक्षकों के पदों पर नियुक्ति दी गई है। पर्यवेक्षकों के 74 पदों बारे हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से रिक्मेंडेशन के आधार तथा खेल कोटा से भरने की प्रक्रिया भी एक सप्ताह के भीतर पूर्ण हो जाएगी अतः 31 मार्च, तक पर्यवेक्षकों के 569 पद भर दिए जाएंगे। जोकि कुल स्वीकृत पदों का 78.24 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षकों के 159 अतिरिक्त पदों को भरने हेतु प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी गई है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के 30 पदों को भरने हेतु मांग पत्र भूतपूर्व सैनिक कक्ष हमीरपुर को भेजा गया है तथा न्यायालय में लम्बित याचिकाओं के कारण ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। जिस बारे में विभागीय स्तर पर प्रयास जारी है। कुछ रिक्तियां पदोन्नति व सेवानिवृत्ति से उत्पन्न हुई हैं। उन्हें भी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं। सरकार द्वारा 4 मई, 2013 को पर्यवेक्षकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित किए गए हैं जिनमें निम्न प्रावधान किए गए हैं। 30 प्रतिशत सीधी भर्ति द्वारा, 40 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बालबाड़ी कार्यकर्ताओं, बालबाड़ी अध्यापकों , बाल सेविकाओं,

17.03.2016/1200/RKS/DC/5

प्राधानाचार्यों, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र, माध्यमिक स्तर केंद्र की महिला, सामाजिक अनुदेशकों में से सीमित सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जिनके पास मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा बोर्ड संस्था से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने सहित 10 वर्ष का अनुभव हो।

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी...

17.03.2016/1205/SLS-DC-1

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ...जारी

20 प्रतिशत् आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से, जिनके पास मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड संस्था से 10वीं की परीक्षा उतीर्ण करने सहित उनकी वरिष्ठता के आधार पर किसी प्रतियोगिता एवं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार संचालित किए बिना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो और 10 प्रतिशत् आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से, जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने की डिग्री सहित उनकी वरिष्ठता के आधार पर किसी प्रतियोगिता और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार संचालित किए बिना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 15 वर्ष का अनुभव हो।

धन्यवाद।

17.03.2016/1205/SLS-DC-2

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः सुरेश भारद्वाज जी, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार के और सदन के ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी ने मैरिटोरियस स्टुडैंट्स को 10,000 लैप टॉप देने का एक निर्णय लिया है। उस निर्णय के मुताबिक लैप टॉप खरीदने की प्रक्रिया एच.पी. स्टेट इलैक्ट्रौनिक्स कार्पोरेशन को दी गई है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : यह विषय अभी नहीं उठाया जा सकता।

श्री सुरेश भारद्वाज : सर, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसमें निर्णय की तारीख है और इसमें करोड़ों, अरबों रुपयों का मसला है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण है और आपकी बात ठीक है, but this is not the time to say.

भारद्वाज जी, इस विषय को रखने के लिए समय निर्धारित कर लेंगे। समय निर्धारित कर इसमें चर्चा होनी चाहिए। ऑफ हैंड चर्चा करना ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, 9 अक्तूबर को इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ने इस मामले में प्री-बिड की और 23 तारीख को उसका टैंडर होना था। टैंडर हो गया जो सबको स्वीकार था लेकिन उसको हैल्ड अप कर दिया गया। उसके बाद फरबरी में फिर से टैंडर किया गया जिसमें किसी भी कंपनी ने भाग नहीं लिया। फिर 2 मार्च को फिर से प्री-बिड कर रहे थे जिसकी तारीख 14 मार्च के लिए तय की थी। उसे एक्सटैंड कर आज 17 तारीख के लिए वह रखी गई है। इसमें इन्होंने एक नियम बना दिया है कि 2014 का प्रोसैसर खरीदा जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो टैंडर प्रक्रिया की जा रही है, जब वह पहले हो गई थी तो उसको क्यों निरस्त किया गया और उसको हैल्ड अप क्यों किया गया? जब 10,000 लैप टॉप खरीदे जाने है तो स्टुडैंट्स के लिए 2015 या 2016 के लेटैस्ट मॉडल वह दिए

17.03.2016/1205/SLS-DC-3

जाने चाहिए जबकि आप 2014 के प्रोसैसर दे रहे हैं। कुछ लोगों को फेवर करने के लिए सारी टैंडर प्रक्रिया को समाप्त करके उसमें एकाध कंपनी को रखकर आप उसको लाभ देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए। जो 2014 के प्रोसैसर हैं, उनको खरीदने का क्या कारण है? यह करोड़ो रुपये की डील है। इसलिए केवल कुछ कंपनियों को लाभ देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इस पर आज तुरंत रोक लगा दी जानी चाहिए और 2015 या 2016 के प्रोसैसर ही क्रय किए जाने चाहिए।

मुख्य मंत्री: यह सूचना मुझे माननीय सदस्य के माध्यम से ही मिली है**। मैं इसके ऊपर उचित कार्रवाई करूंगा और संबंधित कार्पोरेशन को बुलाकर उचित आदेश दिए जाएंगे।**

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं। जो बात श्री भारद्वाज जी ने उठाई है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। 2014 का मॉडल क्यों लिया जा रहा है? यह लेटैस्ट मॉडल होना चाहिए। आप हाऊस को ऐश्योर करिये कि आप 2016 के लेटैस्ट मॉडल को लेंगे।

मुख्य मंत्री : मैंने कह तो दिया। I have just come to know about it . I will look into the matter.

17.03.2016/1205/SLS-DC-4

वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों (वार्षिक वित्तीय विवरण) पर चर्चा

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों (वार्षिक वित्तीय विवरण) पर क्रमशः आगे चर्चा प्रारंभ होगी। अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। कल के दिन हम चर्चा नहीं करेंगे बल्कि इस चर्चा पर माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर सुनेंगे। आज बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं और हमारे पास पूरा दिन उपलब्ध है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि 10-12 मिनट से ज्यादा न बोलें ताकि इसी समय में सब बोल सकें। कल भी कुछ मैंबर्ज़ बोलने से रह गए थे जिन्हें आज शामिल किया गया है। यदि आप सब सहयोग देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी।

अब मैं श्री रविन्द्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस चर्चा में भाग लें।

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान, जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 8 मार्च, 2016 को यहां प्रस्तुत किए हैं और जिनके ऊपर पिछले 2-3 दिनों से चर्चा जारी है, मैं भी उसी चर्चा में भाग लेने के लिए शामिल होने के लिए अपने स्थान पर खड़ा हूं।

जारी ...गर्ग जी

17/03/2016/1210/RG/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह ----क्रमागत

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट यहां प्रस्तुत किया है, आपने भी, माननीय सदस्यों ने और सभी ने उसको पढ़ा होगा और देखा होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने अपना 19वां बजट यहां पेश किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी उठकर चले गए। मुझे भी बजट पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते

हुए वर्ष 1992-93 से लगातार 22-23 साल हो गए । यहां पर मूलरूप से मुझे दो मुख्य मंत्रियों वर्तमान मुख्य मंत्री और प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन वर्तमान में इन्होंने इतिहास रचा और सबसे लंबा भाषण और सबसे लंबे समय साढ़े तीन घण्टे तक बजट पढ़ा। इसके लिए सच में वे बधाई के पात्र हैं। इसमें क्या कुछ होना चाहिए, माननीय ठाकुर गुलाब सिंह जी आज किसी कारणवश यहां नहीं हैं, उन्होंने चर्चा में भाग लेते हुए कहा था। मैं भी दो दिन पहले इसको देख रहा था। आदरणीय प्रो. धूमल जी ने बतौर मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री दिनांक 16 मार्च, 2012 को जो बजट यहां इन्होंने प्रस्तुत किया था, उसको और वर्तमान बजट को यदि आप देखेंगे, तो न तो पृष्ठों में कोई कमी है और न ही योजनाओं में कोई कमी है। जैसे-जैसे इन योजनाओं के नाम बदलकर या केन्द्र ने जो प्रधानमंत्री के नाम से योजनाएं यहां दी हैं उनको यहां अपना नाम देकर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश को देने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करुंगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पीछे प्रस्तुत किए गए, उनके ऊपर कुछ कहूं। केन्द्र में पिछले दो वर्षों से जो हमारी सरकार है, अधिकारियों ने जिस ढंग से उसके ऊपर एक नकारात्मक रवैया अख्तियार किया है यह दुःख का विषय है कि उस पर जो टिप्पणी आई, तो इस बजट भाषण में आई ही, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में भी आपने दो साल से पहले भी यू.पी.ए. सरकार के समय में हमारी औसतन विकास दर क्या रही, उस पर भी प्रकाश डाला होता, तो शायद अच्छा होता। मुझे लगता है कि इस माननीय सदन के सदस्य भी और प्रदेश की जनता भी उसमें जाना चाहती है। लेकिन फिर भी मैं निश्चित तौर पर यहां कहना चाहूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ नं.-14 पर जो आपने औसतन विकास दर प्रतिशत दर्शाया है आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी भी वित्त

17/03/2016/1210/RG/AG/2

मामलों से जुड़े रहे, निश्चित तौर पर उन्होंने भी काम किया होगा। लेकिन उस समय राष्ट्रीय स्तर पर औसतन विकास दर 8% थी, तो प्रदेश में भी धूमल जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं थी और विकास दर 8% ही यहां भी रही है। यदि आप इससे और आगे चलेंगे, तो जैसा मैंने जिक्र किया कि आपने दो सालों का आंकड़ा लिया। जैसे ही वर्ष 2012 में सरकार बदली और प्रदेश की बागडोर श्री वीरभद्र सिंह जी के हाथ में आई और राष्ट्रीय स्तर पर यू.पी.ए. की सरकार में एकदम से डॉऊन-फॉल आया, औसतन विकास दर कम रहकर

राष्ट्रीय स्तर पर 5.6% रह गई, तो प्रदेश में भी इस सरकार के आने के उपरांत वह 6.4% रह गई। वर्ष 2013-14 में भी यू.पी.ए. की सरकार थी। थोड़ा सा उन्होंने काम किया, तो औसतन विकास दर राष्ट्रीय स्तर पर 6.6% और प्रदेश स्तर पर 7.1% रही। लेकिन उसके बाद जब केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार आई, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और श्री अरूण जेटली जी वित्त मंत्री बने, तो देखिए आप जहां राष्ट्रीय स्तर पर, अधिकारियों ने जो यहां दो सालों का मेन्शन किया कि 'केन्द्र की सरकार के कारण पूरे देश का माहौल आर्थिक तौर पर बिगड़ा।' यदि आपने यू.पी.ए. सरकार के जो दो वर्ष बीच के रहे, वे भी दर्शाए होते, तो बहुत अच्छा रहता। आज वर्तमान में वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर 7.7% है, तो प्रदेश की 7.5% है। वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर 7.6%, तो यहां 7.7% है। इसमें यदि आप कहें कि आपने बहुत छलांग लगा दी, तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसी के साथ आपने इस सर्वेक्षण में जो बातें कही हैं,

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1215/MS/DC/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी-------

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो हैरानी होती है जो आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ संख्या-6 में इन्होंने कहा है कि मुख्य उपलब्धियां; सामाजिक, आर्थिक और पुनरूत्थान के ऊपर, अध्यक्ष जी, यह विषय आपसे संबंधित है इसलिए कृपया इधर भी नज़र रखिए। इसमें लिखा है कि चाय के लिए उत्थान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के चाय उत्पादकों को कृषि लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से तो अनुरोध है ही लेकिन आपसे भी अनुरोध है कि इस प्रदेश में अनुसूचित जाति के कितने प्रतिशत चाय उत्पादक हैं जिनको यह 50 प्रतिशत अनुदान देने की बात यहां कही गई है? केवल-मात्र एक कागज बनाकर यहां लिख देना कि हम उन उत्पादकों को उपदान देंगे जबकि ऐसे उत्पादक प्रदेश में है ही नहीं और यदि होंगे भी तो एक-दो या चार प्रतिशत होंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। इसको किसलिए एड किया गया? इसके कारण कहां किसको लाभ मिला, कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का जवाब देते हुए इसके बारे में भी बताएं।

इस तरह से यहां कहा गया कि मुंबई, बेगलुरू, अहमदाबाद और नई दिल्ली में निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए। सदन से उद्योग मंत्री जी भी चले गए हैं और साथ में मुख्य मंत्री जी भी चले गए हैं। क्या ये बताएंगे कि इसमें कितनी बड़ी उपलब्धि इनकी रही है? ये बार-बार कह रहे थे कि लगभग 4 हजार 71 करोड़ रुपये से ऊपर यहां निवेश होगा और लाखों लोगों को यहां रोज़गार मिलेगा। इस मान्य सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया है यदि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही यहां कहा है कि "स्वच्छ भारत अभियान योजना" को प्रदेश के 12 जिलों में लागू कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, सरकार इसके ऊपर चिन्तन करे। "स्वच्छ भारत अभियान योजना" जब लागू नहीं हुई थी तो प्रदेश की जनता जानती है। मैं धूमल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने प्रदेश में यह योजना लागू की थी कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई प्लास्टिक या पॉलीथीन का लिफाफा नज़र नहीं आएगा और जहां सारा प्रदेश प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त बना वहीं पर एक अधिकारियों की टीम उप-मण्डल स्तर पर निरीक्षण के लिए जाती थी और एस0डी0एम0 उनको देखते थे। पूरे प्रदेश में उस वक्त कहीं भी गन्दगी का नामो-निशान नहीं मिलता था। वर्तमान में तो आपको इसके लिए पैसा भारत सरकार दे रही है। अध्यक्ष जी, अब यदि आप यहां से पालमपुर तक जाएंगे तो हर पुल की बगल में आप खड़े हो जाएं,

17/03/2016/1215/MS/DC/2

आपको वहां गन्दगी के ढेरों का आलम देखने को मिलेगा। शिमला में क्या हाल है इसके लिए माल रोड देखने की आवश्यकता नहीं है। माल रोड से नीचे आप राम नगर की तरफ जाइए या इनके अगल-बगल की बस्तियों में जाइए। हमारी यहां पर जो अन्य बस्तियां हैं उनमें आज के दिन में जाने की आवश्यकता है।

इसी तरह से "मातृ शक्ति बीमा योजना" जिसमें 10 साल से 75 साल तक की महिलाओं का बीमा होगा परन्तु यह योजना तो धूमल जी की दी हुई है। प्रदेश के सारे बी0पी0ए0 परिवार आज तो बढ़ गए होंगे लेकिन उस समय 2 लाख 98 हजार ऐसे परिवार थे, जब उन सारी महिलाओं का बीमा करवाया गया था। यदि अकस्मात कोई घटना घटती थी तो पहले 25 हजार रुपये, फिर 50 हजार रुपये और फिर एक लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते थे।

इसी तरह से शिक्षा के ऊपर बड़ा-भारी कहा गया। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इसके ऊपर काफी प्रकाश डाला है। लेकिन अध्यक्ष जी, वस्तुस्थिति क्या है? आज हमारा विद्यार्थी, हमारा छात्र और हमारा बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है आज के दिन में वह कहीं भी कम्पीटीशन के काबिल नहीं है। जैसे कल माननीय इन्द्र सिंह जी ने बड़ी डिटेल में स्कूलों के खोलने के बारे में बताया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि आज पूरे प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है। हमारी सरकार के समय में जो योजना बनती थी या भारत सरकार की जो गाइड-लाइन्ज बनती थीं, हम उनको इम्पलीमैंट करते थे लेकिन वर्तमान सरकार क्या करती है? यहां पर सारी की सारी जानकारी दी हुई है कि कई स्कूलों में विद्यार्थी ही नहीं है और कई स्कूल खाली हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण में सारे-का-सारा डाटा दिया हुआ है मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां पर बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं इसमें निश्चित तौर पर एक बात जो सामने आई है, मैं उस पर मान्य सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में कहा की बढ़ी है। वह निश्चित तौर पर बढ़ी है। उसमें 1 लाख 30 हजार 67 रुपये आंकी गई है जो इस साल होने वाली है। अध्यक्ष जी, इसके ऊपर हमें आकलन करना चाहिए कि प्रदेश में बी0पी0एल0 फैमिलीज कितनी है। मैं यहां सारी डिटेल लेकर आया हूं। आज के दिन में "राष्ट्रीय सुरक्षा पैंशन योजना" के अंतर्गत 3 लाख 39 हजार 921 व्यक्तियों को हम सामाजिक सुरक्षा पैंशन दे रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1220/जेएस/एएस/1

श्री रविन्द्र सिंहः-----**जारी**-----

आपने प्रश्न के ज़वाब में कहा और महामहिम् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी आया है। साथ में 41,319 लम्बित मामलें आज के दिन में भी पड़े हैं। यदि कुल मिलाएंगे तो ये लगभग 3,81,240 व्यक्ति बनते हैं। ये 3,81,240 व्यक्ति मतलब परिवार है। हमारे 17 या साढ़े 17 हजार परिवार हैं। प्रति व्यक्ति आय हमारी 1,30,200/-रूपए के करीब है। अगर इन परिवारों को आप निकाल देंगे तो यह परिवार कहां बैठते हैं, हमारे प्रदेश की स्थिति आर्थिक तौर पर क्या है उसके बारे में आकलन करने वाली बात है? कोई उद्योगपति आता

है तो उसकी तो करोड़ों में इन्कम है। आप अगर एवरेज़ निकालेंगे और जो एवरेज़ आपने निकाल दी है, लगभग 4 लाख परिवार हमारे हो गए हैं, उनकी वस्तुस्थिति क्या है? इसके ऊपर भी चिन्तन करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि इसमें दो-तीन प्राथमिक क्षेत्र जिन्हें सर्वेक्षण वाईज़ दिखाया गया है, पृष्ठ-12 पर उसमें आपने कहा है कि प्रदेश में हमारी जो औसतन आय की जाती है उसमें विभिन्न विभाग या कार्यक्षेत्रों में काम किया जाता है, उसमें दर्शाया गया है। पिछले साल के मुकाबले में आपने निश्चित तौर पर इसमें देखा होगा हालांकि इसमें बेरोज़गारों का आंकड़ा काफी निराश करने वाला है, राज्य में दिसम्बर, 2015 तक 8 लाख 8 हजार 767 पंजीकृत बेरोज़गार है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवैल्पमैंट से ताल्लुक रखने वाले निर्माण क्षेत्र में भी कोई खास बढ़ौत्तरी नहीं हो पाई है। यह आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015-16 में भले ही खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में 5.6 प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन फल उत्पादन में कमी भी आंकी गई है, जिसको कि हम प्राथमिकता के ऊपर लेते हैं और उसमें कमी आंकी गई है। इसके साथ जो अन्य प्राथमिक क्षेत्र हमारे हैं उनमें जैसे कृषि, पशु-पालन,वन, मत्स्य और खनन शामिल हैं। इसमें बीते वर्ष में 1.7 प्रतिशत की कमी पाई गई है। यह रिपोर्ट कह रही है और यह इस रिपोर्ट में दर्ज़ है। हम अपने आर्थिक स्तर पर किस ओर जा रहे हैं यह आज चिन्तन का विषय है। इसी के साथ इसमें आप देखेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रदेश को कुदरत ने बहुत कुछ दिया और शायद ही कोई प्रदेश भले ही पहाड़ी राज्य हो, उनमें यहां की तरह कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि सर्वेक्षण की पृष्ठ संख्या-4 पर जो सारणी है उसमें यहां पर आने वाले पर्यटक लाखों में हैं लेकिन इसमें भी कमी पाई गई है। विदेशी पर्यटक जो वर्ष 2010 में 4 लाख 54 हजार । वर्ष 2011 में 2 लाख 84 हजार हुए। वर्ष

16.03.2016/1220/जेएस/एएस/2

थे 2012 में जब बी0जे0पी0 की सरकार थी और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे उस वक्त उनकी संख्या 5 लाख हुई। वर्ष 2013 में इसमें गिरावट आ गई और 4 लाख 14 हजार विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2014 में 3 लाख 90 हजार आए और इस साल जो कि 31 जनवरी तक का सर्वे होगा उसमें 4 लाख 6 हजार विदेशी पर्यटक आए। यह कमी आने के क्या कारण है इसके ऊपर चिन्तन करने की आवश्यकता है? निश्चित तौर पर माननीय

मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर गौर फरमाएंगें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो बिन्दु यहां पर है मैं उनके ऊपर भी निश्चित तौर पर आना चाहूंगा। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की ओर से केन्द्र सरकार को कहा कि हमें केन्द्र की तरफ से बड़ी सहायता नहीं मिली है। लेकिन मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि केन्द्र में सरकार आने के बाद जब मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने वे सारी कठिनाइयां अपने प्रदेश में स्वयं झेली है। उनको मध्यनज़र रखते हुए क्या यह सही नहीं है कि 14वें वित्तायोग ने जो एन0डी0ए0 सरकार ने जो टोटल टैक्स डीवेल्यूएशन हमारा था 28 हजार 225 करोड़ रूपए वर्ष 2015-2020 के मध्य जो हमें पीछे कम मिला था वर्ष 2010-15 के बीच में 11 करोड़ 131 लाख मिला था यानि बढ़ौत्तरी 17 हजार 94 करोड़ रूपए की, यह नरेन्द्र मोदी जी ने, एन0डी0ए0 की सरकार ने हमें यहां पर उपलब्ध करवाई है। यहां पर दो लाईनों में धन्यवाद करने से बात बनने वाली नहीं है। बार-बार मंच पर आलोचना करना कि केन्द्र की सरकार हमें देख नहीं रही है, योजना आयोग बन्द कर दिया और तीन हजार करोड़ रूपए का नुकसान हो गया, लेकिन जो पैसा नीति आयोग के माध्यम से आ रहा है। जो केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत पैसा दे रही है, उनका जिक्र यहां पर न करना और केवल मात्र डेढ़ लाईन में धन्यवाद कर दिया।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

17.03.2016/1225/SS-AS/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

इसके अतिरिक्त ग्रांट-इन-ऐड 2015-2020 के लिए 43,810/- करोड़ दी गई जोकि 2010-2015 के मुकाबले में 33,356/-करोड़ रुपया ज्यादा है। इसके अतिरिक्त मुझे मालूम हैं क्योंकि मैं भी विभाग के साथ संबंधित रहा हूं कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 25, 30, 35, 40 या 50 परसैंट प्रदेश सरकार का शेयर हुआ करता था। आज आपको यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पास करना चाहिए था जैसे धूमल साहब ने उस समय केन्द्र सरकार का किया था, जब हमें पैकेज मिला था। हमने उस समय केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया था। यहां 90:10 का अनुपात यू0पी0ए0 सरकार ने बंद कर दिया था। उसको फिर बहाल किया। इसके लिए हम केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने 90:10 के अनुपात में

सारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें प्रदेश सरकार को दी हैं। मैं एक बात और यहां रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। मुझे याद है कि जब बाढ़ नियंत्रण का विषय मेरे समक्ष आया, जब वह विभाग मेरे पास था, तो 2008 से पहले बाढ़ नियंत्रण के लिए भारत सरकार से कोई 90:10 के अनुपात में पैसा नहीं आता था। 2008 से पहली बार चाहे वह स्वां नदी का है, चाहे वह छौंच खड्ड का है, चाहे हमारी सीर खड्ड का है या पांवटा साहब की हमारी गिरी नदी का है, पैसा 90:10 अनुपात में आया। आने वाले समय के लिए एक योजनाबद्ध रूप से हमने केन्द्र सरकार को 90:10 अनुपात के लिए मनाया था। सी0डब्ल्यू0सी0 व फ्लड प्रोटैक्शन मैनेजमैंट के समक्ष हमने बात रखी थी और उन्होंने हमारी बात को माना था। आज हमें खुशी है कि 2008 के बाद विभिन्न बाढ़ नियंत्रण के जो प्रोजैक्ट आते हैं वे 90:10 के अनुपात में आने शुरू हुए हैं। यह धूमल जी की देन है। यह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को देन रही है। यह भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, समय का भी ध्यान रखें। आप ऑलरेडी 16 मिनट बोल चुके हैं। अगर आप ज्यादा समय बोलेंगे तो इस तरह से चर्चा में चार दिन लगेंगे। इसलिए कृपया अपनी बात संक्षेप में रखिये।

17.03.2016/1225/SS-AS/2

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, पिछले कल देखेंगे तो कई सदस्य 30-30 और 35-35 मिनट बोले हैं। कई तो 40 मिनट बोले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । इसके साथ ही जो यहां पर बताया गया है, इस प्रदेश का आर्थिक दृश्य बड़ा सोचने वाला है। वैसे यह 19वां बजट पेश हुआ है और 18 बजट इससे पहले पेश हो चुके हैं। लेकिन इस प्रदेश को गर्त में धकेलने वाला कौन है? आशा कुमारी जी, यह चिन्तन करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि आप भी उस समय विधायिका थीं। 1988-89 में अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा, शायद आप भी यहां विधायक या मंत्री होंगे तो उस समय जब 9वां वित्तायोग हिमाचल में आया था तो उस समय कौल सिंह जी भी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे होंगे, आपको याद होगा कि उस समय सारे-के-सारे आंकड़े गलत प्रस्तुत कर दिये थे। मैं बार-बार इस विषय को कहता हूं। उस समय जो 210 करोड़ रुपये का घाटा प्रदेश का था उसे 9वें वित्तायोग के समक्ष गलत प्रस्तुत किया गया। उस समय भी यही मुख्य मंत्री थे, जिनके पास आज वित्त विभाग है। इन्होंने उस 9वें वित्तायोग को खुश

करने के लिए केवलमात्र 10 करोड़ का घाटा बताया और वह जो पांच साल का गैप पड़ा, एक साल में 200 करोड़ का घाटा हुआ यानी कि पांच साल में 1000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। उससे यह सारा गर्त हुआ। लोन लेना और लोन के साथ काम करना उससे स्थिति बिगड़ी है। आज यह जो स्थिति बनी है इसके लिए अगर कोई दोषी हैं तो निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह जी दोषी हैं अन्य कोई मुख्य मंत्री इसके लिए दोषी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पृष्ठ-8 पर 14 नम्बर पैरे में लिखा है कि राज्य पर अत्याधिक कर्ज भार काफी समय से चिन्ता का विषय बना हुआ है। चिन्ता का विषय 1988-89 से हो गया। पिछले साल का बताया है कि 31 मार्च, 2015 को हमारा ऋण बोझ 35151 करोड़ रुपया था। इस साल 9000 करोड़ रुपया सरकार लोन ले चुकी है। 31 मार्च, 2016 को यह ऋण बढ़कर लगभग 44000 करोड़ रुपया हो जायेगा। जब अगला चुनाव 2017 का आयेगा तो यह आंकड़ा 50 हजार करोड़ रुपये से ऊपर चला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे यहां लिखा भी है और कई बड़े अच्छे-अच्छे स्लोगन्ज़ पढ़े हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना है, जैसे इन्होंने अंत में कहा थाः-

"कुछ तुम बदल के देखो कुछ हम बदल के देखें,
जैसे भी हो दिलों के मौसम बदल के देखें।
ये आईने भला क्या बदलेंगे अपनी सूरत,
आओ कि अपनी सूरत खुद हम बदल के देखें।"

17.03.2016/1225/SS-AS/3

मुख्य मंत्री जी ने यह कहा तो जरूर है लेकिन मुख्य मंत्री जी मैं भी यह कहना चाहता हूं, यह गालिब का शेर हैः-

"ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।"

इसलिए मुख्य मंत्री महोदय, आपने आईना ही साफ करने की कोशिश की है। धरातल पर आर्थिक तौर पर प्रदेश को मजबूत करने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाये।

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1230/केएस/डीसी/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी----

हमारे यहां पर बोर्ड और कॉर्पोरेशन लगभग 11 हैं, वे 11 के 11 आजकल घाटे में चले हुए हैं। जिसमें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा घाटा बिजली बोर्ड का है। बिजली बोर्ड का दो हजार करोड़ से ऊपर घाटा हो गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का है, उसके बाद मार्किटिंग बोर्ड का घाटा है और उसके बाद फोरैस्ट का है। ये चार बोर्ड/निगम सबसे ज्यादा घाटे में हैं और पीछे जो अभी हाल ही में केबिनैट मीटिंग हुई, बड़ी हैरानी की बात है कि जब ये 11 बोर्ड/कॉर्पोरेशन्ज़ हमारे घाटे में चल रहे हैं, उनमें करोड़ों का घाटा हो गया, फिर एक और निगम बनाने का प्रस्ताव उस केबिनैट की मीटिंग में पास कर दिया और काम वह क्या करेगी, सरकार अब शराब बेचेगी। शराब बेचने के लिए सरकार ने नया निगम बनाने की केबिनैट में एप्रूवल दे दी। प्रदेश सरकार को हो क्या गया है? क्या करने जा रहे हैं? ये केवल मात्र धंधा करने की कोशिश है, जो हम कहते हैं कि माफिया इस प्रदेश में हावी हो गए हैं। कोई ड्रग माफिया, कोई शराब माफिया, कोई भू-माफिया और एक हिमाचल प्रदेश में आप एक वाईन माफिया नया खड़ा कर देंगें। यहां निगम का कॉर्पोरेशन का आगे ही बोझ पड़ा हुआ है और यह कौन सी योजना आ गई? किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? किस व्यक्ति के साथ तालमेल हो रहा है? ये सारे तथ्य हमारे सामने आएं। यह प्रदेश में चलने वाला नहीं है। यहां प्रदेश के लोग इस विभाग के अंन्तर्गत काम करते है, लोकल लोग काम करते हैं और जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत बड़ा कॉकस जिन्होंने उत्तराखंड हथिया लिया है, जिन्होंने यू.पी. हथिया लिया है, शायद वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके आगे रिश्तेदार होंगे वे काम करने वाले हैं। उनको कॉर्पोरेशन का बोर्ड चेयरमैन बनाकर उनको आगे यह सारा का सारा देने की कोशिश की जा रही है। यह चिन्ता का विषय है और इसके ऊपर निश्चित तौर पर सोचने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि ऐसा कोई कदम उठाने से पहले आपको चिन्ता करनी होगी और चिन्तन भी करना होगा कि हम इस प्रदेश को किस ओर ले जाना

चाहते हैं। सरकार का काम जनता की सेवा करना है , विकास करना है न कि शराब बेचना है। शराब बेचना सरकार बन्द करें, यह मैं कहना चाहता हूं।

17.03.2016/1230/केएस/डीसी/2

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहता हूं जिन्होंने विधायक निधि को 75 लाख रु0 से बढ़ाकर 1 करोड़ रु0 किया है, उसके लिए ये निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिस मन्शा के साथ इस विधायक निधि को धूमल जी ने शुरू किया था आगे बढ़ते-बढ़ते हम एक करोड़ तक पहुंचे हैं। भविष्य में यह और आगे बढ़े और हमारी मांग भी है कि क्योंकि अन्य योजना तो है नहीं इसलिए इसको बढ़ाकर डेढ़ या दो करोड़ रु0 कर देंगें तो हमें काम करने में और आसानी रहेगी। यहां पर ऐच्छिक निधि भी बढ़ाई गई है उसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर अधिकारियों को भी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी कहना चाहता हूं कि तमाम प्रदेश, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से प्रदेश हैं जहां पर उनकी पूंजी अपनी होगी, वहां पर उद्योग लगते हैं, वहां पर काम करने का सिलसिला है । वहां पर एग्रिकल्चर के बड़े-बड़े फार्म हाऊसिज़ हैं। वहां पर काम करने का अन्य से राजस्व प्राप्त होता है लेकिन यहां पर जो स्थिति है, हम सारे के सारे भारत सरकार के ऊपर निर्भर है। आपने देखा होगा कि 100 रु0 में से लगभग 80 रु0 कुछ पैसे हमें भारत सरकार देगी और 19 रु0 कुछ पैसे हम ऋण के तौर पर उगाही करके फिर प्रदेश का विकास करेंगें। उसमें कितनी पैंशन है, वेतन है आदि-आदि केवल मात्र 12 रु0 कुछ पैसे विकास के ऊपर रह जाते हैं। यह सारा चिन्तन करने का विषय है । जो वर्ष 2016-17 का बजट है, मेरा निवेदन रहेगा, यह जो यहां पर कहा गया है उसके ऊपर चिन्तन करें, मुख्य मंत्री महोदय अधिकारियों की डियूटी लगाएं केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए। पैसे की वहां कोई कमी नहीं है। हम कितनी जल्दी अपनी डी.पी.आर. तैयार कर वहां ले जाते हैं? मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय यहां से दो-तीन अधिकारियों की परमानैंट डियूटी दिल्ली में लगाई जाए वे वहां बैठे और वे केवल मात्र इस प्रदेश से जो डी.पी.आर. जाए उसके पीछे वहां बिना किसी भेदभाव के चाहे वह किसी क्षेत्र की डी.पी.आर. हो, देखने में आया है कि हमारी सी.आर.एफ की स्कीमें या जो हमारी अन्य

स्कीमें हैं, उनको वहां पर ठंडे बस्ते में डाला जाता है। मेरा निवेदन रहेगा कि जिसकी डी.पी.आर. बनती है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी

17.3.2016/1235/av/dc/1

श्री रविन्द्र सिंह--------- जारी

उस डी0पी0आर0 को प्राथमिकता के ऊपर करने के लिए अधिकारियों का निर्देश दिए जाएं। विधायकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी इनीशिएटिव लेकर वहां जाएं और अधिकारियों से बात करें ताकि हमें केंद्र की स्कीमों का लाभ मिले। मैं यहां पर मुख्य मुद्दे उठाऊंगा जिसका प्रदेश लाभ ले सकता है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक डाकघर में ए0टी0एम0 की सुविधा उपलब्ध करवा दी है जो कि एक अप्रैल से शुरू हो जायेगी और उसका जनता को लाभ मिलेगा। देहरा में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। हिमाचल में शायद शिमला और देहरा में यह सुविधा शुरू की गई है। कम्पनियों को एक दिन में रजिस्ट्रेशन देने की बात कही है। मेरा उद्योग मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस बारे में इनीशिएटिव लें। प्रदेश में जो एक पुराना ढर्रा चल हुआ है, आप अधिकारियों को इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्य करने के निर्देश दें। आपको जानकारी होगी कि जब पश्चिम बंगाल में नैनो गाड़ी बनाने की प्रपोजल बनी थी तो वहां पर मुख्य मंत्री बनने के बाद श्रीमती ममता बैनर्जी ने ऐजिटेशन किया था। वह ऐजिटेशन बहुत लम्बा चला था और किसी को पता नहीं चला कि नैनो गाड़ी (टाटा) के लिए अब इंडस्ट्री कहां बनेगी। उस समय आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे। उन्होंने यह मामला टाटा कम्पनी से चुपचाप टेकअप किया। उससे पहले टाटा कम्पनी ने गुजरात में काई उद्योग नहीं लगाया था। वहां की सारी-की-सारी बातें और वातावरण देखकर रतन टाटा जी ने मोदी जी को एक महीने का समय दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक महीने के अंदर-अदर जमीन और एन0ओ0सीज0 इत्यादि औपचारिकताएं पूर्ण कर लेंगे तो हम आ जायेंगे। मगर नरेन्द्र मोदी जी ने एक महीने से पहले-पहले केवल 22 दिन में ही नैनो गाड़ी बनाने के लिए टाटा कम्पनी को जमीन दे दी।

आपको भी ऐसा ही इनीशिएटिव लेना होगा। फूड प्रोसैसिंग के लिए सौ प्रतिशत एफ0डी0आई0 के लिए कहा है। इसके लिए आपको अनुमति मिलेगी, आप इसको टेकअप कीजिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तथा अन्य जिनका मैंने जिक्र किया उसके लिए 2 लाख

17.3.2016/1235/av/dc/2

18 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है आप इनको लेकर वहां जाइए। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये ऋण वितरण अगले आने वाले साल के लिए हैं। आपका जो कौशल विकास भत्ता है वह सब इसके अंतर्गत आता है। इस साल में एक लाख करोड़ रुपये दे चुके हैं। सार्वजनिक परिवहन में परमिट की स्थिति खत्म कर रहे हैं। आने वाले साल में जो सार्वजनिक परिवहन होगा उसमें परमिट का कानून सारा खत्म कर दिया जायेगा। वर्ष 2016-17 में बुनियादी ढांचे के लिए वहां पर कुल परिव्यय 2 लाख 21 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अगले साल के लिए नये 'स्टार्ट-अप' के लिए टैक्स में छूट होगी। ग्रामीण विकास के लिए 87765 करोड़ रुपये का आबंटन होगा। मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रुपये का आबंटन होगा। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से यू0सीज0 भेजिए। आपने 740 करोड़ में से केवल 338 करोड़ रुपये व्यय किए थे और यू0सीज0 आप फिर भी नहीं दे पाये। जब तक आप यू0सीज0 नहीं भेजेंगे तब तक आपको मनरेगा में पैसा कैसे मिलेगा? वह एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश की व्यवस्था की है। देश में बीस नये हवाई अड्डे बनेंगे और उसके लिए हमारे प्रदेश में भी चयन किया गया है। उसके अंतर्गत इसको वहां पर टेकअप करना चाहिए। परमिट राज खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जितने परमिट है जैसे हमने जी0एस0टी0 के अंतर्गत कहा कि यहां पर जी0एस0टी0 लागू हो जाए उसके लिए आप भी सिफारिश कीजिए। उसके अंतर्गत प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। आप उस जी0एस0टी0 बिल को पास करवाइए। यहां की सरकार ने अपनी मोहर लगाकर केंद्र सरकार को इसके लिए अपनी परमिशन दी हुई है। आने वाले

एक साल में 10000 किलोमीटर नेशनल हाई-वे बनेंगे। फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का आबंटन होगा। 62 नये नवोदय विद्यालय खोले जायेंगे। आने वाले साल में हर जिला में डायलाइसिज सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी। (---व्यवधान---) जब आप (श्री राजेश धर्माणी जी को कहा।) अपनी पार्टी के पुराने लोगों के नुमाइंदे बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मैं तो आपको योजनाओं के बारे में बता रहा हूं। आप इनमें से जिनका लाभ ले सकते

17.3.2016/1235/av/dc/3

हैं, लीजिए। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं और हम अच्छी बात कर रहे हैं। मैं यहां पर प्रदेश के हित की बात कर रहा हूं कि आप इनको केंद्र से टेकअप कर सकते हैं। गांव में गरीब महिलाओं के लिए एल0पी0जी0 के कनैक्शन दिए जायेंगे। (---व्यवधान---)

Speaker: Hon'ble Member, no more time please. You have already taken 7 minutes extra to speak. Please windup.

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। इसी तरह से, प्रदेश में चाहे हमारे विधान सभा क्षेत्र की बात हो, वहां तो मुख्य मंत्री जी आना भी नहीं चाहते। एक-दो बार प्रोग्राम बनाया भी मगर बाद में वह कैंसिल कर दिए। उसके पीछे क्या कारण रहें वह तो मुख्य मंत्री जी जानते हैं।

टीसी द्वारा जारी

17.03.2016/1240/TCV/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह----- जारी

अन्त में एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि जहां प्रदेश में बड़े-बड़े संस्थान आ रहे हैं वहीं देहरा को भी सैंट्रल युनिवर्सिटी प्राप्त हुई है। मेरा निवेदन रहेगा कि उस केन्द्रीय विश्वविद्यालय जिसके नाम

हमने ज़मीन कर दी है, पर्यावरण की परमिशन भी मिल गई है, माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्र की सरकार को कहे कि जगह हमने चयन कर दी है और जो पत्र उन्होंने 23 जनवरी, 2013 को भारत सरकार को लिखा था उस पर अमलीजामा पहनाएं। ये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बज़ट में केन्द्र की स्कीमों का ही यहां जिक्र किया गया है, क्योंकि इस बज़ट में प्रदेश के किसानों/बेरोजगारों/नौजवानों/मजदूरों और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं हैं। इसलिए मैं इस बज़ट का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

17.03.2016/1240/TCV/AG/2

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपना 19वां बज़ट इस मान्य सदन में पेश किया। आपने चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व श्री रविन्द्र सिंह जी जो मेरे मित्र और बड़े वरिष्ठ सदस्य भी हैं और मंत्री भी रहे हैं तथा एक बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत जोर-शोर से भाषण दे रहे थे। हालांकि इन्होंने अन्त में कहा कि मैं इस बज़ट का समर्थन करने में असमर्थ हूं मगर इनका जो पूरा भाषण था उससे तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस बज़ट के खिलाफ़ कुछ भी बोलने में असमर्थ है। इन्होंने इस बज़ट के बारे में तो चर्चा ही नहीं की। आर्थिक सर्वेक्षण और केन्द्र के बज़ट पर इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखें। माननीय प्रधान मंत्री जो तत्कालीन गुजरात के मुख्य मंत्री थी, उनकी कार्यशैली पर भी अपने विचार रखे। मैं इनका धन्यवाद करती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो एक करोड़ रूपया विधायक निधि के लिए बढ़ाया उसके लिए इन्होंने धन्यवाद किया। अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो विधायकों को 75 लाख से एक करोड़ रूपये हमारे एम0एल0ए0 फण्ड के लिए किया है यह कदम धन्यवाद के योग्य है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि एक करोड़ है या दो करोड़ है, प्रश्न यह है कि एम0एल0एज़0 की मान-सम्मान और इज्जत का प्रश्न होता है। जितना इस सरकार ने विधायकों के मान-सम्मान के लिए कार्य किया है, शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। उसमें माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी का योगदान भी सराहनीय है। इसमें आप लोगों का भी योगदान रहा लेकिन असलियत तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो वित्त मंत्री भी हैं मंजूरी न देते तो आज हर क्षेत्र में विधायकों का जो मान-सम्मान बढ़ा है,वह न बढ़ता। यह तो एक

ऐतिहासिक कदम है। मैं आपको यह कह रही हूं कि विधायक निधि देना अपने आप में एक धन्यवाद योग्य कदम है। मगर जो मान-सम्मान बढ़ाया है उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एम0एल0ए0 फण्ड से निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में कुछ गतिविधियों के लिए पैसा देने में सक्षम रहते हैं।

श्री आर0के0एस0 --- द्वारा जारी

17.03.2016/1245/RKS/AG/1

श्रीमती आशा कुमारी ... जारी

हर यह चाहेगा कि यह निधि बढ़े। मैं यह सोचती थी कि इंटरनैशनल वूमन डे पर जब यह बजट रखा गया है, तो हम इस सदन में तीन ही महिला विधायक हैं और हमें 10% एक्सट्रा बजट मिलना चाहिए। महिलाओं को इनिशिएटिव मिले ताकि और महिलाएं सदन में आ सकें।

अध्यक्षः यह संविधान के विरूद्ध हो जाएगा Equality to all फिर नहीं रहेगी।

Smt. Asha Kumari : Little inequality for women. अध्यक्ष महोदय, जो डिशक्रिशनरी ग्रांट 4 लाख से 5 लाख रुपए बढ़ाई गई है, इससे हमारे चुनाव क्षेत्र के गरीब लोग जो हमारे पास धनराशि के लिए आते रहते हैं, उनको डिस्बर्स करने में हमें फायदा मिलेगा। मुख्य मंत्री महोदय, ने 'खेत संरक्षण योजना' अनाऊंस की है। अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग की मीटिंग में माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी ने यह सजेशन दी थी कि जंगली जानवरों को खेतो में आने से रोकने के लिए एक योजना बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, यह योजना अच्छी है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि इस योजना का कार्यान्वयन किस तरह से होगा? इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? क्या वन विभाग करेगा? क्योंकि जंगली जानवरों को वन विभाग डील करता है। क्या एग्रीकल्चर विभाग करेगा या इसको पंचायती राज विभाग कार्यान्वित करेगा।? खेतों को एग्रीकल्चर विभाग डील करता है। यदि एग्रीकल्चर

विभाग डील करेगा तो एग्रीकल्चर विभाग की 80 % पोस्टें खाली पड़ी हैं। जब कर्मचारी ही नहीं है तो यह सब कैसे होगा? तारों के लिए आप सब्सिडि देंगे। आपने कहा कि तारों में सोलर लाइट, सोलर पैनल या इलैक्ट्रिक से करंट देंगे। यह योजना जहां बहुत महत्वकांक्षी है, वहीं यह खतरनाक भी है। क्योंकि करंट से डॉमैस्टिक कैटल को भी रोकना होगा कि वे तोरों के नजदीक न जाए। जो लोग वहां से आते -जाते हैं उनको आप कैसे रोकेंगे? दूसरी बात यह है कि इसकी कॉस्ट इफैक्टिवनैस क्या है? जो जंगलात विभाग तार लगाता है वह अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि यह

17.03.2016/1245/RKS/AG/2

लोहे की होती है। मेरी इसमें कुछ आब्जर्वेशनज हैं कि आप इसे कैसे कार्यान्वित करेंगे। इस सदन में जंगली जानवरों और बंदरों के बारे में इतनी बार चर्चा हो चुकी है कि मुझे बार-बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। मगर सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा था। इस योजना को हमें देखना चाहिए। पायलट प्रोजैक्ट को हम चालू करें। देखते हैं इसमें हमें कितनी सफलता मिलती है। मगर जो बंदर है, सुअर है, नील गाय है, पॉरक्यूपाइन(सायल) इन सब को वर्मिन डिक्लेयर करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर हमने एग्रीकल्चर सैक्टर को, होर्टीकल्चर सैक्टर को बढ़ावा देना है तो सबसे पहले खेत की रक्षा करना, फसल की रक्षा करना, हमारी नम्बर वन प्रायोरटी होनी चाहिए।

गौसदन की बात पिछले दो साल से हमारे बजट में अपीयर भी हो रही है,

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी

17.03.2016/1250/SLS-AS-1

श्रीमती आशा कुमारी ...जारी

इस बार फिर से उसके ऊपर एम्फैसिज दिया गया है और यह बात रखी गई है कि गौसदन को बढ़ावा देने के लिए टैंपल ट्रस्ट जैसे संस्थानों को पैसा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पैसे का नहीं है बल्कि ज़मीन का है। सरकार इन गौसदनों को खोलने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। क्या जल्दी-से-जल्दी ज़मीन ट्रांसफर करने के लिए आप कोई नीति बनाएंगे? पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना आपकी एक अच्छी योजना है। पंचायतों में पशुधन का पंजीकरण हो, पंचायतें उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करें और उन पर नंबर लगाने का कोई तरीको हो। लेकिन पूर्व में यह प्रयोग भी असफल रहा है। कान में टैग लगाया गया था लेकिन लोगों ने पशु के कान ही काट दिए। आप इसको किस तरह से कार्यान्वित करेंगे; इसको बड़े सीरियसली लेना पड़ेगा। पशु पालन मंत्री जी से मेरा निवेदन है, क्योंकि आप के पास ही पशु पालन तथा पंचायती राज दोनों विभाग हैं, कि पशु का पंजीकरण करना आप ज़रूरी करिए। ऐसी बहुत सारी पंचायतें होंगी जहां लोग अपने पशु को नहीं भी छोड़ते हैं। आप देखते हैं कि शहर के जितना नजदीक आप आते जाते हैं वहां ज्यादा-से-ज्यादा गांए, जो दूध देना छोड़ देती हैं, उनको वहां छोड़ा जाता है। ...(व्यवधान)... दूसरे राज्यों से भी पशु आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि इस बजट में एक बहुत बड़ी और अच्छी उपलब्धि मुख्य मंत्री आवास योजना है। बी.पी.एल. के तहत जितने भी वर्ग हैं इनमें जनरल कैटेगिरीज के लोग अक्सर हमारे पास आते हैं और यह राष्ट्रीय चर्चा का विषय है कि जो गरीब है लेकिन एस.सी. एस.टी. नहीं है is he not entitled to some benefits under these schemes? यह एक बहुत अच्छा इनिशियेटिव है। हमने भी प्लानिंग की बैठक में इसे रेज किया था और बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात रखी थी कि जनरल कैटेगिरी के लिए मुख्य मंत्री अपनी स्टेट से बजट देकर इस काम को करें। यह बहुत ही सराहनीय कदम है जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं।

17.03.2016/1250/SLS-AS-2

कल हमारे बड़े भाई गुलाब सिंह जी कह रहे थे और अभी माननीय रविन्द्र सिंह जी भी कह रहे थे कि यह बजट स्पीच वही है जो माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री धूमल जी ने दी थी। अगर यह वही है तो आप मुझे बताएं कि वह सारी चीजें जो अभी इस बजट में रखी गईं हैं वह उस बजट स्पीच में कहां थीं। यह सब नई स्कीमें हैं। ...(व्यवधान)... बजट साईज भी

डबल हो गया है। लेकिन पन्ने बराबर होने से बजट एक जैसा नहीं होता। मुझे लगता है कि सबेरे रविन्द्र रवि जी ने अपने चश्मे महेन्द्र सिंह जी को दे दिए थे और आप दोनों एक ही चश्में से सब-कुछ देखना चाहते हैं, उसी से यह गड़बड़ हो रही है। आप अपना-अपना चश्मा अलग रखो तो सबको ठीक नज़र आएगा।

अध्यक्ष महोदय, अर्बन एरिया में पार्किंग के लिए 10.00 करोड़ रुपये का बजट रखना एक सराहनीय कदम है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पार्किंग की समस्या केवल अर्बन एरियाज में ही नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं विशेषकर जो सब-डिविजनल हैड क्वार्टर्ज़ हैं, जैसे सलूणी सब-डिविजनल हैड क्वार्टर है जो अर्बन एरिया नहीं है, पंचायत एरिया है। इसी तरह तीसा भी पंचायत एरिया है। और भी बहुत सारे सब-डिविजनल हैड क्वार्टर्ज़ होंगे जो पंचायत एरिया में पड़ते हैं जहां पार्किंग की भयंकर समस्या हो गई है। आजकल गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन पार्किंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अर्बन लोकल बॉडीज के एरिया को छोड़ कर भी वह इलाके हैं जहां पर सब-डिविजनल हैड क्वार्टर्ज़ हैं या जहां पर कोई रिलिजियस इंपौर्टैंस के मंदिर है जहां लोगों की भीड़ रहती है; जैसे कि भलई माता मंदिर है, ऐसे स्थानों पार्किंग के लिए कोई-न-कोई योजना होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे टूरिज्म हब्ज हैं, वहां के लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए।क्रैश बैरियर्ज़ के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं, यह एक अच्छा कदम है।

मुख्य मंत्री सड़क योजना में लॉस्ट माईल कनैक्टिविटी की बात है। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा होता और होगा अगर मुख्य मंत्री जी सभी विधायकों को क्लैरिफाई कर दें कि इस योजना के तहत कौन-सी सड़कें आएंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण इसु है क्योंकि लॉस्ट माईल कनैक्टिविटी में हो सकता है कि 750 मीटर सड़क रह गई हो या एक किलोमीटर या 100 मीटर रह गई हो।

जारी ...गर्ग जी

17/03/2016/1255/RG/AS/1
श्रीमती आशा कुमारी----क्रमागत

तो लास्ट माइल कनैक्टिविटी का ऐग्जैक्ट क्या मतलब होगा और इसमें क्या योजनाएं ली जा सकती हैं, इसका स्पष्टीकरण और जानकारी सभी विधायकों के पास होनी चाहिए ताकि हम अपनी योजनाओं को उस तरह से बना सकें।

अध्यक्ष महोदय, जो एच.पी. रोड प्रोजैक्ट सैकण्ड फेज़ 3,200 करोड़ रुपये का अप्रूव हुआ है उसके लिए भी आपको बधाई है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी डी.पी.आर्ज. बनकर तैयार हैं। क्योंकि मेरा और अन्य माननीय सदस्यों का यहां एक प्रश्न लगा हुआ था कि पिछले वित्तीय वर्ष में यानि जो चालू वित्तीय वर्ष है, इसमें कितना पैसा पी.एम.जी.एस.वाई. में भारत सरकार से आया, तो जवाब 'शून्य' था। मुझे उम्मीद है कि पी.एम.जी.एस.वाई. का जो रुका हुआ पैसा है वह भारत सरकार अब रिलीज़ जरूर करेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो एफ.आर.ए. और एफ.सी.ए. clearances हैं, इनको स्पीड अप करने की आवश्यकता है। इसी सदन में आपकी अनुमति से मैंने एक प्रश्न भी लगाया था और चर्चा भी उठाई थी, माननीय सदस्यों ने उसमें हिस्सा भी लिया था क्योंकि दोनों पक्षों के सदस्यों का कंसर्न इस बारे में है। जो हमारी एफ.सी.ए. clearances हैं और जो सड़कें हमारी वॉयोलेशन में बनी थीं, हाई कोर्ट ने जिनको वॉयोलेशन में पाया उन सड़कों की F.C.A. clearance के लिए समितियां बनी थीं। लेकिन अभी तक वॉयोलेशन वाली सड़कों की F.C.A. clearance नहीं हुई हैं। कंजरवेटर फॉरेस्ट उस कमेटी के हैड हैं और कंजरवेटर एवं ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकट्ठे ही नहीं हो पाते हैं। 2000 से ज्यादा सड़कें रैग्युलराईज नहीं हो पा रही हैं उन पर हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि जितने पैसे आपने रखे हैं, ये तभी सार्थक होंगे जब ये clearances होंगी। अगर clearances ही नहीं होंगी, तो इन सड़कों के लिए पैसा रखने का क्या ओचित्य होगा? हमारी स्कीम F.C.A. clearance के कारण रुकी हुई है। F.R.A. की जो भारत सरकार से क्लेरीफिकेशन आई है, मुझे यह लगता है कि इस क्लेरीफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी। इस एक्ट को पढ़ने की क्षमता हममें खुद होनी चाहिए थी, हमने क्लेरीफिकेशन क्यों मांगा? हमने दो साल बरबाद किए और हमारा जो वन विभाग है, उसने अपने ही एक्ट को समझने में नासमझी की। अगर अपने एक्ट को वे समझ लेते, तो उनको क्लेरीफिकेशन लेने की जरूरत ही नहीं थी।

17/03/2016/1255/RG/AS/2

हमने तो कई बार कहा कि यह जो एक्ट है इसको ही आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सदन में भी बहुत बड़े-बड़े वकील बैठे हैं, इन्हीं से पूछ लेते, वकीलों से ही पूछ लेते, तो ये समझ लेते कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो 'आदर्श विद्यालय योजना' शुरू की है, अच्छी है। इसमें हर विधान सभा क्षेत्र में 2 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को आदर्श विद्यालय नामित किया जाएगा। इससे उनकी मन्शा लगती है कि पढ़ाने के अति-आधुनिक साधनों से युक्त क्लास-रूम्ज़ बनाए जाएं। आजकल टीचिंग टैक्नीक्ज़ नई-नई आ गई हैं जैसे स्मार्ट क्लासिज इत्यादि है, उससे पढ़ाया जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा अभी मानना है कि सबसे जरूरी है कि जो भी हम आदर्श विद्यालय बनाएं, उनमें स्टाफ पूरा होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता में जो कमी आती है वह स्टाफ की कमी के कारण आती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए यदि अध्यापक नहीं होंगे, तो आप जितनी मरजी सुविधाएं दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको इनमें स्टाफ की पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी योजनाओं के तहत अध्यापक लगे हुए हैं। कुछ का इस बजट में वेतन भी बढ़ाया गया है। 'पी.ए.टी.' अध्यापकों को नियमित किया जाएगा और ई.जी.एस. अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और उन्हें अब 3,500/-रुपये के स्थान पर 7,000/-रुपये दिया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे 'पी.टी.ए.' पॉलिसी के अन्तर्गत जो टीचर्स लगे हुए थे उनमें से कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनकी break in service हो गई और वह इसलिए हुई कि जब सरकार बदली, तो कुछ राजनीतिक एवं कुछ अन्य कारणों से उनको निकाल दिया गया। उनको कोर्ट से दुबारा वापस लगा दिया गया। लगभग 600-700 ऐसे टीचर्स हैं और अक्सर वे सभी को मिलते रहते हैं। चाहे पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सभी से वे मिलते रहते हैं और वे अपनी बात रखते हैं कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी कि उनकी सर्विस ब्रेक हुई।

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1300/MS/DC/1

श्रीमती आशा कुमारी जारी--------

अब सात साल में आप इनको कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे हैं। उनकी सर्विस नौ-नौ साल हो गई है मगर बीच में due to break उनको कन्सीडर नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा सरकार से यह निवेदन रहेगा कि चाहे इनको वित्तीय लाभ मत दीजिए लेकिन वन टाइम रिलैक्सेशन दीजिए। जिनकी सर्विसिज कोर्ट से बहाल हुई हैं उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दीजिए। आप उनको वित्तीय लाभ कुछ मत दीजिए मगर जिनकी सर्विसिज नौ-नौ साल हो गई है just because बीच में छः-छः महीने के लिए due to some reasons हटा दिया गया और कोर्ट से फिर उनको वापिस लगा दिया गया, उनको यह वन टाइम रिलैक्सेशन देकर अनुबंध पर कर दिया जाए।

अध्यक्षः माननीय सदस्या, कृपया एक मिनट के लिए बैठिए। अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है लेकिन क्योंकि आप बोल रही हैं तो आप बोल लीजिए फिर उसके बाद दोपहर का भोजन कर लेंगे।

सदस्यगणः अध्यक्ष जी, ठीक है।
अध्यक्षः माननीय सदस्या, आप अपनी चर्चा जारी रखिए।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री और सरकार बधाई की पात्र है कि यंग विडोज जिनकी उम्र 45 साल से कम है उनकी पैंशन 600/-रुपये से बढ़ाकर 1200/-रुपये कर दी है। इसी तरह से फंक्शनल पोस्ट्स 13,000 भरने की बात कही गई है और दैनिक भोगी कर्मचारियों के वेतन को 180/-रुपये से बढ़ाकर 200/-रुपये करने की बात भी कही गई है।

अध्यक्ष जी, आज प्रश्न काल में मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था। क्योंकि हम रोज़गार की बात कर रहे हैं तो चाहे वह चम्बा जिला हो, हिमाचल प्रदेश हो, देश हो या विदेश हो, सभी जगह आज सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है। बहुत सारी जगहों पर इण्डस्ट्रियल एरियाज सैटअप हुए हैं और कामयाब भी हैं। इण्डस्ट्रियल एरिया ऊना, सोलन, नाहन में तो

है ही लेकिन अब कांगड़ा में भी एक और बनने जा रहा है। मगर चम्बा एक ऐसा जिला है जहां इण्डस्ट्रियल एरिया

17/03/2016/1300/MS/DC/2

सैटअप करने का बहुत कम स्कोप है। बल्कि निल है। वहां पर रोज़गार या तो हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट से मिल सकता है या जो आज प्रश्नकाल के अंत में मेरा प्रश्न संख्या 2949 सीमेंट कारखाने को लेकर लगा था, उससे हो सकता है। अध्यक्ष जी, सीमेंट कारखाना ही एक ऐसा उद्योग चम्बा के लिए है जो वहां के लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है। माननीय मंत्री जी जब प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि यह सीमेंट प्लांट चुराह क्षेत्र में लगना है। जबकि ऐसा नहीं है। इसकी जो माइनिंग लीज है, वह चुराह क्षेत्र की है लेकिन इसकी बाकी कालोनिज और जो प्लांट सैटअप होना है, वह मेरे चुनाव क्षेत्र में है। मेरे और माननीय सदस्य श्री हंस राज जी के चुनाव क्षेत्र के बीच में सिर्फ एक नदी का फासला है वैसे साथ-साथ ही लगता है। यह विषय हमारे क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि चम्बा चुनाव क्षेत्र से भी संबंधित है। क्योंकि यह रोजगार का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि दो साल तो वैसे ही निकल गए। आपने कोशिश की होगी, मैं इस बात को डिस्प्यूट नहीं करना चाहती। मगर सच्चाई यह है कि आज की तारीख में कुछ नहीं हुआ है। चाहे कारण यह रहा हो कि केन्द्र सरकार ने अपनी नीति बदल दी, चाहे कारण यह रहा हो कि नई नीति के तहत आप एप्लीकेशन्ज इन्वाइट नहीं कर सकते, आपको ऑक्शन करना है। मगर मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस सीमेंट प्लांट को समयबद्ध तरीके से ऑक्शन कर दिया जाए। जो भी इसकी प्रक्रिया है या जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है उसको अपनाते हुए इसकी ऑक्शन करें ताकि चम्बा जिला के लोगों को भी कुछ रोजगार उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा, बिजली बोर्ड का एक और सब्सीडरी एच0पी0सी0सी0एल0 है। मेरे चुनाव क्षेत्र में 48 मेगावाट का सुंडला-सुरगानी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट है। उसका सब कुछ हो चुका है। एन्वायरनमैंट क्लीयरैंस भी हो चुकी है मगर फडिंग अभी तक टाई-अप नहीं हुई है। दो साल से मैं इस मामले को इस सदन में उठा रही हूं और सदन के बाहर भी

उठा रही हूं। मुझे यह आश्वासन मिलता रहता है कि इसकी फण्डिंग जल्दी होने वाली है। अध्यक्ष जी, यदि वह प्रोजैक्ट चालू हो जाएगा तो मेरे और माननीय हंस राज जी के चुनाव क्षेत्र में, क्योंकि हमारे चुनाव क्षेत्रों के बीच में वह प्रोजैक्ट पड़ता है तो वहां कुछ रोजगार के अवसर अवश्य ही आएंगे।

17/03/2016/1300/MS/DC/3

अध्यक्ष जी, बजट हर क्षेत्र में कुछ-न-कुछ बात लेकर आया है। आज की तारीख में चाहे वह हिन्दुस्तान का निवासी हो या हिमाचल का हो, सभी महंगाई से त्रस्त हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने सस्ती दरों पर दालें, तेल और नमक देने का प्रावधान रखा हुआ है वरना अध्यक्ष जी, जो आजकल महंगाई की मार है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

16.03.2016/1305/जेएस/डीसी/1

श्रीमती आशा कुमारीः-----जारी-----

उससे बचना बहुत मुश्किल है। कुछ न कुछ इस तरह की योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार चलाएगी तभी जा करके इस मंहगाई की मार से एक साधारण परिवार बच सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हर वर्ग के लिए चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे बागवान हों, चाहे किसान हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों और यहां तक कि चाहे माननीय विधायक हों, इन सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करती हूं। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित की जाती है।

17.03.2016/1420/SS-AG/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2:20 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने उनके मुताबिक हिमाचल प्रदेश का 19वां बजट प्रस्तुत किया। इस 19वें बजट में क्या लिखा है यह तो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन पहले यह बताना चाहता हूं कि 16 कविताएं, शेर, उक्तियां इस बजट भाषण में उन्होंने लिखीं और लगता यह है कि तीन साल की गहरी निद्रा के बाद जब बजट भाषण लिखने लगे तो पहले वे कविताएं लिखने लग गये थे तथा कविता लिखते-लिखते ही बजट पर कुछ चीज़ें लिख दीं। उनको बधाई सिर्फ इस बात की है कि वे साढ़े तीन घंटे खड़े रहे और उन्होंने खड़े रहकर बजट भाषण दिया। बाकी इस बजट में न तो कोई कंटैंट है, न यह प्रदेश के हित में है और न ही कोई इसमें सत्यता है।

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1425/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

क्योंकि तीन वर्ष तक कौमा की स्थिति में यह सरकार रही है और अभी भी ऐसा लगता है कि इलैक्शन की आहट देखकर सेमी कौमा की स्थिति में आने की कोशिश कर रही है और इनको अपनी पुरानी बातें भी याद नहीं रहती जो इन्होंने अपने मेनिफैस्टो में लिखी है। 2016-17 के लिए 32, 593/- करोड़ रु0 का बजट अनुमान प्रस्तुत किया है जिसमें से 9,445 करोड़ तो वेतन पर चले जाएंगें। 4200 करोड़ रु0 पैंशन पर चले जाएंगें और ब्याज अदायगी पर 3400 करोड़ रु0 जाएंगें । जो बाकी ऋणों की वापसी है उस पर 2229 करोड़ चले जाएंगें। फिर कुछ और ऋण लिए हैं जिन पर इनके 428 करोड़ रु0 चले जाएगें। फिर मेंटिनैंस वगैरह के काम के लिए केवल 2,266 करोड़ रु0 बजट में रह जाते हैं। 476 करोड़

रु0 का राजस्व घाटा है और 4,076 करोड़ रु0 का वित्तीय घाटा है। इसमें से प्रति व्यक्ति 100 रुपये के मुकाबले 80.60 कुल प्राप्तियां हैं और 19.40 का अंतर ऋण से पूरा होगा, यह अपने बजट अनुमान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है। ऋण के बारे में जो उन्होंने बजट भाषण में बताया वह 31 मार्च, 2015 का फीगर दिया है। लगभग 35 हजार करोड़ रु0 का ऋण हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी तक ले चुकी है और ऋण की स्थिति इतनी क्यों हुई है, माननीय रविन्द्र सिंह जी ने इस पर संक्षेप में टिप्पणी की थी। 9वें वित्तायोग के अध्यक्ष एन.के.पी. साल्वे की अध्यक्षता में जब यहां पर 9वां वित्तायोग आया था वे आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे केन्द्र में वे वित्तायोग के अध्यक्ष थे । उस समय उनसे जो बजट के एक्चुअल अनुमान थे, उनको छिपाया गया ओर यह दर्शाया गया कि हम तो बहुत बड़े नेता है और उस समय जो वित्त सचिव थे, वे भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री अपने आप को मानते थे और उसकी नतीजा यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश को जो एडमिनिस्ट्रटिव एक्सपेंडिचर में 90:10 के हिसाब से जो केन्द्र से ग्रांट मिलती थी, विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था, वह दर्जा समाप्त हो गया और उसके बाद यह नतीजा हुआ कि हर साल आपको ऋण लेना पड़ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी का और पक्ष के साथियों का तो लगता है कि वे चारवाक की उस युक्ति पर अमल करते

17.03.2016/1425/केएस/एजी/2

हैं कि ऋण लेते जाओ और घी पीते जाओ। ऋण ले रहे हैं उससे वे अपनी मौज मेला कर रहे हैं प्रदेश की जनता की चिन्ता नहीं है। पांच साल किसी तरह से निकाल दो उसमें जो कुछ भी कर सकते हैं, जितने भी लोगों को लाभ दे सकते हैं जो इनके माफिया काम करते हैं, वह सब कुछ करते रहो ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2016/1430/av/as/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागत

क्योंकि उसके बाद तो हमें दोबारा आना नहीं है इसलिए ऋण लेकर काम करते जाओ। अभी 31 मार्च तक 35000 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया जो पिछले साल लिए गए ऋण को मिलाकर 50000 करोड़ के लगभग पहुंच जायेगा तथा अगले वर्ष तक 60000 करोड़ की सीमा लांग सकता है। अभी जिस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में चल रही है उसको देखते हुए यह होना स्वाभाविक है। यहां पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन या ऐक्सपैंडिचर कंट्रोल के लिए आपने कोई भी कदम इस बजट भाषण में नहीं दिखाए हैं। आपने रिसोर्स कंट्रोल के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षा मैडम विद्या स्टोक्स जी को बनाया था और शायद मुकेश अग्निहोत्री जी मैम्बर थे। उस कमेटी से ठाकुर कौल सिंह जी तो रिजाईन कर गये थे। उस कमेटी के बारे में बड़ा शोर हुआ, मीडिया ने भी बड़ा शोर किया। उस कमेटी के क्या सुझाव थे या उसकी क्या रिपोर्ट थी; इस बारे में कुछ नहीं पता। वह कमेटी कभी बैठी या नहीं बैठी; उसमें तो कमेटी का गठन होते ही अध्यक्षता की वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। उस कमेटी की तरफ से रिसोर्स कंट्रोल के लिए दिया गया कोई भी सुझाव आज तक प्रदेश सरकार की ओर से नहीं आया। इस बजट भाषण में भी इस बारे में एक लफ्ज नहीं कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाईजेशन किस प्रकार से करेंगे। आप तो रिसोर्स मोबिलाईजेशन में और भी कमी करते अगर हमारे विपक्ष के नेता द्वारा ऐक्साइज पॉलिसी के बारे में मामला न उठाया गया होता। इसी तरह से आपने ऐक्सपैंडिचर कंट्रोल पर भी कोई काम नहीं किया है। जैसे यहां पर माननीय नरेन्द्र ठाकुर जी ने अपने भाषण में कहा था कि आप रोजाना नई-नई कॉर्पोरेशन्ज बनाते हैं। ऐसी कॉर्पोरेशन्ज हैं जिसमें आपके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है मगर आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बना रहे हैं। उनको गाड़ियां दे रहे हैं, टी0ए0/डी0ए0 दे रहे हैं। जिसमें कोई काम ही नहीं है उसके आप चेयरमैन बना रहे हैं। अब तो आई0टी0आई0 की जो एस0एम0सीज0 होती हैं उसके चेयरमैन आई0टी0आई0 के दफ्तर में जाकर बैठते हैं और अपनी गाड़ियों में बत्तियां

17.3.2016/1430/av/as/2

लगाकर घूमते हैं। यहां पर ऐडवोकेट जनरल के संदर्भ में किए गए प्रश्न के जवाब में कहा था कि आपने 40 के लगभग लॉ ऑफिसर बना दिए। आपने बनाए हैं तो उनसे काम लीजिए। यह मसला यहीं पर आया था कि आपने कुछ वकील बाहर से अप्वाईंट किए हुए हैं। आपने 8-10 आदमी अप्वाईंट किए हुए हैं और उनकी फीस देने को बनती है। वह फीस या आपने कितने पैसे किस वकील को दिए हैं, आप उसका विधान सभा के अंदर ब्यौरा तक नहीं देते हैं। अब अच्छा बजट कैसे बनेगा? उसके लिए आप ऋण लेते हैं। फिर ऋण की वापसी और उस पर लगने वाले ब्याज की वापसी, इसके अलावा विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी सरकार पिछले तीन वर्षों से कौमा की स्थिति में है। विकास के नाम पर आपका यहां पर एक भी पत्थर नहीं हिल रहा है। आपको वर्ल्ड बैंक से ऐक्सटैंशन मांगनी पड़ रही है। हाटकोटी-ठियोग सड़क का काम अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। मगर आपका उस सड़क का काम समाप्त नहीं हो रहा है और आज भी अगर आप उस रास्ते पर जाएं तो वहां पूरा-का-पूरा आदमी कीचड़ में डूब जाता है। आपके पास विकास करवाने के लिए कुछ भी नहीं है इसीलिए आपने अपने बजट भाषण में कोई भी बात ढंग से नहीं की है। आप केंद्र सरकार से केवल स्पैशल प्लान ऐसिस्टैंस मांगते हैं कि वह हमारी खत्म हो गई क्योंकि वित्त आयोग आ गया और प्लानिंग कमीशन चला गया। मगर उसके बावजूद आपका जो टैक्सिज का डैवोल्यूशन था, जो कि 32 प्रतिशत तक होता था वह फाईनैंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 42 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उसके कारण आपको आज 40625 करोड़ रुपये रैवन्यू डैफिसिट ग्रांट का मिलेगा। इसमें से 8000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिल रहे हैं और इस वर्ष का आपको पैसा मिल भी चुका है।

टीसी द्वारा जारी

17.03.2016/1435/TCV/DC/1

श्री सुरेश भारद्वाज----- जारी

इस बात का जिक्र कहीं नहीं है कि उस पैसे का आप क्या उपयोग कर रहे है? किसी प्लॉन के लिए कर रहे हैं या प्रदेश की जनता के विकास के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है? क्या इसका उपयोग, आपके चेयरमैन और माफियाज़ जो काम कर रहे है, कहीं उनके ऊपर तो नहीं हो रहा? आप इस बात का जिक्र भी नहीं करते कि आपको केन्द्र सरकार से क्या मिल रहा है? आपको 40 हजार करोड़ के अतिरिक्त, 30 हजार करोड़ रूपये की अन्य एसिस्टेंस अगले 5 साल में मिलने वाली है। इस बात के लिए धन्यवाद करना तो दूर, आप इसका जिक्र तक नहीं करते हैं। आपने स्किल डैवेल्पमैंट पर यहां सदन में बहुत बातें की हैं। इसके लिए आपने स्किल डैवेल्पमैंट कारपोरेशन बना दी है और स्किल डैवेल्पमैंट कारपोरेशन में रूरल डैवेल्पमैंट मिनिस्ट्र, टैक्निकल ऐजूकेशन मिनिस्ट्र और शायद इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्र,श्री मुकेश अग्निहोत्र जी भी हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी उसके चेयरमैंन है लेकिन इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं हैं। अगर आप 500 करोड़ रूपया 5 साल में खर्च करेंगे तो इसका मतलब है कि 100 करोड़ रूपया एक साल में खर्च करेंगे। अब तो आपने एक नया नोटिफिकेशन कर दिया है कि कारपोरेशन में प्रदेश के स्किल डेवैल्पमैंट एक्सपर्ट रखे गये हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह भी उसके मैंबर होंगे। अगर आप इसमें रखना चाहते तो इसमें सारी पॉलिटीकल पार्टी के युवा नेताओं को रख सकते थे। आप स्किल डैवेल्पमैंट कारपोरेशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाते। आप जो इस प्रकार की कारपोरेशन्ज बना रहे हैं आपने इसमें एक साल में कितने लोगों को स्किल डैवेल्पमैंट के कोर्सिज़ करवांए हैं? यहां पर पहले चर्चा हो चुकी है कि कितने फ़ेक आर्गेनाइजेशन्ज़ थे जिनको आपकी सरकार ने लाईसैंस दे रखे थे और वह आर्गेनाइजेशन्ज़ सर्टिफिकेट बांटते थे। इसका कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। आपने अपने मैनीफेस्टो में कहा है कि हम साल में एक लाख लोगों को स्किल डैवेल्पमैंट के आधार पर रोजगार देंगे। लेकिन अगर आपने एक लाख लोगों को स्किल डैवेल्पमैंट दी है तो उसका आंकड़ा कहां है? क्या वह एक लाख लोग इम्पलाईमैंट एक्सचेंज में दर्ज हो जाएंगे और जो आपका 8 लाख का आंकड़ा है एक साल में उसे बढ़ाकर 9 लाख तक ले जाएंगे। इसका आपके पास कोई आंकडा नहीं है न ही उस कॉरपोरेशन में कोई पारदर्शिता है। आप ने यह भी कहा

17.03.2016/1435/TCV/DC/2

था कि हम स्किल डेवैल्पमैंट अथोरटी बनायेंगे। ये मैनीफेस्टिो कांग्रेस का पर्सनल डॉक्युमैंट नहीं रह गया है ये आपकी सरकार का एक दस्तावेज़ हैं। उसमें आपने अथोरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। पिछले कल इस मान्य सदन में बहुत जोर-शोर से चर्चा हो रही थी कि आपने इलैक्शन तो जीत लिया लेकिन यह इलैक्शन आपने प्रदेश के युवाओं को बेवकूफ बनाकर जीता है, उनको धोखा दे करके, उनको यह कह कर कि कांग्रेस आएगी तो हम आपको 1000 से 1500 रूपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। कल जब चर्चा यहां पर आई तो आपने कहा कि मैनीफेस्टिो में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। आपने मैनीफेस्टिो के पेज़ 23 पर जहां कर्मचारियों के लिए लिखा है कि राज्य के ऐसे बेरोजगार 10+2, स्नातक युवा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक है को 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां सदन में इस बात के लिए मुकर रहे हैं। जब आपको आपका डाक्युमैंट बताया जाता है तो आप कहते हैं कि ये तो बाली जी ने बनाया है, हमने तो बनाया ही नहीं है। आप जिस चीज़ को लेकर चुनाव में गये आज आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कौशल विकास भत्ता, जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के समय से चल रहा है, आज माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने केन्द्र में इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई है। वहां से पैसा प्रदेश की सरकारों को आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम भी कौशल विकास कर रहे हैं लेकिन आप तो बेरोजगारों की भीड़ बढ़ा रहे हैं।

श्री आर0के0एस0 --- द्वारा जारी ।

17.03.2016/1440/RKS/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज द्वारा... जारी

सरकार को जानकारी नहीं है कि कौशल विकास किस को दिया है। एच0आर0टी0सी0 में तो माननीय श्री बाली जी ने कण्डक्टर के नाम पर ही कौशल विकास चला दिया है। कौशल विकास भत्ते के नाम पर दो-अढाई महीनें के लिए कंडक्टर रखे जाते हैं और1,000 रुपए कौशल विकास भत्ता देकर उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। सारी की सारी बसें सड़कों पर खड़ी रहती है। हमीरपुर के बारे में ठाकुर साहिब बता रहे थे कि वहां 20 गाड़ियां सड़क पर खड़ी हुई हैं। यह कहा जाता है कि हमारे पास कोई कंडक्टर नहीं है। जब आप यहां से परवाणु की ओर जाते हैं तो आपको रास्ते में नीली, लाल, पीली सब तरह की बसें

सड़क पर खड़ी मिलती है। अगर इनको कहा जाए कि लालपानी से खलीनी तक बस लगाओं तो कहते हैं कि हमारे पास कंडक्टर नहीं है। आप कौशल विकास वालों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। एच.आर.टी. सी. के लिए पिछले साल 400 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान था। लेकिन न उनके पास वर्कशॉप में काम करने वाले लोग है, न उनके पास कंडक्टर हैं, न उनके पास बसें हैं। जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने, नीतिन गडकरी जी ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत प्रदेश को बसें दी है, वही बसें उनके पास है। लेकिन आप उन बसों को प्रदेश में चला भी नहीं सकते हैं। लम्बी-लम्बी बसों को आपने ऐसी सड़कों में चला दिया है, जहां पर छोटी गाड़ियों को ले जाना भी मुश्किल काम है। स्किल डवलेपमेंट में आप पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं। आपने साढ़े तीन घंटे का बजट भाषण तैयार कर दिया और उसमें वाहवाही लूट ली की हम साढ़े तीन घंटे खड़े रह सकते हैं। अगर यही स्थिति रही तो आप अगली बार इसी तहर से खड़े रहेंगे क्योंकि जनता आपको यहां बैठने नहीं देगी। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रर्यटन नगरी किसी समय ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान की राजधानी रही है। देश विदेश का पर्यटक यहां पर आता है। उस हिमाचल प्रदेश की राजधानी में पीलिया के रोग से हजारों लोग पीड़ित हो गए, बड़े-बड़े अधिकारी पीड़ित इस रोग से गस्ति हो गए। जिस समय यहां पीलिया का प्रकोप बढ़ा उस समय यहां इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं था।

शिमला की जनता यह समझती है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इस बार सर्दियों में बर्फबारी नहीं हुई है। यहां पर पानी की दिक्कत आ रही है। अश्वनी खड्ड का पानी आपने बंद कर रखा है। गिरि में सिल्ट आने के कारण पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है।

17.03.2016/1440/RKS/AS/2

आजकल शिमला में तीसरे दिन पानी दिया जा रहा है और तीसरे दिन भी लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के बारे में बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। अगर शिमला के लिए पानी चाहिए तो चांसल से जो स्कीम बनती है, चंद्रनाहन से जो स्कीम बनती है उस स्कीम को लाना ही पड़ेगा। आपने 10-15 साल पहले भी यह बात कही थी, अगर आपने उस समय यह स्कीम बना दी होती तो यह बहुत कम धनराशि में तैयार हो जाती। दूसरा अल्टरनेट, जो बंसतपुर और सुन्नी के पास कॉलडैम का रेजरवायर बना हुआ

है उससे पानी मुहैया हो सकता है। लेकिन रैक्रिंग एक्सपेंडिचर उसमें इतना ज्यादा होगा कि ऋण लेने वाली सरकार इसे कभी पूरा नहीं कर सकती है। इस बजट में पानी के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। पूरे प्रदेश के पानी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। पानी की स्थिति क्या होगी? आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं। रोहतांग में सी.एन.जी. चलाना चाहते हैं, वहां सारा कारोबार बंद करना चाहते हैं। लेकिन राजधानी में पानी कैसे मिलेगा इस बजट भाषण में चर्चा नहीं की जाती है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप संक्षेप में बोलिए, आप कितनी देर बोलेंगे? बात यह है कि अगर सभी वक्ताओं ने बोलना है तो आपको अपना टाईम करटेल करना पड़ेगा।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्षः बैठने की बात नहीं है, You are very senior Member. आप ध्यान रखें कि बाकि सदस्यों ने भी बोलना है।

सुरेश भारद्वाजः मैं बिल्कुल रैलिवेंट विषय पर बोल रहा हूं। मैं पॉलिटिक्ल भाषण नहीं दे रहा हूं। एजूकेशन के लिए यहां पर चर्चा हुई।

श्री गर्ग द्वारा जारी...

17/03/2016/1445/RG/DC/1
श्री सुरश भारद्वाज----क्रमागत

बहुत सारे स्कूल खोल दिए जाते हैं। शिमला में भी स्कूल हैं, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। क्योंकि शिमला में इसलिए स्कूल खोलने पड़ते हैं क्योंकि टीचर्स को ऐडजस्ट करना होता है। प्राथमिक स्कूलों में यहां कोई बच्चे नहीं होते। लेकिन जिस चीज की व्यवस्था इस बजट में होनी चाहिए थी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है। उसके जो रिटायर्ड लोग हैं उनको पेन्शन नहीं मिल रही है। हमने वर्ष 2011-12 में 81 करोड़ रुपये की ग्रांट दी

थी। आज उस विश्वविद्यालय का 150 करोड़ रुपये का बजट है और उसमें उनका 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा है। हमारी ग्रांट जो आज से पांच साल पहले 81 करोड़ रुपये थी, इस बार उनको 90 करोड़ रुपये दे दिया गया । 100 करोड़ रुपये भी पूरा नहीं किया। अब यह विश्वविद्यालय कैसे चलेगा? वहां के जो कुलपति और वहां की जो ऐग्जीक्यूटिव कॉउन्सिल। है वह गरीब बच्चों की फीसें बढ़ा रही है। विश्वविद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालयों में सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीसें exorbitant रूप में बढ़ा दी गई हैं। इस सरकार को यह सारी बीमारी है कि एक समिति बनाते हैं, लेकिन फिर उसकी रिपोर्ट नहीं आते देते। जैसे इन्होंने एक कमेटी रिसोर्स मोबिलाईजेशन की बनाई थी वैसे ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर एक समिति बनाई गई थी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके चेयरमैन थे और अब वे ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के चेयरमैन हैं। लेकिन उनकी बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट के दर्शन नहीं हुए, लोगों को उस कमेटी की रिपोर्ट के दर्शन हो जाएं, इसके लिए लोग तरसते रहे, लेकिन आपने उसको लोगों को दिखाना मुनासिब नहीं समझा। हम जानना चाहते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या था? कितनी फीस बढ़नी चाहिए, यदि रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना हे, तो फीस बढ़नी चाहिए, लेकिन कितनी फीस बढ़नी चाहिए थी, कम-से-कम उस कमेटी की रिपोर्ट का साक्षात्कार तो कराते। आपने उस समिति के ऊपर टी.ए. एवं डी.ए. के ऊपर खर्चा किया है। कम-से-कम उसकी रिपोर्ट को लोगों को तो दिखाया जाता। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में क्या आपने सारे कॉलेजिज में 'रुसा' लगाया दिया है। अब 'रुसा' लगाने का नतीजा यह हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रेजुएट फाईनल सेमिस्टर के बच्चे यहां से निकल कर जा रहे हैं उनको हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेज़र विषय कैमिस्ट्री है, तो इन्होंने वहां पर माइनर विषय हिन्दी रख दिया है।

17/03/2016/1445/RG/DC/2

जब दूसरी जगह पर काम्बिनेशन में एम.एस.सी. के लिए जाता है, आपके पास कैमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहां के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर यह बहुत चिन्ताजनक विषय है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बाहर मौका नहीं मिल रहा है। इसके बारे में बजट में कुछ नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने

'रुसा' लगाया, बहुत अच्छा किया। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को हमने बाहर जाने से रोक दिया ताकि वे कहीं बाहर न जा सकें, कोई अच्छी डिग्री हासिल न कर सकें। इस प्रकार की स्थिति शिक्षा की प्रणाली को ठीक करने की आवश्यकता है। चाहे स्कूलों का सिस्टम भी है। आप यहां शिमला का सीनियर सैकण्डरी स्कूल, संजौली का देखिए। यह शिमला प्रदेश की राजधानी है। वहां की हालत देखिए कि किस हालत में वह स्कूल चल रहा है? उस बिल्डिंग में प्राथमिक विद्यालय भी नहीं चल सकता। जो वहां किराये की नगर निगम की बिल्डिंग है। आप इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे विचार करिए। उसके लिए पैसों का प्रावधान करिए, तो समझ में आएगा कि हिमाचल प्रदेश आगे प्रगति कर रहा है। लेकिन जब आप कुछ काम नहीं करेंगे, तो यहां स्थिति खराब होती जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हिमाचल पथ परिवहन निगम का मैंने जिक्र किया कि किस प्रकार से चल रही है। उनकी गाड़ियां चलती हैं, वह घाटे में जा रही है, फिर ऊपर से जो उनके पेन्शनर्ज हैं उनको पेन्शन नहीं मिल रही है। पिछले तीन महीने से दर-दर भटक रहे हैं। जो उनके ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं जब वे हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के एम.डी. के पास जाते हैं, तो वे खड़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की है। इन सारे-के-सारे निगम और बोड्र्ज की है। इस स्थिति में इस बजट का समर्थन करना बहुत मुश्किल काम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : इसमें शिमला नगर निगम की ग्रांट नहीं बढ़ाई गई है। किसी काम के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। वह सेन्टर्ज की स्कीम पर निर्भर रहता है, उनको अप्रूव नहीं किया जाता और मुश्किल यह है कि जब स्मार्ट सिटी के लिए प्रतियोगिता है,उसमें भी फिगर्ज की फरजिंग कर दी जाती है।

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1450/MS/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी-------

एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार और कोशिश कर रहे हैं कि उस स्मार्ट सिटी के चक्कर में गांव और नगर के लोगों को कारपोरेशन का झांसा दिया जाए। लेकिन कारपोरेशन में जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। पानी के लिए आप यहां पर कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और पीलिया जैसे भयंकर रोग की स्थिति पर कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि IGMC हिमाचल प्रदेश का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसको खत्म नहीं करना है। आप सारे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाइए लेकिन अगर शिमला में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होंगी तो सारे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम होगा। सारे प्रदेश के लोग IGMC में अपना इलाज करवाने के लिए पहली व्यवस्था में आते हैं। पी0जी0आई0 में एमरजैंसी से अंदर जाना ही मुश्किल हो जाता है इसलिए IGMC में सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो केन्द्र से आपको पैसा मिलता है, जैसे कैंसर के लिए मशीनें लगाने हेतु आपको पैसा मिला है उसको अभी तक खर्च नहीं किया गया है। इस बारे में आपने यहां पर अपने जवाब में कहा है। आप जो बाकी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। मेरा स्वास्थ्य की दृष्टि से मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि IGMC से टीचर्स बाहर भेजने की बजाए इसको आप मेडिकल युनिवर्सिटी में कन्वर्ट कीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश में जो बाकी के कॉलेजिज भी बनेंगे, उनके लिए भी सुविधा होगी। क्योंकि यहां पर 5-6 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। इसलिए अगर एक मेडिकल युनिवर्सिटी बन जाएगी तो उससे पूरे प्रदेश के लोगों को सुविधा होगी यानी जो अपना इलाज करवाने के लिए यहां आते हैं उनको सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे यहां बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17/03/2016/1450/MS/AS/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, भारद्वाज जी ने मेडिकल युनिवर्सिटी की बात कही है। यह मामला पहले ही सरकार के विचाराधीन है और इसमें हमने एक बिल का प्रारूप भी तैयार कर दिया है। जैसे ही केबिनैट की मंजूरी मिलेगी, मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल युनिवर्सिटी होनी चाहिए। यह सरकार के विचाराधीन है।

17/03/2016/1450/MS/AS/3

अध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य जगजीवन पाल जी भाग लेंगे। कृपया संक्षिप्त में ही बोले।

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)ः अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 08 मार्च, 2016 को जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में इस बार हिमाचल प्रदेश के सारे वर्गों, सारे क्षेत्रों, चाहे सड़कों का क्षेत्र है, चाहे पीने-के-पानी का क्षेत्र है, अस्पतालों का क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र है, उसको मध्य-नज़र रखते हुए पूरे प्रदेश को राहत देने की कोशिश की है। पूरे एक वर्ष यानी एक अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक क्या-क्या हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा इसमें उसको दर्शाया है। मैंने अनुभव किया है कि इस बार मुख्य मंत्री जी ने नीचे के जो हमारे किसान हैं, उनके अंदर की आवाज को समझने की कोशिश की है। जिस सुलह क्षेत्र से मैं आता हूं। हमारे हजारों किसानों ने,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1455/**जेएस/एएस**/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव):------**जारी**-------

खेती-बाड़ी करना छोड़ दी। उसका एक ही कारण है कि बेसहारा, आवारा, जंगली पशु और बन्दर। आपने इस बार किसानों की दुखी हुई नब्ज़ को पकड़ा है। हमारी चाहे प्लानिंग की मीटिंग हो , चाहे प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग हो हमारे कांग्रेस के ही नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उस तरफ मेरे मित्र बैठे हैं उन्होने भी चिन्ता प्रकट की है और सभी लोग चिन्ता में हैं। हिमाचल प्रदेश का किसान जिसका रूख जमींदारी से, कृषि से हट रहा है उसको कैसे दोबारा उस तर्ज़ में लाया जाए और यह तीन चीजें ये हमारे लिए बहुत बड़ी

समस्या की बात है। पहले हमारे क्षेत्रों में बाहरासिंघा, वन गाय आदि नहीं होती थी। लेकिन अब 10-12 सालों से बाहरासिंघा,साम्भर, वन गाय ये रात को आ करके नुकसान करती है उसका कोई इलाज किसान के पास नहीं है और किसान निहत्था हो गया है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब उसने खेतीबाड़ी करना छोड़ दी है। लेकिन ये जो खेत संरक्षण योजना के लिए तार लगाने का एक शरूआत की है। हमारे साथी खास करके भारतीय जनता पार्टी के भाई और यहां तक कि मुख्य मंत्री विपक्ष के नेता सबसे पहले इसके ऊपर उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने भी यह चिन्ता व्यक्त की कि इसमें पता नहीं जो सोलर करंट लगेगा उससे क्या पता कि आदमी मर जाएं? कोई दुर्घटना हो जाएगी। उनके बाद जितने भी वक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोलें हैं सबने इसके ऊपर नेगेटिव एटिट्यूट एडॉप्ट किया है कि इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाईयो, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने मुख्य मंत्री जी ने बड़ी भारी चर्चा करके बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को पूछ-पूछ करके इस योजना को शुरू किया है और मैंने भी कई भाईयों से बात की है। हमारा देश विकासशील है और हमारा प्रदेश भी विकासशील है। नये-नये प्रयोग होंगे। लेकिन जो विकासशील देश हैं वहां की सड़कों के किनारे भी ऐसी तारें लगा करके उसमें सोलर करंट गुजार करके ताकि वहां कोई ऐसी चीज़ वहां अन्दर न आ जाए उससे थोड़ा सा झटका लगेगा। इस करंट के साथ कोई मरेगा नहीं। बन्दर इसको छुएगा और उसे थोड़ा सा झटका लगेगा फिर दोबारा उसके पास आने की कोशिश नहीं करेगा। वन गाय आएगी उसको थोड़ा सा झटका

16.03.2016/1455/जेएस/एएस/2

लगेगा वह दोबारा से उसके पास आने की कोशिश नहीं करेगी। मित्रों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिल कर lets try once. इसको शुरू तो होने दो और हम सब लोग उसको शुरू करवाने में मदद करें। इस परिणाम मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे आएंगे। मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो इन्होंने इसके लिए 25 करोड़ रूपया रखा है, लेकिन यक 25 करोड़ भी जब यह किसान

इसे यूज़ करेगा, तार लगाएगा और उसकी खेती बचेगी फिर दोबारा से खेती करने लगेगा तो ये 25 करोड़ रूपए भी कम पड़ जाएंगे, इसमें दोबारा से और मांग आएगी। मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिए एक बहुत अच्छी योजना लाई है इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उनको मुबारकवाद देता हूं। इसके बावजूद दूसरी बात पिछले वर्ष के बजट में मुख्य मंत्री जी ने प्रावधान किया था कि हमने यह कहा था और सब लोगों ने यह मांग की थी

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

17.03.2016/1500/SS-AS/1

श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

कि हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं 80 साल के हो गये हैं उनके अमीर-अमीर लड़के हैं लेकिन वे कई जगह अपने माता-पिता की तरफ नहीं देख रहे हैं। वे बुरी खस्ता हालत में हैं। हमने कहा कि उनको आयसीमा के पहलू से बाहर निकाल दिया जाए। हमने तो 80 साल से कम आयु कहा था, हमने 70-75 आयुसीमा की मांग की थी, लेकिन अगर 80 साल आयुसीमा कर दी है तो भी उसके लिए धन्यवाद। वह भी स्वागत योग्य है। मैं अपने विपक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिन-जिन बुजुर्गों को पहला मनी ऑर्डर 6600-6600 रुपये का पहुंचा तो उन्होंने 'जय हो राजा वीरभद्र सिंह जी' कहा। इस बार भी आपने 100 रुपया और बढ़ाया है यह भी स्वागत योग्य है। लेकिन इस बार एक और अच्छा काम किया है। ये बोल रहे हैं कि इस किताब में तो कुछ है नहीं। मेरे भाई रवि जी पहले थुरल क्षेत्र से थे, अब थोड़ी दूर देहरा चले गये हैं। ये भी बोल रहे थे कि इस बजट बुक में कुछ नहीं है। अभी शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज जी भी बोलकर गये हैं कि इस बजट बुक में कुछ नहीं है। अरे, ये दो बातें तो मैंने कह दीं और अब तीसरी पर आ रहा हूं। हमारे समाज में एक बहुत दुखी वर्ग और है जिसकी आवाज़ मुख्य मंत्री जी ने सुनी है। यदि किसी शादीशुदा महिला का पति 18 साल से लेकर 40-45 वर्ष की आयु में किसी बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य वजह से मर जाता है जब हम उनके घर बैठने के लिए जाते हैं तो सारे-के-सारे गांव के लोग बोलते थे कि इसका कुछ करो। हम बोलते हैं कि 550 रुपया पैंशन लग जायेगी। हम तो यही कर सकते हैं और वह वाटर कैरियर लग सकती है। लेकिन आपने यह भी

समाज की दुखती नब्ज को पकड़ा है और उन बेचारी बेसहारा विधवाओं को जिनके दो-तीन बच्चें हैं और आय का कोई साधन नहीं है 600 रुपये से बढ़ाकर सीधे 1200 रुपये पैंशन की है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। यह तो इनकी सोच है। यह एक नहीं बल्कि विपक्ष का जो भी सदस्य बोलने के लिए उठ रहा है वह यही बोल रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि जितने भी वक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोले हैं सबने स्कूलों पर ही अटैक किया है कि स्कूल क्यों खुल रहे हैं। अरे भाइयों, स्कूल खुलने हैं। आपने तो स्कूल बंद कर दिये थे। मुख्य मंत्री जी ने आते ही दोबारा से उन स्कूलों को खोला। उसके लिए इनका धन्यवाद। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारा प्रदेश डिवैल्पिंग स्टेज पर है और इसके कारण ही जहां से भी

17.03.2016/1500/SS-AS/2

दूर-दराज़ से मांग आ रही है वहां स्कूल खोलने पड़ेंगे। मुख्य मंत्री जी इन्हें खोल रहे हैं इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। जैसे-जैसे हम डिवैल्पिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता उन स्कूलों में टीचर्ज़ भी आयेंगे। उन स्कूलों में बैठने का प्रबंध भी होगा। याद करो, जितने इस वक्त यहां बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूं कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल में शनिवार को आधे दिन की छुट्टी होती थी तो गोबर गांव से इकट्ठा करके लिपाई की जाती थी। आज वह चीज़ नहीं है। आज क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और पक्के कमरे बन रहे हैं। दोबारा अच्छी बिल्डिंगें बन कर तैयार हो रही हैं। आहिस्ते-आहिस्ते डैस्क बैठने के लिए आ रहे हैं। कुर्सियां आ रही हैं। अब स्मार्ट रूम बनाने की बात आ रही है। मॉडल स्कूल बनाने की बात आ रही है। भाइयों, ऐसी क्या बात है? यह सारा कुछ वापिस आयेगा। सब ठीक होगा। लेकिन आपके मन में जो शंका है इसको छोड़ दो। पॉजिटिव सोच शुरू करो। पॉजिटिव सोचना शुरू करो, अपने आप सब ठीक हो जायेगा।

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1505/केएस/एएस/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) जारी----

इसके बावजूद आपने बसों के बारे में जिक्र किया कि बसें खड़ी है। मैंने तो कोई बस खड़ी नहीं देखी। मेरे चुनाव क्षेत्र में हमारी तो मांग है कि और बसे चलाओ। आजकल तो हर जगह बसें दौड़ रही है, आपके क्षेत्र में क्यों नहीं दौड़ रही होंगी, यह मुझे नहीं पता।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक और बड़ा अच्छा फैसला लिया है। हमारे जो स्कूल है, कई वर्षों से स्कूलों में पी.ई.टी. और प्लस टू स्कूलों में डी.पी.ई. नहीं लग रहे थे। पहले तो क्रिकेट का जमाना था लेकिन अब पांच-छः साल से एक नया ट्रैंड आया है, कबड्डी, बास्किट बॉल और बॉलीबॉल का जमाना आ गया है। उसके भी आई.पी.एल. हो रहे हैं। अभी कबड्डी के आई.पी.एल. हुए आपको मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश का अजय ठाकुर नामक लड़का है उसने कितने पैसे कमाए। तो यह जो इन्होंने सभी स्कूलों में पी.ई.टी. और डी.पी.ई. लगाने का फैसला किया है, इसके रिजल्ट्स बाद में आएंगें और इनके लगने से प्लेयर्ज़ का भविष्य संवरेगा। सरकारी स्कूलों में बहुत बच्चे पढ़ते हैं। भाई हंस राज जी बैठे हैं। इनके तीसा के गवर्नमैंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल में लगभग 1100 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैरा में 700 बच्चे हैं तो यह एक बहुत पॉज़िटिव फैसला है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी इस बजट में एक बहुत अच्छी स्कीम ले कर आए हैं। हमारे समाज में पिछले 10 वर्षों से डिस्पेरिटी फील की जा रही थी। एक वर्ग महसूस कर रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और वह जनरल केटैगरी है। जनरल केटैगरी में जो बी.पी.एल. परिवार हैं, उनके लिए भी मकान के लिए इस बार 75 हजार रु0 मिलेंगें तो जो यह असमानता एक वर्ग फील कर रहा था और हम भी विधान सभा में चर्चा करते थे कि गलत हो रहा है, इस बार मुख्य मंत्री जी ने इस चीज़ का समाधान कर दिया है और यह बहुत अच्छा फैसला है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

17.03.2016/1505/केएस/एएस/2

अध्यक्ष महोदय, मज़दूरी 180 से बढ़ाकर 200 रुपये की गई है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। होम गार्डज़ के जो आपने 280 रु से 300 रुपये बढ़ाए हैं, यह भी सराहनीय कदम है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2016/1510/av/dc/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल)क्रमागत

इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के तेवर उस तरह के नहीं लग रहे जिस तरह के लोक सभा के चुनाव के बाद लग रहे थे। लोक सभा चुनाव जीतने के बाद जब हमारा यहां पर सैशन हुआ तो उस वक्त इनके तेवर इस तरह के थे जैसे कि हम एक महीने के बाद विपक्ष की तरफ और ये लोग सत्ता पक्ष में बैठेंगे। मगर वह तेवर आहिस्ता-आहिस्ता डेढ़-दो साल के बाद ठंडे हो गये हैं। अब ये लोग चुपचाप बैठ गये हैं। अब मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं। यहां कांगड़ा से जो एम0पी0 बनें उनका वहां पर नारा होता था कि 'मेरा एक सपना है, मुझे पठानकोट की लाइन को ब्रॉडगेज बनाकर लेह तक ले जाना है।' अरे! उसका क्या हुआ? (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य (श्री रिखी राम कौंडल जी को कहा।) जब आप बोल रहे थे तो इन्होंने बीच में आपको नहीं टोका। आपकी तरफ से जब कोई सदस्य बोलेंगे तो इसका जवाब दे देना। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। जब आप बोलेंगे इस बारे में तब बोलना।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने उनका नाम नहीं लिया। वहां से जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा कि मैं रेलवे को लद्दाख तक पहुंचाऊंगा। क्या हुआ? केवल सर्वे, सर्वे और केंद्र सरकार ने हाथ में केवल झुनझुना दे दिया। (---घंटी---) अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। आजकल तो वह बंद है। दूसरे देशों में बड़े-बड़े मेनेजमैंट कर दिए गए। दूसरे देशों में एक महीना पहले लोग इवैंट को मेनेज करने

जाते थे। पता नहीं वहां उन देशों में इवैंट मेनेज करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपये लग गये। मेरे ख्याल में मेक इन इंडिया तो खत्म हो गया। हमारे जो वित्त मंत्री हैं वह अपील कर रहे हैं कि आप घबराओ मत और भारत में इनवैस्ट करो। मगर यहां कोई नहीं आ रहा है। यहां पर बेरोजगारी भत्ते के ऊपर बातें हो रही थी तो मैं यह कहना चाहता

17.3.2016/1510/av/dc/2

हूं कि हमारी सरकार कौशल भत्ता दे रही है। हमारी सरकार अभी डेढ़-दो साल और रहेगी। हमारे मुख्य मंत्री जी में क्षमता है तथा ये अभी और ज्यादा पैसा बढ़ायेंगे। यहां पर सुरेश भारद्वाज जी कह रहे थे कि युवाओं को बेवकूफ बनाया गया। अरे! हमारी पार्टी ने कोई बेवकूफ नहीं बनाया मगर आपने तो देश की जनता को इतना गुमराह किया कि आपकी पार्टी की सरकार के दिल्ली में बैठते ही लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपये आ जायेंगे। वह अच्छे दिन कहां चले गये?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) : हमारे प्रदेश में जैसे गोविन्द सागर, पौंग डैम तथा कोल डैम है वहां पर मछली पालन से हमारे हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। हमारे जो छोटे-छोटे नाले और खड्डे हैं जिनमें सारा साल पानी रहता है उनमें कई बार ऐसा हो रहा है कि माइग्रेटरी लेबर्ज घास पर छिड़कने वाला जहर ले आते हैं और उसको पानी में घोलकर उसमें मछलियां मारते हैं। जिससे पानी में मछलियां मर जाती है और वह खत्म हो जाती है। हमारे वे नौजवान जो कम पढ़े-लिखे हैं और यह काम कर सकते हैं उनके लिए उन नालों में दो-दो किलोमीटर करके दिया जाए

टी सी द्वारा जारी

17.03.2016/1515/TCV/DC/1
श्री मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल)

और मछलियों का बीज डाला जाये तथा बरसात खत्म होते ही उन खड्डों और नालों को आबंटित कर दिया जाये। ताकि वे नौजवान अपना रोज़गार उन खड्डों से कर सकें। इससे छोटी-छोटी मछलियां ज़हर से मरने से भी बच जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय न्युग्ल खड्ड आपके ही इलाके में है। इस खड्ड के बारे में मैं चाहता हूं कि जैसे ऊना में तटीकरण हो रहा है, इसका भी तटीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि हमारी 50-60 पीने के पानी की स्कीमें व सिंचाई की स्कीमें चली हुई है,उनका भी तटीकरण किया जाये। आपने मुझे इस बज़ट भाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बज़ट का जोरदार समर्थन करता हूं।

17.03.2016/1515/TCV/DC/2

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार, समय का ध्यान रखे अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो 2016-17 का बज़ट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, हमें भी इस सदन में लगातार 14 वर्ष चर्चा में भाग लेते हुए हो गए हैं। जब हम पहली बार आए थे अगर हम उस समय के मुख्य मंत्री जी का बज़ट और आज का बज़ट देखें तो पेजों में अन्तर जरूर है परन्तु कोई नीतिगत फैसले जो सरकार को लेने चाहिए इसमें नहीं लिए गए है। प्रदेश आत्मनिर्भर बनना चाहिए और प्रदेश के अन्दर जो लगातार कर्ज़ बढ़ता जा रहा है, उसकी रिसोर्स मोबेलाइजेशन करके उसको कम किये जाने की जरूरत है। इस बज़ट में हम कोई बड़ा विज़न नहीं दे रहे हैं। हम लगातार एक कर्ज़ को भरने के लिए दूसरा कर्ज़ उठाए जा रहे हैं और जब तक 2017 में ये सरकार जाएगी उस समय तक यह कर्ज़ 50 हजार करोड़ रूपये तक पहुंच जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात कही कि 'पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी' लेकिन इस बज़ट में ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है कि हम नौजवान को खेत तक पहुंचा सकें। हम अगर एक-एक विभाग की समीक्षा करें तो कोई विज़न उसमें नहीं दिखता है। आज इस प्रदेश के अन्दर जो सबसे बड़ा चिन्ता का विषय है और वह यह है कि आजादी के बाद हम हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखे तो 90 प्रतिशत लोग अभी भी गांव में रहते हैं। कुछ न कुछ उसकी लैंड

हॉर्डिगं है और धीरे-धीरे यह लैंड हॉर्डिंग कम होती जा रही है। हमारी जो कृषि पर निर्भरता थी वह भी कम होती जा रही है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

हमारी जो जी0डी0पी0/प्रदेश की आय हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से मिलता था आज वह भी कम होता जा रहा है और

श्री गर्ग जी ---- द्वारा जारी

17/03/2016/1520/RG/AS/1
श्री वीरेन्द्र कंवर----क्रमागत

उसका एक तो सबसे बड़ा कारण हम बेसहारा पशुओं को ले रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम जो कहते हैं कि पशु धन है, बहुत बहुमूल्य पशु धन था जिसको हम घरों में रखते थे और वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब तूड़ी 10/-रुपये किलो पड़ रही है और पशु रखना आम-आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। हम बेसिक बात पर क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं इसके लिए कोई नीति बनाते? अगर हम आज भी गांवों में प्रत्येक घर में जाएं, तो 5-5 या 6-6 पशु लोगों ने रखे हैं, लेकिन यदि दूध की बात आए, तो दूध पैकेट का सुबह जाकर लाते हैं और उससे चाय बनाते हैं। हम उनको क्यों नहीं प्रेरित कर पाए? हमारे पास पशु पालन विभाग इतना बड़ा विभाग है। हमने हर पंचायत स्तर पर डिसपैन्सरी भी खोल दी और क्यों नहीं हम उनकी नस्लों में सुधार कर पाए कि हम लोगों को प्रेरित करें कि जो चार पशु उन्होंने रखे हैं, वे दुधारू हों। भारतीय मूल का जो पशु धन है, हम उसमें क्यों संबर्धन नहीं कर पाए? हमें इसके लिए कोई नीति लानी चाहिए। लोगों ने हमें फौलो किया है। विदेशों में आज हमारी भारतीय मूल की गऊ को ले जाकर चाहे वह राठी है, गीर है या चाहे वह सायवाल जाति की है, उनकी नस्लों में उन्होंने बढ़ौत्तरी की है। आज जो 8-8 लीटर दूध देने वाली गऊएं हैं, वे 28-28 लीटर दूध दे रही हैं। उन्होंने रिसर्च की कि जो जर्सी गाय का दूध है, इससे कैंसर में बढ़ौत्तरी हो रही है, शरीर में विभिन्न बीमारियों में बढ़ौत्तरी हो रही है। इस जर्सी गाय के साथ न तो दूध पीने वाले का लगाव है और न रखने वाले का लगाव है और

यह जर्सी नसल वास्तव में विदेशों में दूध के लिए बनाई गई थी और बाद में इसका मास खाने के काम आता था। वास्तव में यह गाय का रूप नहीं है। भारतीय मूल की जो देशी गाय है, हमारी कृषि उसी के ऊपर आधारित थी। लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। हमारी विदेशी नसलों से पता नहीं हिन्दुस्तान के लोगों को बहुत प्यार रहता है। हमने इन विदेशी नसलों को यहां प्रोत्साहित किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, यहां माननीय मंत्री बैठे हैं, इनसे कहूंगा कि इस बारे में कोई नीति लाइए और अगर आप कोई नीति इसके लिए बनाएंगे, तो बाहर से भी अन्य प्रदेशों से पशु धन लाकर यहां लोगों को प्रेरित करिए। इस काम के लिए कोई योजना या प्रोजैक्ट बनाकर शुरूआत करें।

17/03/2016/1520/RG/AS/2

आज हिमाचल प्रदेश जैसा जहां 90% लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन जब दूध की बात आती है, तो हम बाहर से लाते हैं।

यही हाल हमारा कृषि में है। यहां हमारे कृषि मंत्री महोदय बैठे हैं। बेशक ये गांव के हैं और कृषि का बहुत अच्छा अनुभव इनको है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनकी भी कोई इच्छा हो। आज अगर आप गांव में जाएं, तो पूरा-का-पूरा कृषि विभाग और आप भी इस बात से सहमत होंगे, सिवाय बीज बांटने के उनका कोई दूसरा काम नहीं है, कोई दूसरा काम वह नहीं करता। हमें तो कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि कृषि विभाग के लोग कभी गांव के अंदर आए हों और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया हो कि आपके यहां नाले में पानी बह रहा है आप इस पानी को उठाकर किस तरह खेत तक पहुंचाइए या यहां आप इस किस्म का बीज पैदा करिए। कभी प्रेरित नहीं किया। यही काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, मात्र पौधे बांटने और कमीशन खाने का काम है। इसके सिवाय कोई अन्य काम इनके पास नहीं रह गया । कभी हॉटिकल्चर इंस्पैक्टर नहीं गए। माननीय मंत्री जी आप इस बारे में कोई नीति बनाइए, आंखें बंद मत कीजिए, कोई नीति बनाइए। जो ऐग्रीकल्चर इन्सपैक्टर्ज जिनको आप लाखों रुपये दे रहे हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1525/MS/DC/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी-------

उनको जहां पर वे पोस्टिड हैं अगर वे ब्लॉक हैडक्वार्टर पर है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सरकारी जमीन है। जैसे कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग सेंटर्ज बने हैं, आप ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर बनाइए। जब आप वहां ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे तो लोग भी देखेंगे कि इस तरह का अनाज और पौधा यहां पैदा हो सकता है। -(व्यवधान)- अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप रिजाइन कर दो। आप शुरुआत तो कीजिए। प्रो0 धूमल जी ने भी शुरुआत की थी। पहले विभाग गांव-गांव के अंदर लोगों को कहता रहा कि यूरिया डालो, यूरिया डालो, पेस्टिसाइड डालो, पेस्टिसाइड डालो और अब कहते हैं कि बन्द करो, बन्द करो। अरे, अपनी कोई नीति तो बनाओ कि आज किसानों/नौजवानों को हम खेत तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हमारी छोटी-छोटी लैण्ड होल्डिंग्ज हैं। वहां पर कुछ हॉर्टिकल्चर के माध्यम से और छोटे-मोटे ग्रीन हाउस के माध्यम से एग्रीकल्चर का हो सकता है। इसके अलावा कुछ सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन का भी कर सकते हैं। हम इन सभी चीजों को तय और इकट्ठा करके प्रत्येक नौजवान को खेत की ओर ले जा सकते हैं। हम तीन वर्ष तक इसकी चर्चा करते रहे और अब तीन वर्ष के बाद कह रहे हैं कि सोलर फैंसिंग खेतों तक लगाएंगे। अच्छी बात है, चाहे इसकी शुरुआत आपने की लेकिन अगर आप कनार्टक, केरल और दूसरे प्रदेशों में जाकर पता करें तो ये ट्रायल वहां फेल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने शुरुआत की -(व्यवधान)- मैं आपको (श्री नीरज भारती, मुख्य संसदीय सचिव)नहीं पूछ रहा हूं। मैं चैयर को एड्रेस कर रहा हूं। आप जिम्मेदार मुख्य संसदीय सचिव है। आप बैठिए, आप चुप रहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। आप तीन वर्ष तक यह पता नहीं कर पाए कि कितनी गौ-शालाएं एन0जी0ओज0 चला रहे हैं। उनकी क्या स्थिति और वित्तीय स्थिति क्या है। अगर वे अच्छी तरह से काम कर रही हैं तो आप उन एन0जी0ओज0 को बढ़ोत्तरी दीजिए। तीन वर्षों में हम सिर्फ एक गोधन जो सड़कों में आवारा घूम रहा है, उनको स्थान नहीं दे पाए? मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन रहेगा कि आप सभी विधायकों की बैठक

17/03/2016/1525/MS/DC/2

इसके लिए कीजिए और सभी से सुझाव लीजिए फिर उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाइए। जब हम अगले साल यहां चर्चा करेंगे तो कम-से-कम एक बात की तसल्ली तो होगी कि बेसहारा पशु ठीक स्थान पर पहुंच चुके हैं। जो हमने पशुधन की गणना शुरू की है, वह करें लेकिन उसमें सभी पशुओं की गणना करने की जरूरत नहीं है। उसमें गाय और बैलों की ही गणना जरूरी है जिनको लोग छोड़ रहे हैं और जिनसे हमारे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर आप ऊना के थानाकलां के पास देखेंगे तो बड़ी-बड़ी गायें लोगों ने पाली हुई हैं जबकि हिमाचल प्रदेश के लोग इतनी बड़ी गाय रखते नहीं हैं। सारी गायें बॉर्डर और पंजाब के क्षेत्रों से हमारे एरिया में आ रही हैं। मैं समझता हूं कि वहां पर भी कानून बनाकर कोई रोक लगाई जानी चाहिए ताकि हम इस समस्या से निपट सकें।

उपाध्यक्ष जी, सबसे बड़ी समस्या आज जो हमारे लिए हैं, वह यह है कि हमने जिस युवा, सेवाएं एवं खेल विभाग का गठन 1982 में किया था आज स्थिति क्या है? आज जिला ऊना की ही बात ले लूं। वहां सिर्फ एक खेल अधिकारी के सिवाय आज उस ऑफिस में चपड़ासी की भी पोस्ट नहीं है। आज बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डोर स्टेडियम माननीय धूमल जी के समय में वहां पर बना,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

16.03.2016/1530/जेएस/एएस/1

श्री वीरेन्द्र कंवरः----**जारी**------

वहां पर वुडल फ्लोरिंग हुई। पिछले दिनों माननीय पी0ए0सी0 कमेटी भी उसको देखने के लिए गई। वहां पर इंडोर गेम्ज़ हो सकती हैं। वहां पर इन्टर नेशनल लैवल की गेम्ज़ हो सकती हैं, लेकिन वहां पर ऊपर से पानी टपक रहा है। सारी की सारी वुडल फ्लोरिंग नीचे खराब हो रही है। उसके रख-रखाव के लिए वहां पर स्टॉफ नहीं है। पिछली सरकार ने माननीय धूमल जी की सरकार ने चार करोड़ रूपए वहां एस्ट्रोट्रफ के लिए स्वीकृत किया। आप हैरान होंगे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका उदघाटन भी किया। वहां पर जो

उदघाटन किया और विपरीत दीशा में एस्ट्रोट्रफ बना दिया। सबसे पहली खामी उसकी यह है। वहां पर किसी ने बैठ करके मैच देखना है उसके लिए भी वहां पर जगह नहीं है। जो एस्ट्रोट्रफ डाला वह टुकड़े-टुकड़े में डाला। जैसे कि उस ठेकेदार के पास उस एस्ट्रोट्रफ के कुछ पिसिज़ बच गए थे और वहां पर जोड़ दिए। कीमत कितनी 4 करोड़ रुपए। पी0ए0सी0 कमेटी ने उसका संज्ञान लिया विभाग को भी बुलाया। लेकिन आज तक वहां पर कुछ भी नहीं हो पाया है। एस्ट्रोट्रफ ऊना में और कोच शिमला में बैठा हुआ है। वह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम देख रहा है। उसको वहां पर होना चाहिए। वहां पर स्पोर्ट्स होस्टल में 15 बच्चे दाखिल कर लिए, लेकिन कुश्ति का कोच कहां शिमला में। आज यह स्थिति हमारे खेलों की है। आज यही हालत सिंथैटिक ट्रैक्स ऐथेलेटिक्स के हमीरपुर में, धर्मशाला में, लेकिन वहां पर कोच नहीं है। ऊना में बहुत बड़ा टेलैंट हॉकी का रहा है। मेज़र ध्यान सिंह मैमोरियल टूर्नामैंटस वहां पर होते हैं। वहां हर वर्ष होते हैं। उसमें पहला नम्बर ऊना का आता है। वहां से पदमश्री श्री चरण सिंह जी हुए। जिन्होंने वर्ष 1962 में गोल्ड मैडल जीत करके इंडिया के लिए ले कर आए थे। वहां से दीपक ठाकुर हुए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हॉकी का कोच भी सरकार वहां पर नहीं दे पाई। धर्मशाला में सिंथैटिक ट्रैक है। वहां पर भी कोच नहीं है। यह हालत इस खेल विभाग की है। हम ग्रांट बढ़ा रहे हैं। आज वही हाल बॉलीबॉल में है। धूमल जी ने 15 लाख रूपया धर्मशाला के लिए दिया, 15 लाख रूपया ऊना के लिए दिया और 15 लाख रूपया

16.03.2016/1530/जेएस/एएस/2

शिमला के लिए दिया ताकि यहां पर भी एस्ट्रोट्रफ बिछाई जाए। आजकल जितने भी मैचिज़ होते हैं वे इन्टर नेशनल स्तर पर जो फैसिलिटी है ऐस्ट्राट्रफ के ऊपर ही होते हैं। सिंथैटिक ट्रैक के ऊपर होते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है खेल विभाग के अन्दर।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने ग्रांट-इन-एड बढ़ाई राज्य स्तर के ऊपर जो खेल संघ है हम उसके लिए देते हैं और एक लाख रूपया देते हैं। लेकिन आजकल उसमें भी राजनीति हो रही है। उसमें भी खेल संघ को वह

ग्रांट-इन-एड नहीं दी जा रही है। उसको जो सब-जुनियर टीम भेजनी होती है उसमें सब-जुनियर ब्वॉयज, गर्ल्ज़ और सीनियर ब्वॉयज, गर्ल्ज और स्टेट चैम्पियनशिप उसको करवानी होती है। मुझे जो थोड़ी-बहुत जानकारी बॉलीबॉल में है कम से कम 20-25 लाख रूपए का खर्च हर साल उस खेल संघ को करना होता है। लेकिन हम क्या दे रहे हैं। हम उसको कोचिंग की फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं। उसने जब ट्रॉयल लिया, जब चैम्पियनशिप की तो जो जिला की टीम बनी, प्रदेश की टीम बनी हमने उसको भेजना है। जब उसको भेजना है तो कम से कम उसको आने-जाने का टी0ए0/ डी0ए0 देना पड़ेगा। उसको किट देनी पड़ेगी। कम से कम 50 हजार रूपए एक टीम भेजने का खर्चा आता है। उसको 10-15 महीने कोचिंग भी देनी है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

17.03.2016/1535/SS-AS/1

श्री वीरेन्द्र कंवर क्रमागतः

लेकिन आज स्थिति क्या है? आज हम यह सब कुछ नहीं दे पा रहे। इसका एक कारण है। हमारे स्कूल स्तर के जो खिलाड़ी हैं कभी 1947 के बाद हमने सोचा है कि हम स्कूल स्तर पर गेम्ज़ करवाते हैं लेकिन जब बच्चा नौंवी, दसवीं पास कर जाता है जोकि खिलाड़ी है फिर वह कहां जायेगा? उसने अपना कैरियर बॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल में चुना है लेकिन उसके बाद वह कहां जायेगा? उसके बाद यहां पर कोई स्पोर्टस कॉलेज नहीं है। यहां पर कोई स्पोर्टस यूनिवर्सिटी नहीं है। लम्बे समय तक अगर उसे औलम्पिक में जाना है, दूसरे अन्य खेलों में जाना है, अन्तर्राष्ट्रीय एशियाई खेलों तक पहुंचना है तो उसके लिए संस्थान नहीं है। हमारे बच्चों के अंदर वह कैपेसिटी और लियाकत है लेकिन आज वह सारी लियाकत/हुनर पलायन हो रहा है। आज वह बी0एस0एफ0 में जा रहा है। आर्मी में जा रहा है। पंजाब के लोग उसको ले जा रहे हैं। रेलवे वाले उसको ले जा रहे हैं। हमारे यहां सिरमौर से खली हुआ। वह यहां झूठे बर्तन मांजता था। लेकिन पंजाब का कोई अधिकारी आया और उसे लेकर चला गया। आज अगर फ्री स्टाईल कुश्ती में किसी का नाम है तो आज अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खली का नाम है। इस तरह से चाहे कोई छोटा

विभाग है या बड़ा विभाग है हमको एक दूरगामी सोच अपनानी होगी। आज होता क्या है? आज हम खेल के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आई0पी0एल0 हो रहा है। हिन्दुस्तान में अगर धर्मशाला के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवैंट मिला था, हमने वह भी मौका खो दिया। आज हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। हम चाहे जिस तरह का बजट रख दो जब तक हमारे अंदर प्रण शक्ति नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस बजट के अंदर भी कोई प्राण शक्ति नहीं है। आज हम भले ही पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले नम्बर पर हैं लेकिन हम छाती पर हाथ रखकर नहीं कह सकते कि हम बढ़िया सेवाएं हिमाचल के अंदर दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं हर बार वह बात प्रश्न के माध्यम से या चर्चा के माध्यम से इस माननीय सदन में रखता हूं कि हमारे 68 विधान सभा क्षेत्र हैं और 68 विधान सभा क्षेत्र के अंदर आप कम-से-कम एक हैडक्वार्टर के ऊपर स्वास्थ्य सेवाओं को स्ट्रैंथन कर दो। वहां पर आप एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, एम0आई0आई0 उपलब्ध करवाओ। वहां पर गाईनाकोलोजिस्ट ज़रूरी है। आप लक्ष्य रखते हैं कि 100 परसैंट गवर्नमैंट हॉस्पिटल डिलीवरीज़ होनी चाहिए। महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करने जा

17.03.2016/1535/SS-AS/2

रहे हैं, उनका सशक्तिकरण करने जा रहे हैं लेकिन वास्तव में आज हमारी स्थिति क्या है। आज हैडक्वार्टर के ऊपर भी डॉक्टर्ज़ नहीं हैं। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हो रही है लेकिन ईमानदारी के साथ बढ़िया कोशिश होनी चाहिए। एक नीति बना करके हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैंने कहा कि आज हम नौजवान को खेत तक नहीं पहुंचा पा रहे। मैंने पिछली बार कहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर ट्यूबवैल के माध्यम से सिंचाई हो सकती है। हमने वहां पर ट्यूबवैल लगवाए। लेकिन जहां पर ट्यूबवैल के माध्यम से सिंचाई नहीं हो सकती वहां के लिए रेन हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने शुरू किये। आज आप देखेंगे कि अगर ऊना से चलेंगे तो समूर खड्ड के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रेन हारवैस्टिंग के लिए बन रहा था। 20 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च होना था। अभी मेरा क्षेत्र चिन्तपुरनी में चला गया, वह गारनी खड्ड पर बनना था, उसकी 15 हजार कैनाल जमीन सिंचित होनी थी। लेकिन हुआ क्या? सरकार चली गई। जो काम जहां पर था वहीं पर खड़ा है। अब कौन जिम्मेदार है? 20 करोड़ रुपया जिससे आज सिंचाई होनी थी, अब कहते हैं कि 20 करोड़ और लगेगा। हमने अब उसे प्राथमिकता डाला है। 20 करोड़ से वह स्कीम बननी थी, आज खेतों तक पानी पहुंचना था वह नहीं पहुंचा। इसके लिए कौन

अधिकारी जिम्मेवार हैं? क्यों नहीं यहां पर वर्क कल्चर की रिस्पोंसिबिलिटी पैदा की जाती? मंत्री जी से पूछें कि कल क्या उत्तर आ रहा था? यहां से माननीय सदस्य ने विषय को रखा तो बताया कि 200 टैंक बने और 190 टूटे हुए।

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1540/केएस/एएस/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी---

वे लीक कर रहे हैं और कह रहीं थी कि यह तो ऐसा है न मैंने बनाए न आपने बनाए। अरे, यह कोई उत्तर नहीं है। मैडम, इन्क्वायरी करवाईए क्यों उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बचा रहे हैं जिन्होंने वहां पर बेईमानी की है? क्यों हम यह काम नहीं कर पा रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आज जमाना बदल गया है। आज भी हम सोचें कि हमारा यह जो देश था, हमारा यह जो देश है, हमारे साथ जापान जैसे देश आजाद हुए थे और उनकी आज अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, सबको मालूम है। पिछले दिनों मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि जापान के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई, समुद्री तुफ़ान आया और परमाणु रिएक्टर लीक हो गए। सुनामी आई और वहां पर सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया लेकिन जापान जो हिन्दुस्तान को स्वां प्रोजैक्ट के रूप में मदद करता था, हमारे अधिकारियें ने वहां पर फोन किया कि क्या यह आगे भी चलेगा तो उन्होंने कहा कि यह हमारी कमिटमैंट है और चाहे सारे का सारा जापान भी तबाह हो जाएगा हमने जो कमिटमैंट की है, उसको हम पूरा करेंगें। उनकी विदेशों ने सहायता करनी चाही लेकिन उन्होंने सहायता लेने से इन्कार कर दिया। नेता सुभाष चन्द्र बोस जी का वाक्य मुझे याद आ रहा है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट में वाइंड अप करें।

श्री वीरेन्द्र कंवरः ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय। वह वाक्य मुझे याद आ रहा है कि एक बच्चा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह बौद्ध मंदिर से आ रहा था। नेता जी ने पूछा कि अगर यह बौद्ध आपके देश पर आक्रमण कर देगा तो आप क्या करेंगें?उसने कहा कि इस भगवान के खिलाफ सबसे पहले बन्दूक मैं उठाऊंगा। ऐसी राष्ट्रभक्ति आज इस देश के अंदर चाहिए। आज हो क्या रहा है? आज जे.एन.यू. में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं । भारत को तोड़ने का षडयंत्र रचा जा रहा है। यहां भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी और हमारे नेता उसको सपोर्ट करने के लिए जे.एन.यू. में जा कर खड़े हो रहे हैं? ...(व्यवधान).... इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मेरा यह कहना है कि चाहे पक्ष के साथी हो या विपक्ष के साथी हों, जहां

17.03.2016/1540/केएस/एएस/2

पर राष्ट्र की एकता का विषय हो, हम सबको एक होना है। जब तक राष्ट्रीयता का भाव हम सबमें नहीं आता, हम राष्ट्र के लिए नहीं सोचते, तब तक काई भी नीति इस देश के अंदर कारगर नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद और मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने जो कुछ बिन्दुओं पर चर्चा की, मैं केवल उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई। इन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर ब्रीडिंग पॉलिसी नहीं है। मैं मानता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जो स्ट्रे कैटल की बढ़ौत्तरी हुई है, वह प्रदेश के अंदर ब्रीडिंग पॉलिसी न होने के कारण भी हुई है। इसलिए प्रदेश के अंदर हमने यह पॉलिसी तैयार कर दी है। इस पॉलिसी के अंदर हम जो हमारी रैड सिंधी जैसी इंडियन ब्रीड है, उसको क्योंकि प्रदेश के अंदर लोअर लैवल भी है, प्लेन एरिया भी है, मिड हिल्ज़ भी हैं और हाई हिल्ज़ भी है तो इसके मध्यनज़र प्रदेश के अंदर हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी तैयार है और इस पॉलिसी के ऊपर हमने किस हाईट पर क्या रखना है, रैड सिंधी साहिवाल, क्रॉस ब्रैड, इसको मध्यनज़र रखते हुए हमने प्रदेश के अंदर ब्रीडिंग पॉलिसी

तैयार कर दी है और एक बात इन्होंने फीड एण्ड फोडर की बढ़ौत्तरी के बारे में कही । इसके भी हम प्रयास कर रहे हैं कि फीड और फोडर को भी प्रदेश के अंदर बढ़ाया जाए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2016/1545/av/as/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ---------क्रमागत

यहां पर चर्चा उठाई थी कि प्रदेश के अंदर हमारी मिल्क की प्रक्योरमैंट प्राइस कम है। हम जो मिल्क प्रक्योर करते हैं वह टू ऐक्सिज के ऊपर करते हैं, फैट एस0एन0एफ0 के ऊपर करते हैं। हमारे प्रदेश में गाय की फैट साढ़े चार प्रतिशत तक आ सकती है मगर उसकी एस0एन0एफ0 हम साढ़े 8 प्रतिशत के ऊपर प्रक्योर करते हैं। मैंने इसके ऊपर काफी काम करने का प्रयास किया और हमारे प्रदेश में यह 7.2 प्रतिशत से ऊपर नहीं है। हम साढ़े 8 प्रतिशत एस0एन0एफ0 लेते हैं परंतु 7.2 प्रतिशत से ऊपर हमारी एस0एन0एफ0 नहीं है। हम इस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारा एस0एन0एफ0 साढ़े आठ प्रतिशत क्यों नहीं है। हम दूध की कीमत तब तक नहीं दे पायेंगे जब तक इसमें एस0एन0एफ0 साढ़े 8 प्रतिशत न हो। विभाग इसको चैक करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हमारे फीड में कमी है। इसी प्रक्रिया में हमारी मिल्क फैडरेशन पिछले पांच वर्षों में लगातार घाटे में चली। इस वक्त हमारी मिल्क फैडरेशन इन तीन सालों के अंदर लगभग 19 करोड़ रुपये के लाभ में है और पिछले पांच सालों में लगभग 911 लाख रुपये घाटा था। उसके बावजूद भी हम इन तीन सालों में 9.92 करोड़ रुपये के लाभ में जा रहे हैं। हमारी मिल्क फैडरेशन प्रदेश के मिल्क प्रोड्यूसर को पहली बार एक करोड़ रुपये बोनस दे रही है। यह आज तक पहले कभी नहीं हुआ। हम दूध की बढ़ोतरी के लिए इस प्रकार के पग उठा रहे हैं और जो आप लोगों ने सुझाव दिए वह भी अच्छे हैं। मैं यहां इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि यह

विभाग पहले पूर्व मुख्य मंत्री जी के पास रहा और उस वक्त इम्पोर्टिड सीमन आए। जब वह सीमन लगे और उनके रिजल्ट आए तो क्योंकि चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग है या पशु पालन विभाग; इसमें धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। सीमन तो इम्पोर्टिड था मगर जब रिजल्ट आए तो मैं भी बछड़ी को देखकर हैरान हो गया कि यह ब्रीड कहां से आ गई। वह इम्पोर्टिड सीमन उत्तराखंड से लाया गया। उसमें हलॉस्टिन ब्रीड की 5000 स्ट्रॉ और जर्सी गाय की 15000 स्ट्रॉ आई। यह विभाग पूरे पांच साल पूर्व मुख्य मंत्री धूमल जी के पास रहा और मैंने यह पता लगाने का प्रयास किया कि किसके

17.3.2016/1545/av/as/2

माध्यम से इम्पोर्टिड सीमन आए। बाद में पता चला कि ये सीमन उत्तराखंड से आए हैं और इसमें कहीं-न-कहीं गड़बड़ हुई है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सीमन डायरैक्ट इम्पोर्ट करेंगे। हम सीमन को ऐम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट टैक्नोलॉजी के माध्यम से लायेंगे। यहां पर एक प्रश्न आ रहा था और हमारी वरिष्ठ सदस्या ने आज सुबह उस पर चर्चा की है। यहां पर इलैक्ट्रिक फैंसिंग की बात की गई। मैं यहां पर इसलिए कहना चाहता हूं कि क्योंकि एक दिन मैं और मुख्य मंत्री जी अनाडेल से कांगड़ा जा रहे थे। मैंने उनसे इस बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा कि अगर हम वानरों की नसबंदी करते हैं तो इसमें बहुत समय लगेगा और हम इस बारे में जनता को क्या परिणाम दे पायेंगे। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं। मैं भी बागवानी करता हूं। मेरे बागीचे के साथ पूरा जंगल है। वहां पर कभी भालू आ जाते थे और हमारे सेब तोड़ देते थे। कभी वहां पर आवारा जानवर घुस जाते थे इसलिए मैंने जंगल की साइड से क्रेट फैंसिंग करवाई। जब क्रेट फैंसिंग हो गई तो देखा कि कुछ समय बाद हजारों की संख्या में बंदर अंदर आने शुरू हो गये। मैं इस चीज को खुद देखता हूं और मैंने कहा कि इन बंदरों को कैसे हटाया जाए। मैंने उसके लिए प्रयास किया क्योंकि मैं जब अब्रोड घूमता था तो देखता था कि जितने भी हाई-वे हैं वहां साइडों में इलैक्ट्रिक फैंसिंग की हुई है। वहां पर हाई-वे के साथ बड़े-बड़े, हजारों किलोमीटर में पाश्चर्ज हैं। हम तो यहां पर घास काटते हैं मगर वहां पर लेबर की कमी से

बड़े-बड़े पाश्चर्ज बनाए हुए हैं। उनकी रखवाली के लिए वहां हाई-वे के साथ इलैक्ट्रिक फैंसिंग की हुई है और उसमें माइल्ड सा कंरट पास किया हुआ है।

टीसी द्वारा जारी

17.03.2016/1550/TCV/AS/1

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री --- जारी।

जो जानवर वहां चरते हैं वे धीरे-धीरे एक पॉस्चर से दूसरे पॉस्चर की तरफ जाते रहते हैं और उस इलैक्ट्रिक करंट की वज़ह से कभी हाईवे के पास नहीं आते। आपके लिए आज शायद ये नई बात है लेकिन मैंने इस बात को तब परखा जब मैंने 2 इलैक्ट्रिक वॉयर अपने बगीचे में लगाई और वह ऐसा सिस्टम है कि अगर आदमी हाथ लगाये तो दो तारे जुड़ते ही ट्रीप कर जायेगी और वह सिस्टम ऐसा कामयाब हुआ कि जब बन्दर आये और वह ऊपर चढ़ने लगे और जैसे ही उन्होनें तार को छुआ तो उन्हें करंट लगा और तब से आज तक 6 साल का समय हो गया है बन्दर आते है और सड़क में ही बैठते हैं लेकिन तार को हाथ नहीं लगाते। बन्दरों ने अपनी भाषा में कुछ ऐसी बात कही होगी कि आज 6 साल हो गये मैंने वहां कोई करंट नहीं लगाया लेकिन बंदर कभी भी मेरे बगीचे में नहीं आते हैं। आप भी वहां जाइये और देखिए। ये मैंने प्रैक्टिकल बात कही है। ये स्कीम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों/बागवानों के लिए दी है। इस तरह की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर को पैसा दिया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि मनरेगा और कंवर्जन्ज के अन्दर हम मिल बैठ करके इसको प्रदेश के अन्दर चला सकते हैं। इसलिए यह एक बहुत अच्छी योजना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

17.03.2016/1550/TCV/AS/2

श्री मनोहर धीमानः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 8 मार्च को इस मान्य सदन में जो बज़ट पेश किया था मैं उसमें चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। बज़ट तो वाकई

काबिले तारीफ है लेकिन पहले में माननीय मुख्य मंत्री जी को इस चीज की बधाई देता हूं कि इस उम्र में भी उन्होनें साढ़े तीन घण्टे खड़े होकर बजट भाषण पढ़ा, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। यह बज़ट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे पहले मैं विधायक निधि की बात करूं जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी विधायक निधि 75 लाख रूपये से बढ़ाकर 1 करोड़ और स्वैच्छिक निधि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है। यही नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने पंचायत सदस्य से जिला परिषद के अध्यक्ष तक सबका मानदेय भी बढ़ाया। किसानों के बारे में यहां बहुत चर्चा हो रही है। ये जो बाड़ बन्दी की बात हो रही है, इसमें 60 प्रतिशत् अनुदान का जो प्रावधान किया गया है ये भी काबिले तारीफ हैं। किसानों के लिए बोर-बैल, कुंआ, जल संग्रहण टैंक और जल प्रवाह योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। सिंचाई हेतु अतिरिक्त 30 हजार एकड़ भूमि को सी0सी0ए0 में लाना, प्रदेश के सभी घरों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, घरेलू उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत बिजली उपलब्ध करवाना, सभी पंचायतों को मोटर योग्य सड़क से जोड़ना ऐसे कई कार्यों का प्रावधान किया है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में लगभग 1000 स्कूल नये खोले गये या अपग्रेड किए गए। 28 डिग्री कॉलेज खोले गए, स्वास्थ्य संस्थान 130 के करीब खोले गए,

श्री गर्ग जी द्वारा -----जारी

17/03/2016/1555/RG/DC/1

श्री मनोहर धीमान----क्रमागत

दैनिक दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाई गई, सात नए उप-मण्डल और 31 नई तहसीलें और उप-तहसीलें खोली गईं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी कड़ी में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं उनके बारे में इस माननीय सदन में बताना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगथ में एक उप-तहसील खोली गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का अपनी ओर से तथा अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। 20 स्कूल अपग्रेड किए गए। एक पी.एच.सी. खोली गई, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। दो 33 के.वी. के सब-स्टेशन खोले गए। इसके लिए मैं

माननीय ऊर्जा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक 108 करोड़ रुपये से औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का तो धन्यवाद करुंगा ही, विशेषकर मैं माननीय उद्योग मंत्री जी भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उसके लिए एक 25 करोड़ रुपये की किस्त भी जारी कर दी है और काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। श्री भरमौरी जी, माननीय वन मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे यहां दो विश्राम गृह भी वन विभाग ने खोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले प्रवास में हमारे यहां किसानों की समस्या को देखते हुए एक सब्जी मण्डी की भी घोषणा की है। डागला पंचायत में एक आयुर्वेद डिसपेंसरी की भी घोषणा की है। मुझे विश्वास हे कि इसका काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र पंजाब की सीमा के साथ सटा हुआ है और लगभग 60 किलोमीटर का क्षेत्र पंजाब की सीमा से लगता है। पंजाब के चार विधान सभा क्षेत्र इससे लगते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि वहां आजकल नशे का कारोबार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। मैंने पिछले सत्र में भी यह कहा था और सरकार ने अनुरोध किया था कि उसको समय रहते रोका जाए और वहां चौकसी बढ़ाई जाए, नहीं तो यह कारोबार शिमला तक पहुंच जाएगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक दिन छोड़कर एक नौजवान की इससे मौत हो रही है। मेरे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है और हमारे यहां जो सड़कें हैं, सब टूट-फूट गई हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसके लिए कोई विशेष

17/03/2016/1555/RG/DC/2

प्रावधान करके मेरे क्षेत्र में इनका सुधार किया जाए। इसका एक कारण और भी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्लू.डी. का केवल एक सब-डिवीजन है और साढ़े तीन सौ किलोमीटर की रोड है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां एक ऐग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्यालय खोला जाए ताकि सड़कों का रख-रखाव ठीक ढंग से हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अधिकांश छोटे-छोटे नाले और खड्डे हैं। मैं चाहता हूं कि उनका तटीयकरण किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र मेरे यहां है, वहां पहले भी काफी उद्योग

लगे हैं और एक नया क्षेत्र विकसित होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि वहां बिजली विभाग का एक डिवीजन भी खोला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्षेत्र पंजाब के साथ लगता है और वहां जो एरिया है, वहां सारी जमीन पंजाब पैटर्न की है और बहुत फर्टाइल एरिया है। वहां अनाज बहुत मात्रा में होता है और मेरे क्षेत्र का किसान भी बहुत मेहनतकश है। वह अनाज तो पैदा कर लेता है, लेकिन उसको मण्डीकरण के लिए पंजाब में जाना पड़ता है और वहां वह अपने आपको ठगा सा महसूस करता है। क्योंकि वह वहां अनाज छोड़कर आ जाता है और पैसे उसको किस्तों में मिलते हैं। जब जी चाहे व्यापारी पैसे देता है।

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1600/MS/DC/1

श्री मनोहर धीमान जारी-------

मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि वहां एक अनाज मण्डी खोली जाए ताकि किसानों को राहत मिले। मेरे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र में 12 पंचायतें ऐसी हैं जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। मैं इस मान्य सदन के माध्यम से सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 12 पंचायतों की सिंचाई सुविधा के लिए जैसे चंगर क्षेत्र में कोई प्रोजैक्ट लगा है, वहां एल0आई0एस0 की कोई स्कीम ऐसी बनें जिससे हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो।

उपाध्यक्ष जी, एक छौंछ खड्ड का कार्य पिछले दो वर्षों से चला हुआ है। यह लगभग 180 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट था लेकिन पिछले दो सालों में सिर्फ चार किलोमीटर ही इसका तटीयकरण हुआ है। यह काम पैसे के अभाव के कारण अधूरा पड़ा है। यह 34 किलोमीटर बनना है और इसका कम्पलीशन का टारगेट वर्ष 2017 रखा गया था। लेकिन पिछले दो सालों में केवल और केवल 21 करोड़ 86 लाख रुपया इस पर खर्च हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इसके लिए पैसे का प्रबंध किया जाए ताकि समय रहते यह प्रोजैक्ट पूरा हो जाए।

उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र की एक बहुत गम्भीर समस्या पंजाब और हिमाचल की सीमा है। मैंने इस बारे में पिछले सत्र में भी बोला था कि इसकी डिमार्केशन की जाए क्योंकि वहां पर लोगों को यह पता नहीं चलता है कि हमारी जमीन कहां है और पंजाब वालों की कहां है। वास्तव में वह एक खड्ड का एरिया है। मतलब जमीन का भाग नहीं है। वहां जब बरसात के दिनों में बाढ़ आती है तो जब लोग खनन करते है तब लड़ाई होती है। एक बार पानी बहकर वहां चला जाता है और दूसरी बरसात में पानी यहां आ जाता है। इसलिए मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि पंजाब और यहां के एरिया की हदबन्दी की जाए।
मैं अपने क्षेत्र की एक बहुत ही दुःखदायी बात करने जा रहा हूं। वहां पर 498 अपंग बच्चे हैं और बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि 107 बैड रीडन हैं। मैं उनकी समस्या को देखते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके लिए एक स्कूल वहां पर खोला जाए क्योंकि वे बच्चे जब दूसरे स्कूलों में जाते हैं तो जैसे

17/03/2016/1600/MS/DC/2

बच्चों ने कोई कृत्रिम अंग लगाया होता है। मान लो हियरिंग एड या कोई आर्टिफिशिएल हाथ लगाया होता है तो दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। इस कारण फिर वे बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि इन बच्चों के लिए एक स्कूल का प्रबंध वहां किया पर जाए। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

17/03/2016/1600/MS/DC/3

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, यहां पर माननीय सदस्य वीरेन्द्र कंवर जी ने कृषि के ऊपर बात की थी। मैं इनकी एक ड्यूटि लगाने जा रहा हूं। नुरपूर का एरिया, ऊना का एरिया, नालागढ़ का एरिया और पौंटा वैली इत्यादि हमारे अन्य भी बहुत से एरियाज हैं। इन एरियाज में पहले बैलों से खेती होती थी। जिस आदमी के पास दो-तीन एकड़ ज़मीन होती थी, वह बारह महीने दो बैल रखता था। जब से ट्रैक्टर चले हैं तब से

ऐसा हो गया है कि वह अपनी जमीन की प्रैपरेशन और सोइंग ट्रैक्टर के साथ करता है और उसको उल्टे पैसे देता है। पहले वह चार महीने कम-से-कम बैलों के साथ हल चलाता था,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1605/जेएस/एजी/1

बहुद्देश्यीय एवं परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः------जारी-------

पहले वह कम से कम चार महीने बैलों के साथ हल चलाता था और 12 महीने बैलों को मेंटेन करता था। अब यह काम चला गया। उसका घास भी बच गया। जो उसने हल चलाना था वह भी बच गया। वह उन दो बैलों के बदले अगर दुधारू गाय पाले, दो दुधारू भैंसें पाले तो लाखों लीटर दूध हिमाचल प्रदेश में इन्हीं इलाकों में मिल सकता है। करोड़ों रूपए की कीमत हमारी हर रोज़ हो सकती है। मैं, कंवर साहब से यह प्रार्थना करना चाहता हूं। क्योंकि मैंने भी लोगों को यह सुविधा दिलाने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा कि ये हमें नौकरी नहीं दिला सकता है और अब यहां डाल रहा है। फिर मैं इलैक्शन हार गया था। आप मुझे दो किसान ऐसे उनसे दो-दो गाए खरीदवा दो और बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दो। माननीय सदस्य मुझे बात पुरी करने दो । I am still speaking. जहां तक लड़कों को खेतों तक पहुंचाने की बात है इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है स्वामी रामानाथन की रिपोर्ट की कैलकुलेशन कहती है कि गेहूं जो है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 1943 रूपए क्विंटल है। भारतीय जनता पार्टी ने एनाऊंस किया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 50 परसेंट उसको उसकी कीमत दी जाएगी। इस बजट के बाद मैं टी0वी0 पर देख रहा था एक आदमी ने प्रश्न किया और इनके एक बहुत बड़े लीडर थे कि क्या आप 3000 रूपया पर क्विंटल गेहूं करेंगे? उसने कहा अभी यह हमारे बस की बात नहीं है। उपाध्यक्ष जी, 1943 रूपए प्रोडक्शन कॉस्ट और 1500 रूपया उसकी स्पोट प्राईस तब कौन सा बेवकूफ लड़का होगा जो एग्रीकल्चर की तरफ जाएगा? मैं तो बहुत कहता हूं। मेरे लड़के ने मुझे कह दिया था कि पापा इसको बचा के रखो मैं तो इसे प्लॉट बना करके बेचूंगा। जिस

वक्त गेहूं का भाव 100 रूपए हुआ करता था उस वक्त हमारी तन्ख्वाह हजार रूपए हुआ करती थी। ठाकुर कौल सिंह जी की भी, गुलाब सिंह जी की भी, श्री महेश्वर सिंह जी की भी और मेरी भी यही तन्ख्वाह हुआ करती थी। अब एम0एल0ए0 की तन्ख्वाह 1 लाख 25 हजार रूपए हो गई है। आप चुप रहो। अब आप दूसरी बार बोलने लग गए हैं ____(व्यवधान)____ कितनी बार बोलता है। आपके बोलने से मैं चुप नहीं रहूंगा। ____(व्यवधान)____ आप लोग इतने आदमी यहां

16.03.2016/1605/जेएस/एएस/2

पर बैठे हुए हैं इनको आप समझा नहीं सकते हैं। जब आप लोग बोल रहे थे तो मैं यहां के सदस्यों को ऑब्जर्व करता रहा इन्होंने मुंह तक नहीं खोला जब आप लोग बोल रहे थे। ____(व्यवधान)____ उस समय 100 रूपया गेहूं की कीमत थी और 1 हजार रूपया हमारी तन्ख्वाह थी। हमारी तन्ख्वाह आज 1 लाख 25 हजार रूपए हो गई और किसान की इन्कम या उसको जो मिल रहा है वह मिल रहा केवल 1500 रूपए। उसकी राईज़ तो 15 गुणा हो गई और उसका राईज़ 125 गुणा हो गई। कौन सा किसान है जो इस प्रोफैशन में रहेगा? जब तक जनरल प्राईस इन्डैक्स के साथ इसकी कॉस्ट को नहीं जोड़ा जाता है तब तक लोग एग्रीकल्चर की ओर नहीं जाएंगे। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य इसमें कोई डिबेट नहीं होगा। प्लीज बिक्रम सिंह जी आप बोलिए। इन्होंने अपने लोगों की बात की है। इसमें डिबेट नहीं होगा। प्लीज ____(व्यवधान)____इन्होंने यह अपना अनुभव बताया। Virenderji, please sit down. बिक्रम जी आप बोलिये। आप शुरू कीजिए। (Interruption) I am not allowing you. प्लीज आप शुरू कीजिए। माननीय वीरेन्द्र कंवर जी आप बैठ जाईये आपको मैंने अलाऊ नहीं किया है। प्लीज ऊर्जा मंत्री जी आप भी बैठ जाईये। ____(व्यवधान)____ श्री बिक्रम सिंह जी आप शुरू करें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

17.03.2016/1610/SS-AS/1

श्री बिक्रम सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं उस पर बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय कांग्रेस के विधायक बार-बार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि आप इस किताब को लोगों के सामने दिखाते हैं और बोलते हैं कि इस किताब में कुछ नहीं है। अच्छा लगता है कि कांग्रेस के प्यारे विधायक बड़े अच्छे तरीके से इस किताब का गुणगान करते हैं और यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि इसमें बहुत कुछ है। आपका फर्ज़ भी यही बनता है। जिस समय बजट चर्चा की शुरूआत हुई तो वह भाई धर्माणी जी ने की। इन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से बड़े तर्क के साथ सारी बातों को रखा। मुख्य मंत्री बड़े कहते हैं कि छः बार बने हैं। बहुत फास्ट हैं। जिस प्रकार से हमारे लोगों को जवाब देते हैं वे भी जानते हैं कि उनके लोग कैसे-कैसे हैं। जो स्टार्टिंग करवाई राजेश धर्माणी जी से और चैक किया कि धर्माणी जी क्या बोलते हैं। धर्माणी जी ने बड़े अच्छे तरीके से शुरू किया, जिस दिन ये बोले उससे अगले दिन इनके विधान सभा क्षेत्र का टूअर फाइनल हुआ। इनको बधाई है। दो साल से वे वहां नहीं गये थे। अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूं कि तारीफ करनी चाहिए। बड़े अच्छे तरीके से जगजीवन पाल जी बोले। चाहिए भी यही है अपना-अपना काम चलाओ, बाकी बजट में कुछ नहीं है। यहां पर बड़े जोर से बोला जा रहा है कि मुख्य मंत्री जी साढ़े तीन घंटे खड़े रहे। उन्होंने साढ़े तीन घंटे में बहुत अच्छा बजट पढ़ा। भई, खड़े होने की आदत किसको होती है? जो स्कूल में खड़े रहे, वे यहां भी खड़े रहे। यह कोई इंटैलीजैंसी वाला विषय नहीं है इनको खड़े रहने की पुरानी आदत है। अच्छी बात है।

बदकिस्मती यह है कि मैं पिछले तीन साल से बोल रहा हूं और पिछले तीन साल से महाशय (मुख्य मंत्री) जी यहां होते ही नहीं। तो फिर कसर क्यों रखती, बोली जाओ जो बोलना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इस बजट की प्रशंसा की जाए। क्यों की जाएं क्योंकि 31 मार्च, 2015 तक इस प्रदेश पर 35315 करोड़ रुपये का ऋण है। इनकी तारीफ करनी चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर जो कर्ज होता है वह इस समय करीब

48000 करोड़ का है और जो आगे आने वाले हैं उनके ऊपर 50 हजार करोड़ का कर्ज़ा होगा। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि

17.03.2016/1610/SS-AS/2

इसकी प्रशंसा करने की बात बार-बार हो रही है। अब मंत्री महोदया चली गईं मैंने आई0पी0एच0 के ऊपर ही ज्यादा बात करनी थी या यहां हमारे उद्योग मंत्री जी बैठे हैं इनके साथ बात करनी है। आपके स्वास्थ्य का हाल तो बड़ा अच्छा है। गोली मांगों तो टीका मिलता है, टीका मांगों तो गोली मिलती है। इसलिए उसकी बात हमने करनी नहीं है। मैंने तीनों-चारों बजट 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 पर अच्छे तरीके से स्टडी की। मैं भाई जगजीवन पाल जी इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आप लोग जो पिछली बार बोल कर जाते हो तो अगली बार उसको बोलते ही नहीं हो। उसका मूल्यांकन ही नहीं करते हो। पिछली बार जो स्कीम आप बजट में देते हो, अगली बार वह स्कीम बजट में नज़र नहीं आती। पिछली बार अगर आपने किसी व्यवस्था का किया होता है अगली बार वह बजट में नज़र नहीं आता। यह बोला 2013-14 में कि 89.5 परसैंट जनसंख्या ऐसी है जहां पर नलों में पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। 53201 बस्तियों में 44254 स्कीमों पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी मिल रहा है

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1615/केएस/एएस/1

श्री बिक्रम सिंह जारी---

और उसमें बोला कि हम इस बार पच्चीस सौ बस्तियों को इसमें और शामिल करेंगें और दो हजार हैंडपम्प और लगाएंगें। मैंने वर्ष 2013-14 में प्रश्न किया था कि कितने हैंड पम्प लगे और उस पर जो जवाब आया था तो पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी दो हजार टोटल नहीं बनते थे। उसके बाद 2014-15 में भी लिख दिया कि पच्चीस सौ देंगें। पिछले वर्ष में भी पच्चीस सौ और अगले में भी पच्चीस सौ, वह भी नहीं मिला। वर्ष 2015-16 आ गया आपने बोल दिया कि आठ हजार चार सौ ग्यारह योजनाएं ऐसी हैं जिनमें हम ठीक तरीके से पानी नहीं दे रहे हैं और उनका उपचार और संयंत्रों का कार्य करने के लिए 512 जलापूर्ति

योजनाओं के लिए 20 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया। अब आ गया 2016-17 तो इस वर्ष में जो पहली लाईन आपने लिखी है उसमें- पानी में फैलने वाली बीमारियों की चिंता । मैंने एक प्रश्न किया था प्रश्न संख्या- 2685 कि हाल ही में शिमला व प्रदेश के अन्य भागों में पीलिया फैलने के परिणामस्वरूप आई.पी.एच. व अन्य विभागों में कितने-किने अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया? कितने सस्पैंड किए गए, किन-किन को गिरफ्तार किया गया? ब्यौरा नाम व पदवार दिया जाए। इसके उत्तर में लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है और आप बजट के ऊपर पहली लाईन लिख रहे हैं कि बीमारियों के कारण हम बड़ी चिन्ता में है। कल आदरणीय श्री इन्द्र सिंह जी का प्रश्न लगा था उसमें भी यह माना गया है कि 616 स्कीमें ऐसी है जिनमें फिल्टर नहीं है और 383 ऐसी हैं जिनके फिल्टर बैड बंद है। अभी मंत्री जी नहीं बैठी हैं लेकिन चलो जगजीवन पाल जी बैठे हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कारण क्या है, उन कारणों को ठीक करें और मैं यह आपको सुझाव भी देना चाहता हूं कि इन सारी चीजों के अंदर इस समय प्रदेश के अंदर 60 ट्रीटमैंट प्लांट्स हैं और वे सभी के सभी ठेकेदारों के पास दिए गए हैं। उनके ऊपर ठेकेदार ही काम कर रहे हैं। सीवरेज़ को डील करने के लिए आपके पास कोई विभाग नहीं है और जब पानी जनता को दिया जाता है, उसके जो पैरामीटर्ज़ चैक करने हैं, उसके टोटल पैरामीटर्ज़ 80 हैं उनमें से केवल 15 ऐसे हैं जिनको हम हिमाचल प्रदेश के अंदर चैक

17.03.2016/1615/केएस/एएस/2

कर सकते हैं। वायरस चैक करने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और इसमें जो पैरामीटर्ज़ हैं, जैसे फीज़िकल पैरामीटर्ज़ 7 हैं, कैमिकल पैरामीटर्ज़ 21 हैं, बैक्टिरियोलोजिकल पैरामीटर्ज़ 2 हैं, टॉक्सिक 10 हैं, पैस्टिसाईडस 18 हैं। 58 बनते हैं और आपके पास पैस्टिसाईड्स को चैक करने के लिए कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 41 लैब्ज़ हैं और उनके अंदर कॉट्रैक्टर का स्टाफ है। अगर वहां पर बी.एस.सी. रखना है, तो वहां पर टैन् प्लस टू तक पढ़ा हुआ काम कर रहा है जिसको टैस्ट करना ही नहीं आता। इस प्रकार से जो क्वालिटी ऑफ वाटर है उसको चैक करने के लिए जरूरी है कि सीवरेज

सिस्टम के लिए अलग व्यवस्था की जाए। बाकी राज्यों में अगर आप जाएं तो वहां पर चीफ कैमिस्ट रखे हैं। हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से देखना चाहिए ताकि लोगों को पानी मिल सके। पानी देने वाले वाटर गार्ड के अभी आपने 150 रु0 बढ़ाए और वह पानी दे रहा है, स्कीम को देख रहा है और पूरा दिन देख रहा है जबकि कागजों के अंदर आपने बोला है कि वह चार घण्टे काम करेगा। वह पूरा दिन काम करता है रात को भी लगा रहता है इसलिए मैं जगजीवन पाल जी से चाहूंगा कि उनके बारे में सोचें, उनकी सिफारिश करें कि इनको ज्यादा पैसा मिले। इतने कम पैसे के अंदर वे अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगें। यह मेरा निवेदन है। ऐजुकेश के बारे में भी यहां पर बड़ी लम्बी-चौड़ी चर्चा हुई। आपने 2014-15 में बोला कि हम नैट बुक्स एण्ड टेबलेट 7500 देंगें। 2015-16 में बोला कि 10 हजार देंगें। 2016-17 में बोला कि 10 हजार देंगें। आप केवल टारगेट मैंशन करते हैं । आप देते क्या हैं इसका कोई पता नहीं। अभी पीछे माननीय विधायक महोदय बोल रहे थे कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, इससे सरकार के किए गए कार्यों का प्रतिबिम्ब का पता चलता है पता नहीं कहां है वह आपका प्रतिबिम्ब। उसमें आपने कहीं मैंशन नहीं किया कि आपने ऐजुकेशन के अंदर ये-ये प्रोविज़न किए थे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2016/1620/av/DC/1

श्री बिक्रम सिंह क्रमागत----

उस ऐजुकेशन सिस्टम में आपने क्या किया और इन तीन वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया, कोई पता नहीं है तथा वर्ष 2016-17 में मिलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। आज आदरणीय धूमल जी ने यहां पर एक विषय उठाया था। यहां पर 10000 लैप टॉप खरीदने की बात की गई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसका टैंडर 23 अक्तूबर, 2015 को हुआ है कि 10000 लैप टॉप खरीदने हैं। इसकी प्री बिड 9.10.2015 को हुई है। टैंडर की सारी स्पैसिफिकेशन्ज बिल्कुल ठीक थी मगर टैंडर रोक दिया गया। दोबारा दिनांक

19.2.2016 को टैंडर हुआ और वह केवल आई वॉश है। वह टैंडर 2.3.2016 को जारी किए गए और उसकी अंतिम तिथि 4.3.2016 रखी गई तथा अब फिर से ऐक्सटैंड करके उसकी डेट 17.3.2016 कर दी है। आपने टैंडर में जो कंडिशन्ज लगाई है, हम चाहते हैं कि अब हमें वर्ष 2016 के हिसाब से लैप टॉप मिलें। आपने उसमें 2014 के प्रोसैसर की बात की है कि जो 2014 में प्रोसैसर चल रहा था वह भी चलेगा। यह केवल कम्पनी की मिलीभगत के कारण है और आपको (श्री नीरज भारती जी को कहा।) तो इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। मैं यहां पर दो-तीन चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। प्रोसैसर रेटिंग को चैक करने के लिए सॉफ्टवेयर को भी चेंज कर दिया है। साइज मार्क की जगह पी0सी0 मार्क, पूरे हिन्दुस्तान तथा विश्व के अंदर साइज मार्क चलता है। आपका पी0सी0 मार्क नहीं चलता और उसके अंदर जो भी लगा है वह नो प्रोफिट और नो लॉस के अंदर बहुत सी कम्पनियों द्वारा बनाया गया है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जितना भी काम हो रहा है उससे यह नहीं लगता कि इस बार भी बच्चों को लैप टॉप मिलेंगे। यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें हुई हैं। अभी यहां पर कहा जा रहा था कि बड़े स्कूल खोल दिए और उससे आपको तकलीफ होती है। हमें कोई तकलीफ नहीं है और आप स्कूल खोलिए। मगर जिस समय आपने स्कूल खोलने हैं उससे पहले एक योजना बनाइए। आप यह योजना बनाइए कि हमने इस बार

17.3.2016/1620/av/DC/2

सौ स्कूल खोलने हैं और उन सौ स्कूल्ज के लिए टीचर्ज और स्टाफ की पोस्टें ऐडवर्टाइज करें उसके बाद स्कूल खोलते रहें। मगर आपका तो उल्टा काम है। आपने स्कूल खोल कर चले जाना और उसके बाद आपकी पार्टी की सरकार नहीं आयेगी, यह सारी चीजें हमारी पार्टी की सरकार के ऊपर पड़ेगी तथा होगा कुछ नहीं। यह एक समस्या है इसलिए क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन को ठीक करने के लिए मेरा यह निवेदन रहेगा आप सिस्टम के साथ चलिए। मैंने पिछली बार भी बोला था कि आपका कॉलेज चलना है तो वह कॉलेज चले। मगर आपका कॉलेज प्राइमरी स्कूल में चल रहा है। (---व्यवधान---) अगर बिल्डिंग

बननी है तो वह कॉलेज किसी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में चले मगर प्राइमरी स्कूल में चल रहा है। प्राइमरी स्कूल के दो कमरों में चल रहा है और जहां कॉलेज खुलना चाहिए वहां इनका कोई ध्यान नहीं है। उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है कि वहां क्या करना है। वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए अच्छे-अच्छे ऐडवोकेट्स करके सुप्रीम कोर्ट में हमारे कॉलेजिज को बंद करने की बात की जा रही है। सैंट्रल युनिविर्सिटी की बात आती है तो यहां पर किसी के पास उसका जवाब नहीं है। देहरा में 1 हजार एकड़ जमीन सैंट्रल युनिविर्सिटी के नाम हो गई है लेकिन क्योंकि वह देहरा हमीरपुर पार्लियामैंट्री में पड़ता है जहां से हर बार कांग्रेस की हार होती है इसलिए उसको भी फंसाया हुआ है। सुधीर जी को खुश करने के लिए बोल दिया कि सैंट्रल युनिवर्सिटी धर्मशाला में खुलेगी, अब युनिवर्सिटी नालों में थोड़े ही न खुलेगी। उसके लिए जगह चाहिए मगर धर्मशाला के अंदर कहीं भी जगह नहीं है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यही है कि कांगड़ा के अंदर सैंट्रल युनिवर्सिटी न खुले। कांगड़ा के अंदर कोई काम अच्छे तरीके से न हो इस षड़यंत्र के अंदर ये सारी-की-सारी चीजें हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि इन सारी चीजों के ऊपर सरकार ठीक तरीके से काम करें और क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन बढ़े। सभी को अच्छी ऐजुकेशन मिले सरकार को इस बात की चिन्ता करनी चाहिए। यहां पर टूरिज्म के ऊपर भी बहुत कुछ बोला गया। मेरे जसवां-प्रागपुर निर्वाचन क्षेत्र के

17.3.2016/1620/av/DC/3

साथ महाराणा प्रताप सागर डैम लगता है। आप इनका तीन साल का बजट ही नहीं चौथा बजट भी देख लीजिए। आपने जो बजट बुक दी हैं और उसके अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। वहां पर कोई पैसा नहीं रखा गया है। पर्यटक की दृष्टि से वह इतना अच्छा क्षेत्र है कि वहां पर ज्यादा-से-ज्यादा काम हो सकता है मगर उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता।

श्री टीसी द्वारा जारी

17.03.2016/1625/TCV/DC/1

श्री बिक्रम सिंह ---जारी ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पर प्राचीन और ऐतिहासिक तलाबों के रीहबिलटैशन की बात की है और पिछले दिनों मैंने एक प्रश्न भी लगाया था कि हमारे क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़े तलाब है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते रहे है कि ऐसी स्थानों के बारे में सरकार को जानकारी दो उसके रीहबिलटैशन को सरकार पैसा देगी। 61 लाख रूपया टूरिज्म डिर्पाटमैंट के पास पड़ा है और टूरिज्म डिर्पाटमैंट ने अब यह जवाब दिया है कि मामला विचाराधीन है। लेकिन वह मामला विचाराधीन नहीं है। टूरिज्म डिर्पाटमैंट हमारे विधानसभा क्षेत्रों में किसी प्रकार की नई स्कीमों को मंजूरी नहीं दे रहा है। पिछले 4 वर्षों से जितने भी प्राचीन मन्दिरों,तलाबों की ब्यूटीफिकेशन के लिए हमने केसिज़ दिए हैं, वह नहीं हो रहे है। किसी एक विधान सभा क्षेत्र में तो करोड़ों रूपये लग रहे हैं और किसी विधान सभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्री डिर्पाटमैंट का भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में संसारपुर टैरस इंडस्ट्री एरिया है। अभी मैंने एक प्रश्न भी किया था। मैंने पूछा था कि फार्मास्युटिकल की कितनी इंडस्ट्रीज़ है जिनका आपने निरीक्षण किया है? इनका जवाब आया कि हम निरीक्षण करते हैं और हमने पिछले 3 सालों में 30 सैंपल भरे हैं। लेकिन अभी तक रिजल्ट किसी का भी नहीं आया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा कितनों का निरीक्षण किया गया उसमें भी आपने एक लम्बी लिस्ट दी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इंडस्ट्रिलिस्ट को जो डायरेक्शन्ज़ दी हैं, वे उसको मान नहीं रहे हैं। यहां पर बार-बार बड़ी-बड़ी बातें होती है कि हम 70 परसेंट हिमाचलियों के लिए रोजगार देंगे। मैं चाहूंगा कि आदरणीय अग्निहोत्री जी इंडस्ट्री मिनिस्ट्र हैं, सुबह भी आज बड़ी लम्बी-चौड़ी चर्चा हो रही थी और आप कह रहे थे कि मुझे तो हरोली वालों ने जीताया है लेकिन इंडस्ट्री मिनिस्ट्र तो आप पूरे प्रदेश के हैं। संसारपुर टैरस को आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर आज से 20-22 साल पहले बनाया है लेकिन इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर को डेवैल्प करने के लिए आज तक एक भी पैसा नहीं दिया गया। अब भी जब इंडस्ट्री लग रही है, वैसे मैं उसका क्रिटिसिज़म नहीं कर रहा

17.03.2016/1625/TCV/DC/2

हूं, आपके क्षेत्र के अन्दर लग रही है, यह अच्छी बात है। लेकिन ऊना के अन्दर बहुत सारा एरिया है जहां इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। मैहतपुर में इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा स्कोप हैं और वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया खुलने चाहिए। लेकिन संसारपुर टैरस के अन्दर आपका एक भी अच्छी इंडस्ट्री नहीं खुली है और वहां पर जो 70 परसेंट के नार्मज़ इंडस्ट्री डिर्पाटमैंट द्वारा रखे जाते हैं, वह कहीं भी नहीं है उनकी वायलेशन हो रही है। मैं चाहुंगा कि आप वहां का दौरा करें। अपने साथ स्टॉफ लेकर जायें और चैक करें कि जो बातें मैं बोल रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। मुख्य मंत्री महोदय ने एक बात का और जिक्र अपने बजट भाषण में किया कि 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' से लोगों को फायदा होगा लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं होता और विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने 2013-14, 2014-15 की बज़ट बुक में भी ऐसा ही लिखा है । हम चाहते हैं कि सरकार घोषणा ही न करें अपितु प्रैक्टिकली भी इस बात को करें। आपने कई योजनाओं का जिक्र किया जैसे मुख्य मंत्री आवास योजना, चीफ मिनिस्ट्र स्टार्टअप/न्यु इंडस्ट्री स्कीम, मुख्य मंत्री सड़क योजना,मुख्य मंत्री शिक्षा योजना,मुख्य मंत्री आदर्श विद्यालय योजना, मुख्य मंत्री ज्ञानदीप ये सारी जो योजनएं हैं इनके लिए पैसा सारा केन्द्र से आना है। आपने 3 साल पहले कभी स्टार्टअप सुना था ये आदरणीय धूमल जी ने बताया है कि स्टर्टाअप क्या होता है? आदरणीय धूमल जी ने बताया कि औद्योगिकरण के लिए इन चीजों की जरूरत है इसलिए स्टार्टअप शब्द आपके सामने आया है। पहले कभी आपको स्टार्टअप याद नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई अच्छा काम केन्द्र सरकार कर रही है तो उसकी चर्चा भी यहां होनी चाहिए। जो अच्छा काम नहीं हो रहा है उसकी चर्चा तो आप जरूर करते हैं। मैं सड़कों का विषय भी यहां पर रखना चाहूंगा। सड़कों के लिए सरकार जितना मर्जी बज़ट रख दें लेकिन

श्री गर्ग जी द्वारा --- जारी ।

17/03/2016/1630/RG/AG/1

श्री बिक्रम सिंह----क्रमागत

आप पिछले तीन साल से प्रश्नों के जवाब में केवल एक ही बात कह रहे हैं कि Forest clearance नहीं हो रही है। जब Forest clearance नहीं होगी, तो आपका दिया हुआ बजट कहां लगेगा? इसलिए चन्द विधान सभा क्षेत्रों में काम हो रहा है। हमारी हालत तो इतनी पतली है कि पिछले तीन सालों से हमने जितने भी अपनी प्राथमिकताएं सड़कें बनाने के लिए दी हैं, एक भी सड़क की डी.पी.आर. अभी तक नहीं बनी है। केवल हम ही लोग दुःखी नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर्यटन के बारे में मैं बात कर रहा था, इसमें मेरा एक विषय रह गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की बातें आती हैं, उनको हम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में लेते हैं। धर्मशाला में मैच नहीं होता है, तो उसमें कहा जाता है कि शहीदों के बारे में आप लोगों का दृष्टिकोण कुछ अलग है। मेरे घर में एक पत्र आया है और बाकियों को भी यह पत्र आया होगा। यह शशि कुमारी राणा का पालमपुर से पत्र है। इनका पति शहीद हो गया। वह ऑपरेशन रक्षक में लांस नायक थे। जिस समय ये शहीद हुए, तो इनकी पत्नी की आयु मात्र 22 वर्ष की थी। इनके एक बेटी थी और एक बेटे का जन्म पति के देहान्त के बाद हुआ। बेटी M.Sc(Zoology), B.Sc.(Medical), B.Ed.(Basic) और 'टैट' क्वालीफाइड है। आप इन सारी चीजों की बहुत चिन्ता करते हैं। इस महिला ने इस पत्र में यह लिखा है कि वह किस-किस दिन, किस-किस वार को होली लॉज में गई और मुख्य मंत्री महोदय को मिलीं। उनका जवाब क्या रहता है? इन्होंने कहा है कि उनका जवाब रहता है, 'देखो', 'उसको कहो', 'लिख देंगे', 'हो जाएगा'। यह उन्होंने पत्र में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है। आप जो बातें धरातल के ऊपर करते हैं, उनको प्रैक्टिल रूप से भी करने की कोशिश करें। आज धर्मशाला में मैच होने जा रहा था, तो उस बारे में तो बहुत बातें उठ रही थीं, लेकिन यह भी एक शहीद के परिवार का रोना है और इस बारे में भी चिन्ता करनी चाहिए। यहां जो मेरे प्रबुद्ध मंत्री भाई बैठे हैं इस विषय को गंभीरता से लें। यह पत्र केवल मेरे घर में ही आया है, इनके घरों में भी इस प्रकार का पत्र गया है, लेकिन इन्होंने फाड़कर फेंक दिया होगा। यदि इनको शहीदों के बारे में इतनी चिन्ता है, ये लोग शहीदों की बहुत बातें करते हैं, तो इनको यह भी पता होना चाहिए कि क्या यह सत्य है कि हिमाचल भवन, चण्डीगढ़ में पाकिस्तानी सामान की सेल लगी हुई है। उनको आपने एक स्टाल दिया हुआ है। अगर ऐसा है, तो आप इसको चैक करिए। मैं यह कहता हूं कि आपको इन सारी

17/03/2016/1630/RG/AG/2

चीजों पर ध्यान देना चाहिए और यह जो विषय जिसके बारे में हम बार-बार आलोचना करते हैं। आपने कहा कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में खुलेगा। लैण्ड भारतीय जनता पार्टी के समय की ली हुई है, उसके बाद उसमें क्या प्रगति हुई? वर्ष 2014-15 में आपने कहा कि एपल जूस कन्स्न्ट्रेट करने के लिए हम शिमला में 15 करोड़ रुपये दे रहे हैं, उसका क्या हुआ? आपने अभी कहा कि घुमारवीं और नदौन में वर्ष 2014-15 में इन जगहों पर वैजिटेबल पैक हॉऊस लगेगा। अब वह कहां स्टैण्ड कर रहा है और उसका क्या बना? यह सारी-की-सारी चीजें बजट बुक के अंदर लिखी हैं। आप बाकी लोगों का ही शोषण नहीं कर रहें, बल्कि पुलिस का भी शोषण कर रहे हैं। पुलिस के बारे में भी सरकार ने 21-5-2001 को आदेश दिए हुए हैं कि 2310 कांन्स्टेबल का यदि 16 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उनको 80/-रुपये विशेष भत्ता मिलेगा और ऑनरेरी हैड कांस्टेबल बनाया जाएगा। 16वर्ष तो क्या 20-20 वर्ष बीत गए, लेकिन वे बेचारे वहीं-के-वहीं हैं और उनकी जो पर्टिकुलर स्पेसीफिकेशन बनाई गई कि ऑनरेरी कांस्टेबल कौन-कौन सी डियुटी करेंगे। लेकिन आज उनसे वह डियुटी नहीं ली जा रही। उन लोगों को हयूमिलेट किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जितना बोला, मुझे नहीं लगता कि धन्यवाद किस बात का किया जाए और आप लोगों की प्रशंसा किस बात के लिए की जाए, क्या प्रशंसा इस बात की जाए कि आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं खोला, क्या प्रशंसा इस बात की की जाए कि आपने मामूली से पैसे बढ़ाए, क्या प्रशंसा इस बात के लिए की जाए कि उद्योगों में 70% प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को नहीं मिल रहा है, क्या इस बात के लिए प्रशंसा की जाए कि जो आप लैप टॉप खरीद रहे हैं उसमें रिश्वत ली जा रही है,

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1635/MS/DC/1

श्री बिक्रम सिंह जारी-------

क्या प्रशंसा इस बात के लिए की जाए कि सारे-का-सारा ढांचा बुरी तरह से बिगड़ा है। शहीदों के बारे में जो आपकी राय है, वह मैंने पढ़कर सुना दी है और पानी के बारे में क्या राय है तो लोग यहां पीलिए के लिए नहीं आएंगे। मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद पीलिए के लिए नहीं किया जाएगा और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि स्कीमें खराब हैं। 200 में से 190 टैंक टूटे हुए हैं। इसलिए आपकी तारीफ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उद्योग मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने उद्योग के बारे में बात की है। वास्तव में इनके समीप ही मनोहर जी के वहां 150 करोड़ रुपये की लागत से इण्डस्ट्रियल एरिया बन रहा है। मुझे लगता है कि इनकी कोई परेशानी इनके साथ है जो ये बीच में सुजानपुर को लेकर आ गए। आपको हमारा समर्थन करना चाहिए था। परन्तु चलो, हम आपकी मदद करेंगे।

श्री नीरज भारती (मुख्य संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने लैपटॉप के बारे में कहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दिन-प्रति-दिन टैक्नोलोजी चेंज हो रही है। आप कह रहे हैं कि टैण्डर आया था। हो सकता है कि वह टैण्डर हमारी रिक्वायरमैंट्स के मुताबिक ठीक न बैठा हो। इसलिए हमने दुबारा टैण्डर इन्वाइट किए हैं। अगर आपको लगता है कि आउट डेटिड टैक्नोलोजी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप हमें डिटेल दीजिए। -(व्यवधान)- जो भी होगा, वह नई टैक्नोलोजी के मुताबिक ही होगा। अगर आपको लगता है कि हम कोई गलत चीज दे रहे हैं तो बताइए?

17/03/2016/1635/MS/DC/2

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य राकेश कालिया जी भाग लेंगे।

श्री राकेश कालियाः उपाध्यक्ष जी, जो 08 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, मैं उन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह जो बजट डॉक्यूमैंट है यह हिस्टोरिकल है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हिमाचल के विकास के लिए न हो और जिसको ये हमारे मित्र बता सकें। हमारे मित्र केवल और केवल विरोध के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें 1000 के लगभग स्कूल खोलने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह से तीन मेडिकल कॉलेज, 130 स्वास्थ्य संस्थान, 24 आई0टी0आईज0, दो इंजीनियरिंग कॉलेज, 7 एस0डी0एम0 ऑफिस, लगभग 31 तहसीलें और 210 करोड़ रुपया राशन सब्सिडी के लिए रखा है। इसके अलावा "राजीव गांधी अन्न योजना" के तहत सस्ता राशन दिया जा रहा है। अभी विधायकों के भत्तों का तो चल रहा है लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने की बात भी हो रही है। चाहे उनमें बी0डी0सी0 मैम्बर्ज हों, जिला परिषद के मैम्बर्ज हों, जिला परिषद के चेयरपर्सन हों या पंचायत के प्रधान और पंच हैं, उनका मान-सम्मान करते हुए क्योंकि उनके निजी खर्चे होते हैं जैसे उनके घरों में लोग काम करवाने के लिए पहुंच जाते हैं तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने बड़ी दरियादिली से उनके मानदेय बढ़ाए हैं। उसके लिए हम मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं।

मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में हैंड पम्प लगाने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये का जो बजट रखा है उसके लिए भी हम इनके आभारी हैं। हमारे दूर-दराज के क्षेत्र जहां प्रौपर स्कीम का पानी नहीं पहुंचता है या जो टेलएण्ड पर लोग बसे हैं उनके लिए वहां पर हैण्ड पम्प लगाए जा सकते हैं।

एच0आर0टी0सी0 को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की राहत देने की बात भी कही गई है। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग के लिए 3 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसी तरह से अन्य भी कई स्कीमें मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के लोगों के लिए लाई हैं। जैसे सामान्य जाति के गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए किसी भी योजना के तहत पहले सब्सिडी नहीं मिलती थी लेकिन

17/03/2016/1635/MS/DC/3

इन्होंने उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है, जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं । वास्तव में ओ0बी0सी0, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो कई स्कीमें हैं लेकिन सामान्य जाति के जो लोग गरीब हैं उनके लिए कोई स्कीम

नहीं होती थी। उनके लिए मुख्य मंत्री जी ने दरियादिली दिखाई है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं।

इसके अलावा 45 साल से कम उम्र की जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी पैंशन को 1200/- रुपये किया है और ओल्ड एज लोगों की पैंशन भी 1100/-रुपये से 1200/-रुपये बढ़ाई है।

इसी तरह से जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए पहले ही यह योजना है

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

16.03.2016/1640/जेएस/एएस/1

श्री राकेश कालियाः-----**जारी**------

कि उनसे एच0आर0टी0सी0 की बसों में किराया नहीं लेंगे और कई स्कूलों में साईंस के सब्जैक्ट, कॉमर्स के सब्जैक्ट और प्रोफैशनल ट्रेनिंग चलाई जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग बोलते हैं कि बजट में कुछ नहीं है, ये चाहते क्या है? कभी ये कहते हैं कि बहुत स्कूल खोल दिए। क्या ये लोग यह चाहते हैं कि स्कूल बन्द किए जाएं? स्कूल खोलने से इनको क्या दिक्कत है? एस0डी0एम0 ऑफिस खुलता है तो फिर ये कहते हैं कि किसलिए ये एस0डी0एम0 ऑफिस खोले जा रहे हैं और तहसीलदार के ऑफिस किस लिए खोले जा रहे हैं। शायद इनको यह लग रहा है कि नये इन्स्टिच्युशन्ज खुले हैं तो इनको कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। इसलिए ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। अब लोगों को नज़दीक-नज़दीक तहसीलें मिल रही हैं। लोगों के काम आसान हो रहे हैं। अभी हमारे यहां घरारी में तहसील दी है। रोज़ की 15-15 रजिस्ट्रियां हो रही हैं। लोग वहीं पर एफेडिविट बना रहे हैं। वहीं पर रजिस्ट्रियां बन रही है नहीं तो लोग अम्ब में जाते थे। वहां पर बड़ा भारी रश होता था और लाईन में लगना पड़ता था। । वहां पर वकील करो और

अपने ही क्षेत्र में तहसील खुल गई है। इस तरह से हमारे क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। एक और साथी यहां पर कह रहे थे कि स्कूल खोलने काह क्या फायदा है? स्कूलों में बच्चे नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 8 स्कूल ऐसे हैं जिनमें लगभग 600 के करीब विद्यार्थी हैं। एक स्कूल अम्बोटा का है उसमें 700 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। घरारी में 600-700 के करीब हैं। इसी तरह से नंगल देहरा में काफी है, मुबारकपुर में काफी है और इन्दौरा में काफी है। कई जगह स्कूलों की जरूरत है और अभी भी हमारे क्षेत्रों में स्कूलों की जरूरत है। हम अभी भी चाह रहे हैं कि कुछ स्कूल और खोले जाएं। कुछ स्कूल अपग्रेड किए जाएं। मैं, मुख्य मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं कि सामने वाले भाई हमारे इतना उत्पात मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं फिर भी एक करोड़ रूपया इनको भी विधायक निधि के तौर पर बराबर दिया जा रहा है। मेरे जैसा कोई होता तो

16.03.2016/1640/जेएस/एएस/2

कोई न कोई डिस्क्रिमिनेशन कर देनी थी, लेकिन मुख्य मंत्री जी दरियादिली दिखाते हैं। पांच-पांच लाख रूपया हमें किसलिए खर्च करना है इन्होंने हमारी ऐसी-तैसी करने के लिए यह पैसा खर्च करना है। चुनाव में ये क्या करेंगे, किस तरह से ये प्रयोग करेंगे। यह मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि इन्होंने ये पैसा किसलिए यूज़ करना है। इन्होंने अपने प्रधानों को देना है। उन्हीं से झण्डें चलेंगे और उन्हीं से हमारे खिलाफ रैलियां होंगी। लेकिन उस व्यक्ति का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं जिन्होंने एम0एल0ए0 इन्स्टिच्युशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया है उनके लिए एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगा।

मेरे दुश्मन भी, मेरे मुरीद हैं शायद,

वक्त, बेवक्त मेरी तारीफ़ करते हैं,

मेरी गली से गुज़रते वक्त, छुपा के खंजर,

रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं।

मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी दरियादिली से यह काम किए हैं। कभी-कभी भाजपा के लोग भी उनके पास चले जाते हैं। तब वे और तरह के कसीदे पढ़ते हैं। यहां पर जब सामने नहीं हैं तो और तरह की बात कर रहे थे। कोई बात नहीं यह तो हम भी समझते हैं कि आप लोगों ने भी टिकट लेना होता है, इसलिए अपने नेताओं के पास हाज़िरी लगानी है। ये मन से हमारा विरोध बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये मन से बहुत सच्चे आदमी है। दिल से कुछ नहीं करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में बेहतरीन कार्य किए हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी और उनके ऑफिसर्ज़ के लिए कहा था कि एक सैक्शन आपने छोड़ दिया जो कि आंगनवाड़ी के वर्कर हैं और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह कौन सी अन्तिम लाईन है, जो हमने लिखनी है। कालिया जी हम सबके लिए करेंगे। यह बहुत ही वॉस्ट, विस्तृत और सबके लिए कुछ न कुछ राहत देने वाला बजट मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है। ये तो दो-चार दिन पहले लॉ एण्ड

16.03.2016/1640/जेएस/एएस/3

ऑर्डर की बात कर रहे थे। तीन दिन से सुन रहा हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर पर डिस्कशन इन्होंने लाई। आप बताओ जो आपकी सरकार हरियाणा में है वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर का क्या हाल हुआ। आप लोगों ने वहां पर क्या किया? वहां पर एक लाख करोड़ रूपए का नुकसान हो गया। पहले तो हिन्दु और मुस्लिम के झगड़े होते थे लेकिन वहां पर आप लोगों ने एक ही कॉस्ट के अन्दर झगड़े करवा दिए। आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आप लोगों को सरकारें चलानी नहीं आती। आप तो अभी दाऊद लाने की बातें कर रहे थे। आपने दाऊद तो क्या आना माल्या भी छूट के भाग गया? आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। एक बहुत बड़ी नेत्री देश की है उनके हम बड़े भाषण मलाईदार सुनते थे। हमें लगता था कि इनसे बड़ी देश भक्त कोई नहीं है। वहां पर केंडल लाईट डिनर करने वहां चले गईं। इस्लामाबाद में केंडल लाईट डिनर किया। एक हमारे प्रधान मंत्री जी को कहते थे कि लाल आंखें करो और ये करो, वो करो और एक के बदले दस लाओ। 56 इंच की छाती है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

17.03.2016/1645/SS-DC/1

श्री राकेश कालिया क्रमागतः

एक के बदले 10 सिर लायेंगे। तो उनका जहाज़ हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए रास्ते में इस्लामाबाद ही उतर गया, बिना ऑपोजिशन को बुलाए, बिना देश को कॉंफीडैंस में लिये हुए। इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। ये क्रिकेट खेलने की बातें कर रहे हैं। भईया 10 किलोमीटर पर एक नौजवान लड़का शहीद हुआ है आप उसकी छाती पर पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर एक मैच खेलना चाहते हो। कहीं और खिला लो, पूरा हिन्दुस्तान पड़ा हुआ है। जहां पर शहीद हुए हैं वहां पर आप मैच क्यों खिलवाना चाहते हैं? कोई ज़रूरी थोड़े है। उस मैच का हमें भी तो कोई फायदा बताओ। लोग सोचते हैं कि हमें 100-100 टिकट मिलती है। हमें तो एक फूटी टिकट नहीं मिलती। हम तो बाहर दरवाजे से नहीं झांक सकते। मैं कह रहा हूं कि न हमारे हिमाचली मैच देख सकते हैं, हमने तो सिर्फ टी0वी0 पर ही देखना है। चाहे आप उसे कलकत्ता करवा लो या इडनगार्डन करवा लो या लॉर्डज़ में करवा लो, हम हिमाचलियों को तो टिकट नहीं मिलने वाली। जालन्धर या दिल्ली से लोग मैच देखने आयेंगे या फिर कहीं बाहर से आयेंगे। हमें तो टिकटें मिलनी नहीं। तो फिर हमने फौजियों का दिल काहे को दुखना, हमारे फौजी जिससे नाराज़ हो रहे हैं। ऐसी आपकी कथनी और करनी है। जब आप ऑपोजिशन में थे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि हम यह कर देंगे। बराक ओबामा को मोदी साहब बोलते हैं Hi, Barack, how are you? 25 साल से कांग्रेस गवर्नमैंट ने एफ-16 की सप्लाई रोक रखी थी लेकिन मोदी साहब के प्रधान मंत्री बनते ही, 15-20 दिन पहले एफ-16 उनको मिल गये हैं और उनकी मारक क्षमता चाईना के बराबर हो गई है। वह राडार में जल्दी नहीं आता। अगर आपकी इतनी अच्छी बनती थी Hi, Barack. Hi, Obama और फोन पर लम्बी-लम्बी बातें होती थीं तो आप इसको रूकवाते। रिलेशन कोई झफियां डालने के लिए थोड़े होते हैं। अपने देश को कैसे स्ट्रैंथन रखना है, अपने देश के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उसे रोकने के लिए अपनी दोस्ती का कैसे इस्तेमाल करना है यह पता होना चाहिए। सिर्फ खाना खाने के लिए इसमें डिनर डिप्लोमेसी का कोई स्थान नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने 15 लाख रुपया प्रति खाता देने की बात कही थी, वह भी पूरी नहीं हुई। आपने कहा था कि आप रुपये की वैल्यू ठीक कर देंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया स्ट्राँग हो जायेगा, वह भी नहीं हुआ। लोक सभा इलैक्शन के समय जो आपने लोगों के साथ जुमले किये थे वे सारे फेल

होते दिख रहे हैं। आपके पास बोलने को कुछ नहीं है। इसलिए कभी हमारे साथी कहते हैं कि स्कूलज़ादे हो गए। आप स्कूल बंद करवा लो जो आपने करवाने हैं। लिखकर दे दो

17.03.2016/1645/SS-DC/2

अगर एक या दो स्कूल बंद भी करवाने हैं। मुख्य मंत्री को लिखकर दे दो कि मेरे क्षेत्र में यह स्कूल नहीं चाहिए। हमें यहां स्कूल नहीं खुलवाने, आप उसे अपने तरीके से कह सकते हैं। तहसीलों के लिए कह सकते हैं। या आप उन्हें खुलवाने के लिए बोलिये। समझ नहीं आ रहा है कि आपकी मंशा क्या है? क्या आप यह नहीं चाहते कि विधवाओं को पैंशन मिले? हम उन्हें 1100 रुपये पैंशन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस बजट बुक में कुछ नहीं है। एक काम में ये बड़े मास्टर हैं। दिल्ली में पता नहीं क्या सीखाकर आते हैं? अरूण कुमार जेतली को समझाकर आते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को तंग करना है। तो लगातार कोई-न-कोई इ0डी0 या कई तरह के महकमें उनके पीछे लगा रखे हैं। जब भी ये मुख्य मंत्री बनते हैं, हम 20 साल से देख रहे हैं कि होली लॉज में एक नई ईंट नहीं लगी। एक नई गाड़ी नहीं दिखी। इनको पता नहीं इनके पास पैसे कहां से नज़र आते हैं। वे सरकारी आवास में भी नहीं रहते। यहां तो लोग ऐसे भी देखे हैं जो सरकारी आवासों को पद पर रहने के बाद भी नहीं छोड़ते। परन्तु होली लॉज आज तक वैसा-का-वैसा है। मुख्य मंत्री जी, एक संत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई बार राजनीतिक रूप से हमारी बातचीत अच्छी नहीं होती लेकिन मैं इस बात का फैन हूं कि उस व्यक्ति ने अपना राजनीति का पूरा जीवन प्रदेश के लिए लगाया है। हमेशा वे प्रदेश की बात करते हैं। इस बात के लिए कई बार हमारा ज़मीर उनके साथ खड़ा होने को मजबूर करता है। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूंः-

"झूठ का सहारा लेकर उम्र जो पाऊं,
मौत से नहीं, शर्म से मर जाऊंगा।
झूठ का सहारा लेकर उम्र जो पाऊं,
मौत से नहीं, शर्म से मर जाऊंगा।
सख्त जान हो गया हूं तूफानों से टकरा-टकरा कर,
लोग समझते थे कि मैं तिनकों की तरह बिखर जाऊंगा।"

जो आप सोचते थे कि ये सी0बी0आई0 वालों को भेजकर यहां इंक्वायरी करवा कर मुख्य मंत्री जी काम करना बंद कर देंगे, उनका ध्यान डाईवर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत है। हमने यहां देखा है। मैं as neutral person बोल रहा हूं। मैं बड़ा मजबूत आदमी हूं। हम कभी किसी से नहीं घबराए। लेकिन हम यहां देखते हैं कि आप 20 लोग उन पर अटैक करते हैं He used to take one by one out of you. सभी की बात

17.03.2016/1645/SS-DC/3

सीरियसली सुनते हैं और सभी का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। Sincerity से जवाब देते हैं। आप मजाक में भी कोई बात बोलें तो उठकर खड़े हो जाते हैं और आपकी बात को एक सही अंदाज में सही डैमोक्रेट के रूप में हमेशा जवाब देते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1650/केएस/डीसी/1

श्री राकेश कालिया जारी---

इसी भावना की वजह से हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। उनके तुजुर्बे का हम फायदा ले रहे हैं और क्षेत्र का विकास भी करवा रहे हैं। ऊना का विकास भी हो रहा है। आपने तो स्वां नदी चैनेलाईजेशन का पैसा रुकवा दिया है। दिल्ली से पैसा आ नहीं रहा है। हमारे अनुराग ठाकुर जी एम.पी. हैं, उनको केन्द्र में मंत्री नहीं बनाया। कहते हैं कि उनकी मोदी से बड़ी बनती है,मोदी प्रदेश में एक नई बहार ला देंगें। बहार क्या लानी है, वह तो बेचारा तीन बार सांसद बनने के बावजूद यूं ही घूम रहा है। उसको अभी भी यूवा मोर्चा में ही रखा गया है। अनुराग का चुनाव क्षेत्र है, पता नहीं मोदी साहब ने पैसे रोक दिए या अनुराग को वहां केस स्ट्रांग करना नहीं आ रहा है, हमारे पैसे वहां पर रोक दिए हैं। हमारा 500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जबकि स्टेट का शेयर हमने दो सौ करोड़ रु0 दे भी दिया है। 107

करोड़ रु0 की पहली किश्त भी जारी हो चुकी है। इतिहास में आज तक नहीं सुना कि जो प्रोजैक्ट सेंक्शन हो गया है, उसका पैसा किसी सरकार ने रोका हो। ये कहते हैं कि हम गंगा नदी बनाएंगें। एक साध्वी मंत्री बनाई है वह कहती है कि गंगा के घाट बनाएंगें। आप गंगा के घाट बनाओ। राम मंदिर भी बनाओ और 15-20 साल पहले आप राम मंदिर की बात भी करते थे। आप बंदरों को पकड़ने की बात भी करते थे। जिन चीजों के साथ धार्मिक बातें बातें जुड़ती हैं, उनके आप दिखाने के लिए पक्षधर होते हैं। आप गऊ माता की बात करते हैं। साथियों आपको न गऊ माता माफ करेगी, न भगवान हनुमान माफ करेंगें और न भगवान राम माफ करेंगें। आपको तो गऊ माता वैतरणी नदी भी पार नहीं करवाएगी क्योंकि जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आप कहते थे इन्होंने पिंक रेवोल्यूशन लाया है।, इन्होंने गऊ काट दी, बैल काट दिए अब क्यों बैन नहीं लगाते ?

उपाध्यक्ष महोदय, ऊना का एक मेन रोड़ था और हमारी पिछली सरकार के समय में उसके लिए पैसा सेंक्शन हुआ लेकिन जब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी

17.03.2016/1650/केएस/डीसी/2

की सरकार प्रदेश में आई तो इन्होंने पांच सालों में उस रोड़ का इतना बुरा हाल कर दिया, ऊना से अम्ब तक लोगों ने आना-जाना छोड़ दिया था। वाया गगरेट हो कर लोग जाते थे और ये पांच साल तक रोड़ नहीं बना सके। अब जा कर जब हमारी सरकार बनी तो मुख्य मंत्री जी ने एक साल के अन्दर-अन्दर वह रोड़ बनाया और आज वह हिमाचल प्रदेश का बैस्ट रोड़ है। उससे बढ़िया रोड़ हिमाचल में कहीं भी नहीं है। पंजाब में भी वैसा रोड़ नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी मित्रों के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूंः

जमींर जिंदा रख, दिल में कबीर जिंदा रख,

सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख,

हौंसलों के तरकश में कोशिशों के वो तीर जिंदा रख,

हार जाए चाहे तू जिन्दगी में सबकुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख,

बहना हो तो शौक से बह, मगर सागर में मिलने की चाहत जिंदा रख।

मिटता तो आज मिट जाए इन्सान, मगर मिटने के बाद इन्सानियत जिन्दा रख।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ जो मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद

17.03.2016/1650/केएस/डीसी/3

उपाध्यक्षः अब श्री बी.के. चौहान जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री बी0के0 चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। जो 2016-17 का बजट इस माननीय सदन में पेश किया गया, इसे मैंने गौर से पढ़ा। दुर्भाग्यवश मुझे जो यहां हिमाचल की सबसे अधिक जनसंख्या जिस प्रोफैशन में है, जो काम करती है वह है कृषक।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

17.3.2016/1655/av/DC/1

श्री बी0के0चौहान क्रमागत

किसान के लिए कोई कारगर या उनके उत्थान और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। उनके कृषि के कारोबार में यदि कोई मुश्किल पड़ जाए या फेल कर जाए तो उसमें कोई भी ऐसी स्कीम या ऐसी योजना नहीं है कि उसको तुरंत राहत दी जा सके या उसका रहन-सहन का स्तर बढ़ाया जा सके। आमदनी बढ़ाने के लिए कोई तरीका

निकाला जा सके या कोई योजना बनाई जा सके। सारा सदन जानता है कि किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। जिन किसानों ने ऋण लिया है वे ऋण के बोझ में दबे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास उस ऋण को वापिस करने का कोई जरिया नहीं है और न ही सरकार ने उसके लिए कोई कारगर उपाय किया है। जब भी किसान ऋण लेता है तो देहाती आदमी सीधा कोऑप्रेटिव बैंक में जाता है क्योंकि पहले किसानों को बड़ी जल्दी ऋण मिल जाता था। अब जो किसान ऋण लेकर बैठे हुए हैं उनके घरों में ताले लग रहे हैं। मेरे अपने जिले में इस सरकार के समय में ही कम-से-कम 30-40किसान ऐसे जो मेरे सम्पर्क में हैं। वे मेरे पास आकर अपनी व्यथा सुनाकर गये। एक किसान ने बताया कि हमारा बड़ा परिवार है, तीन-चार भाई है। आधा घर उनके पास है और आधे घर में कोऑप्रेटिव बैंक ताला लगाकर चला गया है। उनके पास यह सामर्थ्य नहीं है कि जो उन्होंने 70-80 हजार रुपये ऋण लिया है जो कि अब हो सकता है कि 1 लाख रुपये से ऊपर हो गया है, वह उसकी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ जब कृषि से उनको कोई आमदनी नहीं हो रही है और अपना पेट भरने के लिए कोई कमाई या गुजारा नहीं हो रहा है तो प्राचीन काल से ही किसानों का दूसरा स्त्रोत पशु धन होता था। आज पशु धन की जो हालत है वह आप सभी जानते हैं। आज किसान गाय को तब तक अपने पास रखता है जब तक वह दूध देती है। दूध देना बंद करने के बाद उसको बाहर निकाल देता है। इसी तरह से बैलों की हालत है। जब तक बैल हल को खींचता है तब तक उसकी सेवा होती है और जब वह कमजोर हो जाते हैं तो उनको बाहर निकाल देते हैं। इस बजट में मुझे उनके उत्थान के लिए कोई योजना नहीं दिखाई देती। जहां तक पशु धन की बात है तो

17.3.2016/1655/av/DC/2

आज आप देख रहे हैं कि जगह-जगह आवारा और बेसहारा पशु मिलते हैं। आप रात को कहीं भी चले जाएं, हम कई बार यहां से रात को चम्बा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कई जगह इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। हमें कई जगह सड़कों पर खड़े मवेशी मिलते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति है, तरस आता है। बड़ी बुरी हालत है, किसान रोता है। जब

वह अपने घर से निकलता है तो गाहे-बगाहे कहीं अपना पशु मिल जाता है और वह पशु उनके पीछे-पीछे आने लगता है। एक इनसान ने पशु को त्याग दिया है और 15 दिन या महीने बाद वह उसको मिले तथा वह उसको फिर भी न ले जाए तो इससे उस किसान को क्या लगता होगा और पशु भी मन ही मन में रोता होगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। अभी सात सदस्यों ने और बोलना है तो इस मान्य सदन का समय एक घंटे के लिए 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया जाता है।

श्री बी0के0 चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें जितना समय देंगे उससे आगे नहीं बढ़ूगा। मैं यहां पर बेरोजगारी और किसान की समस्या इसलिए रख रहा हूं

टीसी द्वारा जारी

17.03.2016/1700/TCV/DC/1
श्री बी0के0 चौहान---- जारी।

क्योंकि वर्तमान सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। उसमें बागवान भी है, बागवान की तो कुछ न कुछ फलों की सैल हो जाती है और वह अपना गुजारा कर लेते हैं लेकिन यहां पर कृषक भूखमरी के कागार पर है। इसके लिए कोई न कोई योजना बनाए। अन्यथा ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। जब भी हम लोग बाहर गांव में जाएंगे तो हमको डंडे तो पड़ेंगे ही कि हम यहां पर बैठे हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि किसको कैसे रोजगार उपलब्ध करवाना और क्या विकास करना है लेकिन जो बहुल कैटागिरी है उसके लिए हम क्यों चुप है? उपाध्यक्ष महोदय, ये बेरोजगारी की समस्या जो है यह बहुत गहरी है और यह सभी जिलों में एक जैसे है, कुछ में हो सकता है ज्यादा हो। बेरोज़गारी हिमाचल में ही नहीं बाहर भी बढ़ती जा रही है। आजकल लोगों ने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना बन्द कर दिया है। एक तो उनके पास पैसा नहीं है और दूसरे नौकरी ही नहीं मिलती है। आज भी कितने ही इंजीनियर्ज़,ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स घर में बैठे हुए हैं और वे हमारे पास आते हैं कि हमें किसी भी छोटी-मोटी नौकरी में लगा दो। हमको 500 रूपये भी

मिल जाएंगे तो भी काफी है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें हम एक बार सुनकर भूल जाते हैं लेकिन इस सदन में हमको इस पर गहन विचार करना चाहिए ताकि हम उनकी बहुत बड़ी मदद नहीं तो थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। जो डिजर्विंग कंडीडेट हैं उनको यदि कोई नौकरी दिला सकते है तो दिलानी चाहिए लेकिन हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एटीट्यूड बड़ा सम्पैथैटिक नहीं रहता है जहां भी हम किसी की मदद कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। यह एक परम्परा सी डाल दी गई है कि बिना सिफारिश से नौकरी नहीं मिलेगी। जब हम और आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ले रहे थे वह जमाना कम्पिटीशन का था अच्छा सा इंटरव्यू दिया और हो जाता था लेकिन अब वह बात नहीं है। अब जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वह भी बाइस्ड हो गये हैं। अगर 10 आदमी की लिस्ट है और उसमें से 2 रखने हैं तो उनका पहले ही चयन हो जाता है कि कौन किसका आदमी है और किसको रखना है। मैरिट अब सैकेंडरी हो गई है और सिफारिश प्राईमरी हो गई है। लेकिन ये प्रथा गलत है इसके बारे में भी सरकार को कोई कारगर कदम उठाने चाहिए और इस दिशा में सोचना चाहिए

17.03.2016/1700/TCV/DC/2

या तो थोरोली मैरिट पर लीजिए अगर आपको मैरिट पर नहीं लेना है तो उन लोगों को लीजिए जो डिजर्व करते है।

श्री गर्ग जी द्वारा ---- जारी

17/03/2016/1705/RG/AG/1

श्री बी.के. चौहान----क्रमागत

सिफारिश में भी अगर कोई आता है और बिल्कुल ही निखिद्ध है, तो उसको नहीं रखना चाहिए। लेकिन कोई 2-4 या 5% में है, तो उसकी गरीबी या उसकी माली स्थिति को देखकर प्राथमिकता देनी चाहिए। यह मेरा अपना मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी शिक्षा की बात कर रहा था। हमारे शिक्षा संस्थानों का बहुत बुरा हाल है। जैसा अभी मेरे कुछ बंधुओं ने यहां बताया भी है। उनकी बहुत ही बुरी हालत है। मेरे

चंबा में बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय हैं और कुछ में तो एक भी अध्यापक नहीं है और हैं भी, तो एक है। जहां-जहां 5-5 या 6-6 कक्षाएं हैं और एक अध्यापक है। वही हाल मिडिल स्कूलों का है। स्कूलों में जे.बी.टी. टीचर्स लगाए दिए हैं जो लोअर क्लास है, ऊपर उनके पास इंगलिश का कोई टीचर नहीं है, मैथ्स का कोई टीचर नहीं है और इन स्कूलों में जो प्राथमिक, मिडिल और यहां तक के हाई स्कूल तक भी ऐसी प्रवृत्ति अध्यापक वर्ग में आ गई है कि वे पढ़ाने को अपनी नौकरी नहीं समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे तफरी करने के लिए आते हैं। मेरे और साथियों ने भी देखा होगा। मेरे चंबा में तो ऐसी स्थिति आ गई है कि जो बाहर से कांगड़ा या अन्य स्थानों से आए हैं उनके तो मजे-ही-मजे हैं। वे सुबह घर से चाय पीकर आते हैं, साथ में टिफिन लेकर आते हैं। कुछ दिन तो मुझे पता नहीं लगा और मैं यही सोचता रहा कि कहीं भी जाओ, तो ये टीचर्स टिफिन लेकर क्यों आते हैं? मुझे एक महिला ने बताया कि ये इसलिए टिफिन लाते हैं कि वहां खाना बनता है और में भी एक स्कूल में खाना बनाती हूं। वे स्कूल में आकर ही अपना ब्रेकफास्ट और लंच कर लेते हैं और शाम के खाने को अपने टिफिन में भरकर ले जाते हैं। यह तो अजीब हालत है। कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है, कोई भी उन पर निगरानी करने वाला नहीं है। पढ़ाना-लिखाना है नहीं, खाना भी सरकारी खाना और तनख्वाह भी लेना। यह हमारे हिमाचल की अंदर की स्थिति है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे घूमने-फिरने का शौक है इसलिए मैं अपने चुनाव क्षेत्र में यदाकदा घूमता ही रहता हूं। मेरे और भी साथी ऐसा करते होंगे। इनके क्षेत्र में शायद ऐसा नहीं होगा। मेरे चंबा में तो हैं जेसे मेरे साथी श्री जरयाल जी भी कह रहे हैं।---(व्यवधान)--- मण्डी में भी है। फिर तो 'रब ही रक्खा है'। शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात कर रहा था कि एक तो टीचर हीं नहीं है। मैंने आने से पहले दोनों डिप्टी डायरैक्टर, हायर ऐजुकेशन और मिडिल, दोनों से यह आंकड़ा मांगा था कि आपके

17/03/2016/1705/RG/AG/2

किस-किस स्कूल में कितने-कितने अध्यापक हैं, लिस्ट मेरे पास थी। लेकिन उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी। यहां से मैंने दो-तीन बार फोन किए। कहते हैं कि हम आपके पास यह सूचना किसी आदमी के द्वारा भेज रहे हैं। बस से सुबह आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन आज तक पता नहीं चला। क्योंकि उनको पता है कि अध्यापक नहीं हैं, हम अगर ऐसा बोलेंगे, तो डी.ई.ओ. आदि हमें डाटेंगे और वे कहेंगे कि हमें, आपने क्यों नहीं बताया। जो

डायरैक्टर या डिप्टी डायरैक्टर है, तो ऐसी स्थिति है। हमारे स्कूलों में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। कोई-कोई स्कूल होगा जहां मुख्य अध्यापक या प्रिंसीपल थोड़ा समझदार हैं और अपनी डियुटी को डियुटी समझता है। तो ऐसे स्कूलों से निकलने वाले बच्चों को क्या नौकरी मिल सकती है? ऐसे बच्चों को जिसने नकल मारकर मैट्रिक की हो और आज कल अध्यापक ही नकल करवाते हैं। उनको अपना रिजल्ट देना होता है इसलिए वही उसका पेपर करवा देते हैं और वह पास हो जाता है। क्या यह सिस्टम बदलेगा?

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1710/MS/DC/1

श्री बी0के0 चौहान जारी--------

क्या मेरे सत्ता पक्ष के बन्धु यह आश्वासन दिला सकते हैं और यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार इसको करके दिखाएगी? इसके अलावा, स्कूलों में पढ़ाई होगी और यह सब जो हो रहा है वह नहीं होगा? सब लोग अपना-अपना काम आठ घण्टे नहीं तो छः घण्टे तो करेंगे ही क्योंकि हर व्यक्ति जो तनख्वाह लेता है उसको कम-से-कम आठ घण्टे काम करना ही है। वह आठ घण्टे नहीं, छः घण्टे नहीं, क्या चार-पांच घण्टे अपनी निष्ठा से काम करेगा? तब तो हम हिमाचल प्रदेश के उत्तम भविष्य के बारे में सपना देख सकते हैं और अपने बच्चों को आगे हायर नौकरी में जाने का सपना देख सकते हैं। वरना जो हम लोग यहां पर बैठे हैं, हम केवल अपनी तनख्वाह पाने और समय बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। हम राष्ट्र के प्रति तो छोड़िए, अपने प्रदेश के प्रति भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यह मेरा अपना मानना है। यदि कोई बुरा समझे तो मुझे क्षमा कर दें। क्योंकि जो हालत आप और मैं फील्ड में देखते हैं उसको देखकर कई बार रोने का मन करता है। उपाध्यक्ष जी, मैंने ये ग्रामीण हिमाचल की एक छवि रख दी है, जिस पर मैं सोचता हूं कि आप विचार करेंगे।

यहां पर स्वच्छ पानी की बात चली थी। स्वच्छ पानी की बात भी तब चली जब शिमला कैपिटल में पीलिए की महामारी फैली यानी पीलिया यहां पर महामारी की तरह फैला। उसके बाद सारे जाग गए कि यहां का पानी खराब है, पानी के सैम्पल खराब है, ये है वो है इत्यादि। काफी सारे लोग मर भी गए। दुर्भाग्यवश यह बीमारी गरीबों को ही नहीं लगी

बल्कि यहां ऑफिसर्ज गैलरी में बैठने वाले सीनियर आई0ए0एस0 ऑफिसर्ज भी इसकी चपेट में आए। वे भी बीमार हुए। उनको भी पीलिया हुआ। तब सब लोगों की आंखें खुली कि यह बीमारी तो जानलेवा है लेकिन उसके बाद भी आंखें हमारे हिमाचल की नहीं खुली। शिमला में तो कुछ प्रबंध शायद कर दिया होगा लेकिन अभी भी हमारे हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खड्डों, नालों और बावड़ियों का ही पानी पी रहे हैं। क्योंकि वहां यही पानी उपलब्ध है। उसमें कोई दवाई भी नहीं डाली जाती। उसको स्वच्छ

17/03/2016/1710/MS/DC/2

करने के मैथ्ड के बारे में क्या आज तक किसी ने सोचा है? मुझे नहीं लगता आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट से इसके लिए अभी तक कोई स्कीम भी बनी हो और सभी जिलों को गई हो कि आपको ये-ये कारगर कदम प्रिकॉशन्ज के लिए उठाने हैं या जहां से आप वाटर सप्लाई करते हैं, वहां पर जो टैंक बना है, वहां पर आपको क्या-क्या प्रिकोशन्ज लेनी हैं। यह शिमला में हुआ तो सारा हिमाचल जाग गया। अगर मेरे चम्बा के गांव में होता तो शिमला तक तो खबर पहुंचते-पहुंचते सारा गांव ही साफ हो जाना था। क्या इसको तत्परता से एक फौरी तौर पर एज एमरजैंसी टेकअप किया गया है? हिमाचल सिर्फ शिमला में ही नहीं है। हिमाचल बहुत बड़ा है और इसमें काफी जिले आते हैं। हिमाचल में शिमला है लेकिन शिमला में हिमाचल नहीं है। ये बातें हैं जिन पर हमें गहन विचार करना होगा। तभी यह बजट मुझे सार्थक लगेगा, हमारा बैठना सार्थक लगेगा और इतना समय देना भी सार्थक लगेगा।

उपाध्यक्ष जी, बेरोजगारी, स्वच्छ जल और किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में मैंने आपको ये थोड़ी सी झलक दिखाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हम और आप दोनों जानते हैं कि क्या हो रहा है लेकिन सिर्फ सरकार ही नहीं जानती है कि हमारे शिक्षक क्या करते हैं और कितनी और कैसी पढ़ाई हो रही है। चम्बा में अशिक्षित ज्यादा लोग हैं जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं ज्यादा अशिक्षित हैं। उपाध्यक्ष जी, आपको हैरानी होगी कि पिछली सरकार के समय चम्बा में भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी आए थे,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

16.03.2016/1715/जेएस/एएस/1

श्री बी0के0 चौहानः--------जारी---------

उन्होंने चम्बा का दौरा किया और वहां पर एक मीटिंग बिठाई और उस मीटिंग में मैं भी था। चम्बा का प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने ये बताया कि चम्बा में हिमाचल ही नहीं भारतवर्ष भर में अनपढ़ महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। मैं उसका कुछ डाटा लाया था। वह है कि 35 परसेंट महिलाएं शिक्षित हैं और बाकी अनपढ़ हैं। 35 परसेंट महिलाएं यदि शिक्षित हुई तो बाकी जो अशिक्षित महिलाएं हैं ।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बी0के0 चौहानः उपाध्यक्ष महोदय, आपने गप्पे मारने वाले लोगों को आधा-आधा घंटा टाईम दिया है मैं काम की बात कर रहा हूं और अभी 22 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आपके 22 मिनट पूरे हो गए हैं।

श्री बी0के0 चौहानः उपाध्यक्ष जी, 22 मिनट तो हो गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें एक प्रोजैक्ट उन्होंने दिया। वह प्रोजैक्ट था 35 करोड़ रूपए का । जितना वह आगे चलता उतनी उसमें फंडिंग होनी थी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि यह सबसे पहले प्रोजैक्ट तीसा में चलाया गया। तीसा के विधायक यहां नहीं है, वे भी शायद इसमें प्रकाश डालते। तीसा में यह प्रोजैक्ट चला और वहां पर पहले बच्चों को यानि बेटियों को शिक्षित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। जो इसकी स्टेट लैवल की कमेटी थी उसमें मैं भी थोड़े समय के लिए और श्री धीमान जी शिक्षा मंत्री थे और स्टेट लैवल कमेटी के वे अध्यक्ष थे। उसके 6 महीने के बाद शायद सरकार बदल गई। उस पीरियड में आप हैरान होंगे उसका सारे का सारा पैसा जो कमेटी वहां पर बनी थी जिसमें अध्यक्ष जो था वह डाईट का प्रिंसिपल था, कोई मिस्टर चन्द्रा करके और एक मेम्बर वहां के ग्रामीण को लिया गया था उनके साथ एक कमेटी बनाई गई

16.03.2016/1715/जेएस/एएस/2

थी। वह सारा पैसा हड़प हो गया। आज उसमें पैसा नहीं रहा है। वह जस का तस है। उस प्रोजैक्ट में करोड़ों रूपए का गबन हुआ है। डी0सी0 जिला लैवल में उसका अध्यक्ष था, न उसने उसके लिए कोई कारगर कदम उठाए कि पैसा कहां गया, कौन खा गया, केस दर्ज़ होता और न ही शिक्षा विभाग के इतने अधिकारी यहां पर बैठे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लैवल पर थे उन्होंने यह किया? ये शिक्षा की स्थिति है। यह प्रोजैक्ट चम्बा जिला को पायलट प्रोजैक्ट ले करके हिमाचल के अन्य जिलों में भी जाना था लेकिन वहीं पर इसको खत्म कर दिया गया। कितना बड़ा नुकसान है? मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा नुकसान है। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे कि बहुत बड़ा नुकसान है। कितनी बच्चियां, कितनी प्रौढ़ महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं थी उन सबको दसवीं तक शिक्षा फ्री देनी थी। वे सब इससे महरूम हो गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस पर सरकार उच्च स्तर की जांच रखें, चाहें विजिलैंस को दें या किसी और को दें। हिमाचल सरकार इसकी इन्क्वायरी करवाए ताकि आगे के लिए इसमें कुछ अच्छा सुधार कर सके। आगे ऐसा गलत काम हिमाचल प्रदेश में न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारा कहने को है लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि वाईंड अप करिए, वाईंड अप करिए । यह सरकार की फेल्योर्ज़ ही थी। जो काम हम लोगों ने किया था या जो पैसा हमने भी लाया उस को भी ये सरकार यूटेलाईज़ नहीं कर सकी। इन्होंने ग्रामीणों की दिशा व दशा पर कोई गौर नहीं किया।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

17.03.2016/1720/SS-DC/1

श्री बी0के0 चौहान क्रमागतः

जैसे आज इस सदन में रूचि नहीं ले रहे हैं और सिर्फ दो-चार लोग ही बैठे हैं वैसी ही रूचि जो इनका डे-टू-डे का काम है उसमें भी मुझे लगता है कि लेते होंगे तभी सारा हिमाचल

त्राहि-त्राहि कर रहा है। कुछ लोग पानी के लिए मर रहे हैं। कुछ शिक्षा के लिए मर रहे हैं। कुछ रोज़गार के लिए मर रहे हैं। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। जो मैजोरिटी पापुलेशन हमारे कृषक की है उसके लिए इसमें कुछ नहीं है। बागवानों के लिए तो शायद कुछ होगा, लेकिन कृषक के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

17.03.2016/1720/SS-DC/2

उपाध्यक्षः जय राम जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मज़ाक हो गया है। सत्र में बजट पर चर्चा हो रही है और उसके बावजूद यहां माननीय मंत्री सिर्फ एक बैठे हैं। यह सरकार का दायित्व होता है कि सभी उपस्थित हों। होना तो यह चाहिए कि तमाम मंत्री यहां पर उपस्थित रहने चाहिएं क्योंकि विपक्ष के विधायकों के पास एक यही अवसर होता है कि जब वे अपने प्रदेश/क्षेत्र से संबंधित मसले को उठाकर सदन में रखते हैं। लेकिन यहां एक को छोड़कर कोई मंत्री नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हम आज से नहीं देख रहे हैं बल्कि डे-वन से देख रहे हैं कि जिस दिन से माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण हुआ है उसके बाद कोई यहां पर रहता ही नहीं है। लंच करने के बाद चले जाते हैं। यह बहुत गलत बात लग रही है। मुझे लगता है कि इस बात को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात यहां पर सुनें। हम अपनी बात किसको सुनाएं जब यहां पर कोई होता नहीं है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यहां हमेशा होते हैं। इनकी बात सुनते हैं। जब बाहर भी चाय पी रहे थे तो इनकी बात पूरी सुनी जा रही थी। बाकी अधिकारी लोग बैठे हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। शायद आप भूल गये कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो हमने कई बार ऐसा माहौल देखा। उपाध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड देखा जा सकता है। हमने यह मामला उठाया था। यहां कोई मंत्री नहीं होता था। अधिकारी गैलरी खाली होती थी। यह विधान सभा के रिकॉर्ड से पता किया जा सकता है।

हम तो यहां तीन-चार मंत्री बैठे हुए हैं। आपको और कितने मंत्री चाहिए? सारे सदस्य बैठे हुए हैं। आपकी बात सुनी जा रही है। फिजूल की बातें न किया करो। आप फिजूल की बातें करते हैं।

उद्योग मंत्रीः माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहीं हैं, अनिल शर्मा जी भी यहीं हैं, शांडिल जी भी यहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग तो अपना कोरम भी पूरा नहीं करते थे और हमें भाषण का मौका तक नहीं देते थे।

उपाध्यक्षः अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

17.03.2016/1720/SS-DC/3

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिवः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 8 मार्च, 2016 को जो बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, प्रदेश के विकास के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाईं। उसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले तीन दिनों से लगातार यहां बजट पर चर्चा सुनने का मौका मिला। हमारे विपक्ष के लोग केवलमात्र विरोध करने के लिए बजट का लगातार विरोध कर रहे हैं। बार-बार इस बात को बोल रहे हैं कि इस बजट में कुछ कहने को है ही नहीं। इसमें विधायक निधि को बढ़ाया गया। इसका हम धन्यवाद करते हैं। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है वह माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से मिली है। उसका भी ये दबी जुबान से धन्यवाद करते हैं। ऐच्छिक निधि बढ़ी।

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1725/केएस/डीसी/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव) जारी----

कालिया जी ने ठीक कहा कि जो भी पैसा यहां बढ़ाया गया है, उसका ये हमारे ऊपर ही उपयोग करेंगें हालांकि बहुत से लोग एक करोड़ की राशि और ऐच्छिक निधि बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इसमें बी.जे.पी. के लोगों को भी फायदा होगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी

ने एक ही बात कही कि अगर बी.जे.पी. के भी लोग हैं तो है तो मेरे हिमाचल के। यह उनकी दरियादिली है जो यह ऐच्छिक नीधि व विधायक निधि बढ़ी । यह माननीय मुख्य मंत्री का एक बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष के बारे में न सोचते हुए सभी को बराबर का हक दिया। विपक्ष के लोग यहां बार-बार एक बात बोल रहे हैं कि कृषि का सत्यानाश हो गया। लोगों ने पशु छोड़ दिए लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश में जो मेहनतकश लोग हैं, पशु-पालक हैं, उन्होंने आज तक कोई पशु नहीं छोड़ा। केवल मात्र ऐसे लोग हैं जो टाईम पास के लिए पशु रखते हैं और जब उनसे उनका चारा पूरा नहीं होता और काम नहीं होता तो उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। अधिकांश पशु हमारे पड़ौसी राज्यों से आ रहे हैं। हिमाचल के लोग मेहनती है। आज भी कृषि कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, पोली हाऊस लगाए जा रहे हैं, कैश क्रॉप की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया है, हमारे लोग सब्जियां पैदा कर रहे हैं। एक समय था जब केवल मात्र कुफरी में, अप्पर शिमला में आलू उगाया जाता था लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर उग रहा है। हमारे ऊना में आज अधिकांश लोग आलू पैदा करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हुई, रिसर्च हुए। प्रदेश सरकार ने कृषकों के लिए, पशु-पालकों के लिए और बागवानों के लिए जो योजनाएं चलाई, लोगों ने उनको अपनाया। बागवानी में विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्में आईं, उनको अपनाया और उनके माध्यम से अपना जीवन-यापन चला रहे हैं, अपने बाग-बगीचों को भी लहरा रहे हैं। यह कह देना कि सत्यानाश हो गया, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जो हमारे अधिकारी है, चाहे पशु-पालन विभाग में हैं, होर्टिकल्चर विभाग में हैं हमारे क्षेत्र में तो वे निरन्तर कैम्प भी लगा रहे हैं, लोगों को किटें भी बांट रहे हैं, अवेयरनैस कैम्प के माध्यम से कैसे उन्नत किस्म का घास उगाना है, कैसे उन्नत किस्म की फसल लेनी है, मौसम के अनुसार कहां पर

17.03.2016/1725/केएस/डीसी/12

कौन सा बगीचा लगाया जाना चाहिए, समय-समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह कह देना कि सरकार कोमा में है, यह बिल्कुल गलत है। अरे, कोमा में तो आप लोग

तीन साल रहे। आप लोगों ने विधान सभा नहीं चलने दी। जैसे यहां सदन समाप्त होता है आप लोग अपने चुनाव क्षेत्र में जा कर प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि बस अगली पेशी में वीरभद्र सिंह अंदर हो रहे हैं और सरकार बी.जे.पी. की आ रही है। आपने लगातार तीन वर्षों तक यही किया। आपने कहा कि सरकार कोमा में थी। सरकार कोमा में नहीं थी। माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर आप लोगों ने इतना दवाब बनाया बावजूद उसके उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर उसका विकास किया। एक बार भी नहीं बैठे। हर काम उन्होंने दरियादिली से किया। यदि आप तीन वर्ष अच्छे से अपने सुझाव देते, सरकार के साथ तालमेल बिठाते तो शायद आपको आज यहां और भी नई-नई चीजें मिलती लेकिन आपने हमेशा विरोध करने की कोशिश की, रोड़ा अटकाने की कोशिश की। आप क्यों भूल जाते हैं कि इस प्रदेश का निर्माण डॉ0 वाई.एस. परमार ने किया 1971 में आप लोगों की विचारधारा बोलती थी, स्टेटहुड को मारो ठुड और आज आप हिमाचल के हितैषी बनते हैं। इस प्रदेश में ढाई सौ स्कूल हुआ करते थे, चंद किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, आज 35 हजार किलोमीटर सड़कें हैं। 18 हजार से ज्यादा स्कूल हैं, कॉलेजिज़ हैं। यह कोई चंद दिनों में नहीं बना है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पैदल घूम-घम कर प्रदेश की जनता के दुखों को समझा और उनके लिए योजनाएं बनाई और उनको क्रियान्वित किया और वह आज आपके सामने हैं। आप लोग तो बीच में आए और जो हमने बनाया उसको आपने खाया। उसको भी आप ठीक ढंग से संभाल कर नहीं रख सके। उसका भी आपने सत्यानाश किया। फिर दोबारा से जब हम वापिस आते हैं तो दोबारा से हमें उसको शुरू से ठीक करना पड़ता है और यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय की दरियादिली है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2016/1730/av/DC/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री इन्द्र दत्त लखनपाल)क्रमागत

और हिम्मत है कि विषम परिस्थितियों और सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने इस प्रदेश की जनता को बहुत कुछ दिया है। आप बोलते हैं कि कुछ नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 650 रुपये तक पहुंचा दिया। 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो अपने आत्म सम्मान की बात करते थे उनको मान-सम्मान मिला, क्या यह छोटी बात है? हमारे प्रदेश में जो महिलाएं कम उमर में विधवा हो जाती है उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1200 रुपये कर दी गई है। हमारी पंचायती राज संस्थाओं में जितने भी चुनकर आये हुए प्रतिनिधि हैं चाहे वह किसी भी दल से हैं उनका सबका मानदेय बढ़ाया गया है, क्या यह छोटी बात है? होम गार्ड का मानदेय बढ़ाया गया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने बजट में हर वर्ग को कुछ-न-कुछ दिया है। यहां पर यह कहना कि कुछ नहीं दिया, गलत बात है। देश के अंदर राजीव गांधी अन्न योजना शुरू हुई और हमारे प्रदेश के अंदर उसको लागू किया गया। आज उसका लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है तो क्या यह छोटी बात है? कौशल विकास भत्ते के रूप में नौजवान बच्चों को अपने कौशल की प्रतिभा निखारने का अवसर मिला है।

मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई-नई पी0एच0सीज0 खुली हैं, अपग्रेड हुई हैं। हैल्थ सब सैंटर खुले हैं तथा उनमें डॉक्टर्ज और नर्सों की भर्ती हुई है। यहां पर शिक्षा के क्षेत्र की बात हुई और विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक ही राग अलापा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नये-नये स्कूल खोले/अपग्रेड हो रहे हैं ये नहीं खोले जाने चाहिए। यहां यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र से दो जज बनें। दो लड़कियां डी0एस0पी0 बनीं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ी। इंजीनियर बनें जो सरकारी स्कूलों से पढ़कर जा रहे हैं। यह कहना कि सारे ही स्कूलों का एक जैसा हाल है, ऐसा नहीं है। कुछ इक्का-दुक्का हो सकता है मगर हमारे सभी टीचर्ज ट्रेन्ड हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। गुणात्मक शिक्षा देने में हमारा रुतवा बढ़ा है। नई खुली आई0टी0आई0 में हमारे बच्चों को अपनी प्रतिभा के अनुसार मौका मिल रहा है। उनको दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरियां मिल रही है। यह कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह गलत बात है।

17.3.2016/1730/av/DC/2

इस बार आई0पी0एच0 विभाग को स्ट्रेन्थन करने के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक बजट रखा गया है। इस विभाग के तहत नये हैंड पम्प्स लगे हैं, पुराने हैंड पम्पों की रिपेयर हुई है तथा इसमें मोटरयुक्त हैंड पम्प भी लगे हैं। यह अलग बात है कि जैसे यहां पर पीलिया के बारे में चर्चा हुई कि शिमला में पीलिया फैला। इससे पहले भी फैला था। यह भी सच बात है कि बीच में कुछ-न-कुछ कमियां रहती हैं। मगर इसमें यदि हम सरकार की फैल्योर बोलें तो गलत बात है। अभी आई0पी0एच0 के पानी की बात हो रही थी कि पानी स्वच्छ नहीं है। आई0पी0एच0 विभाग हर स्कीम का क्लोरिनेशन करता है। पानी में दवाइयां डाली जाती है। लोगों को इसके प्रति जागरुक किया जाता है और उनको किट्स बांटी जाती है कि आपने अपना रख-रखाव कैसे करना है। मगर इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद आज लोग भी थोड़े लथार्जिक हो गये हैं। मगर हमें अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखने की जरुरत है।

यहां पर पोलीथीन को किसने खत्म किया? इस प्रदेश को पोलीथीन मुक्त करने के लिए यह योजना माननीय वीरभद्र सिंह जी ने लाई थी। यहां ऐक्ट लाया गया और वह लागू हुआ और हमारी पहाड़ियां बची। यदि आज जनसंख्या के घनत्व और लोगों के रहन-सहन को देखा जाए तो उसमें केवलमात्र सरकार की ही कमी नहीं है जागरुकता की भी कमी है। हमारे समाज में लोगों को जागरुक करने की जरुरत है कि कूड़े को कैसे ठिकाने लगाना है। यह केवलमात्र सरकार का ही काम नहीं है यह हम सबका काम है। सब करते होंगे और हम भी अपने-अपने क्षेत्र में करते हैं। लोगों को जागरुक करते हैं कि पानी का रख-रखाव कैसे करना है।

टीसीद्वारा जारी

17.03.2016/1735/TCV/DC/1
मुख्य संसदीय सचिव(श्री इन्द्रदत्त लखनपाल)---- जारी।

दूसरी बात जहां तक आवारा पशुओं की बात है, मैं माननीय मंत्री श्री अनिल शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपने घर से शुरूआत की है। यह निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो आवारा पशुओं का कृषकों में भय बना रहता है उनके लिए एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना की भी शुरूआत होगी हालांकि मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में अभी बिजली वाली तो नहीं लेकिन बाड़ीकरण के लिए अपनी विधायक निधि से पैसा दिया है और मैंने अपने ही विधान सभा क्षेत्र में लगभग 7 गऊशालाएं खुलवाई है तथा लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे नौजवान बच्चे जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं उसमें हमारे परिवारों की भी कमी है जब तक हमारे नौजवान बच्चों को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, खेत में काम करने वाले बच्चे की पीठ नहीं थपथपाएंगे, वह खेत में काम नहीं करेगा। हमने अपने बच्चों को मौम की गुडिया बना दिया है। खेत तक तो हमारी नई जनरेशन के बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं तो वह क्या खेती-बाड़ी करेगें। अगर आज खेतों में कोई काम कर रहा है तो वह कोई रिटायर्ड पर्सन हैं या कोई रिटायर्ड फौजी हैं वे काम कर रहे होते हैं और हमारे बच्चे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाहर चले जाते हैं। इसके लिए भी एक सोच को डेवैल्प करने की जरूरत है, अपने बच्चों को मान-सम्मान देने की जरूरत है, उसको 'बेकार' की संज्ञा से बाहर निकालने की जरूरत है। पढ़-लिखकर बच्चे को अगर कोई खेत में काम करता हुआ देख लेगा तो उसको बोलेगा कि तू इतना पढ़ गया है फिर खेत में काम क्यों कर रहा है। ये सारी समस्याएं हैं इसके बारे में भी सोच होनी चाहिए। सरकार की तरफ से हर क्षेत्र में यथासंभव सहायता की जा रही है। चकोतादार, पट्टाधारकों की समस्या का हल करने के लिए जो 40 वर्षों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे इस बज़ट के अन्दर उसका प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा। एच0आर0टी0सी0 को घाटे से उभारने के लिए मु0 250 करोड़ रूपये की रकम दी है और पी0डी0एस0 सिस्टम के माध्यम से सस्ता राशन मिल रहा है और प्रदेश के अन्दर लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अन्य प्रदेशों में जाकर देखिए क्या हालत है? आपने तो आज यह कहा कि युवाओं को ठग्गा लेकिन ठग्गा तो मोदी जी ने है, उन्होंने 100 दिन के अन्दर 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा

17.03.2016/1735/TCV/DC/2

किया था, 100 दिन के अन्दर महंगाई खत्म करने की बात कही थी, वह वायदें कहां गये? राजीव गांधी जी का नाम तो आप लोग मजबूरी से लेते हैं अगर आज आप आई0टी0 युग की बात करते हैं तो राजीव जी का धन्यवाद करना चाहिए। ये लैपटॉप जो आज हमारे सामने लगे हैं, पंचायतीराज के माध्यम से जो आप लोग बहुत दनदनाते हैं और 18 साल के नौजवानों को वोट का अधिकार दिया है ये सब राजीव गांधी की देन है। इस प्रदेश के अन्दर हरित क्रान्ति लाई वह इन्दिरा गांधी ने लाई, पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की वह ज्वाहर लाल नेहरू जी ने लाई। आप लोग तो इनका नाम तक नहीं लेना चाहते। मनरेगा की आप बात करते है, मनरेगा के अन्दर केन्द्र से पिछले वर्ष हमें जो 746 करोड़ रूपया सैंक्शन हुआ था लेकिन उसके एवज़ में हमें 258 करोड़ रूपया ही आया। उसके बाद 60 परसेंट यू0सी0 14-15 अक्तूबर तक देने का टाईम दिया गया था, लेकिन मैं श्री अनिल शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा कि इनके विभाग ने 80 परसेंट यू0सी0 14 सितम्बर से पहले ही वहां पर जामा करवा दिए और आप बोलते हैं कि यू0सी0 नहीं गये। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? मनरेगा में कट लगा दिया। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तो लोक सभा के अन्दर कहा कि मनरेगा को प्रतीक चिन्ह बनाउंगा। ये देश के लिए अभिषाप है, फिर उन्होंने इसके लिए 58 हजार करोड़ रूपया क्यों रख दिया? वे समझ गये कि जब विदेश के लोग हमारे देश में ये देखने आये कि 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार इतनी बड़ी आबादी को कैसे मिल रहा है तो वह भी हैरान हुए। ये मनमोहन सिंह जी की देन है।

श्री गर्ग जी द्वारा---- जारी

17/03/2016/1740/RG/AS/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री इन्द्रदत्त लखनपाल)----क्रमागत

---(व्यवधान)--- उन्हें बात समझ में आई, बिहार में हार हुई, फिर उन्हें मनरेगा याद आया, एक बात और सुनिए वह जो मोदी जी ने 58 हजार करोड़ रुपये इस देश में दिया, वह कहां-कहां लगेगा, हमें भी मालूम है। वह सारा गुजरात जैसे प्रदेशों में जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां उन्होंने बांटना है। हमारा जब पिछला पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अगले की तो उम्मीद ही नहीं है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है। आज चालीस हजार करोड़ रुपये देने की बात करते हैं, लेकिन वह आया कहां? जब आएगा, तब देखेंगे। इससे पहले यू.पी.ए. सरकार के समय में माननीय पूर्व

मुख्य मंत्री श्री धूमल जी बुके लेकर दिल्ली जाते थे और वहां से वे सारी स्कीमें लेकर आते थे और परवाणु में आकर कहते थे कि केन्द्र की सरकार भेदभाव कर रही है। हमारे जो मंत्री दिल्ली में यू.पी.ए. सरकार में होते थे, प्रदेश में आकर योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करते थे। आप लोग स्वां चैनेलाइजेशन का हाल देख लीजिए, उसके पैसे आपने रोक दिए, मनरेगा के पैसे आपने रोक दिए, जो गरीब लोगों को बी.पी.एल. लोगों को मकान बनाने के लिए जो पैसे मिलते थे उसमें कट लगा दिया, सिंचाई की स्कीमें बंद कर दीं। आप 90:10 की बात कर रहे हैं, तो वह तो हमारा अधिकार है। वह पहले भी मिलता रहता था, वह तो इन्दिरा गांधी के समय से मिलता है। उनके समय से हमारा अधिकार था जो हमें मिलता था। आपने तो पिछले दो साल से उसको बंद किया हुआ था। अगर आज दे दिया, तो हमारे ऊपर कोई ऐहसान नहीं किया है। वह हमारा हक़ है, वह हमारी मांग थी जो आपने दिया है। उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय और हमारे यहां के मंत्रियों ने पत्र लिखे तब उनको मजबूरन देना पड़ा। अन्य पहाड़ी प्रदेशों का दबाव पड़ा, तब उनको देना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ये योजनाएं बदलने की बात करते हैं, तो क्या आज के प्रधानमंत्री जी योजनाएं नहीं बदल रहे हैं? वे भी तो बदल रहे हैं। जब आप यहां बैठे थे, तो आपने भी योजनाएं बदलीं। आपने राजीव गांधी विद्युत योजना का नाम बदल दिया, 108 योजना का नाम आपने बदल दिया। आपने भी अपने समय में बड़ा कुछ किया। इसलिए यह तो चलता रहता है, लेकिन यह कहना कि इस बजट में कुछ नहीं है। तो इसमें बहुत कुछ है, सब कुछ दिया है और इस प्रदेश की जनता के लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने जो बजट बनाया है, यह उनकी सोच और मेहनत है। वे रात-दिन प्रदेश की जनता के बारे में सोचते हैं और

17/03/2016/1740/RG/AS/2

उस सोच को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उनके लाभ के लिए यह बजट दिया है। इसलिए आप इस बजट के बारे में चिन्ता न करें। आपको यह डर लग रहा है कि अब इनको सातवीं बार मुख्य मंत्री बनना है। इनको मुख्य मंत्री बनने से कैसे रोका जाए? जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, ये रुक नहीं सकते। आपके सपने धराशायी होंगे और हम लोग यहीं बैठेंगे। आप में से बहुत कम वहां बैठेंगे। सातवीं बार हमारे मुख्य मंत्री बनेंगे और प्रदेश की जनता बनाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के पक्ष में माननीय मुख्य मंत्री जी का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उन्होंने कर्मचारियों को डी.ए. की किस्त के अलावा अंतरिम राहत भी दी है। मैं तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने भी काफी मेहनत करके यह बजट बनाया है। लेकिन फिर भी जो सुधार की गुंजाईश है उस बारे में एक-दो बातें कहना चाहूंगा। हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए क्योंकि उनका बहुत ज्यादा काम रहता है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऑऊटसोर्सिंग के ऊपर नौकरियों को बंद करने का किया है। इस बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। यह एक बहुत बड़ा कदम मुख्य मंत्री जी ने उठाया है। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने कितनी कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद इस बात का निर्णय लिया होगा। लेकिन यह हमारे पहाड़ी प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने यह ऑऊटसोर्सिंग पर नौकरियां देने वाला 31 मार्च के बाद काम बंद कर दिया है। इन्होंने कितने लोगों को पदोन्नतियां दीं? आपके समय में पदोन्नति ही कोई नहीं मिलती थी। आप लोगों ने अपने पांच साल में कोई भर्तियां ही नहीं कीं और आज हजारों के हिसाब से कर्मचारियों को पदोन्नतियां मिल रही हैं। नई भर्तियां हो रही हैं, 13,000 भर्तियां करना अगले वर्ष में प्रस्तावित है। पी.टी. टीचर, ड्रॉइंगमास्टर, डी.पी.ई. टीचर जो हमारी मांग थीं उनको हमारे मुख्य मंत्री जी ने माना है और इस सबके लिए आप सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। 'पैट' वालों को नियमित किया, पी.टी.ए. के टीचर्स को कॉन्ट्रेक्ट में बदला, आप लोगों ने तो उनको भी घोड़े मारकर दौड़ा दिया था। तो ये सारी बातें उन्होंने की हैं और बहुत ही दरियादिल से इस बजट को बनाया है जिससे प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा, सभी क्षेत्रों का विकास होगा।

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1745/MS/DC/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी-----

हमारे सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने इस बजट का समर्थन किया है। मेरा आप लोगों से भी आग्रह रहेगा क्योंकि दिल से तो आपको भी लग रहा है कि यह बजट बहुत अच्छा है लेकिन जो आप यहां बातें कर रहे हैं वह हमें समझ नहीं आ रही हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप भी इसका समर्थन करें। उपाध्यक्ष जी, आपने बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

17/03/2016/1745/MS/DC/2

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री गोविन्द राम शर्मा जी भाग लेंगे।

श्री गोविन्द राम शर्माः उपाध्यक्ष जी, जो आदरणीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी ने 08 मार्च, 2016 को वर्ष 2016-17 के लिए बजट यहां पेश किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
मेरे से पूर्व बहुत से वक्ताओं ने इस पर अपने विचार यहां रखे हैं। जो कुछ बातें इसमें अच्छी हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं और जो गलत है उसका विरोध भी करता हूं। यह बात ठीक है कि विधायकों की विधायक निधि 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई है। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि इसको बढ़ाने का और प्रयास करे। दूसरा, एक बहुत बड़ा काम जो मैं समझता हूं कि विधायकों के लिए किया है, वह ऐच्छिक निधि का किया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि उसको भी कम-से-कम छः लाख रुपये यदि कर दें तो हम आपके आभारी रहेंगे।

इसी तरह से जो विधवा पैंशन, अपंग पैंशन और बुजुर्गों की पैंशन बढ़ाई है, यह अच्छी बात की है। लेकिन यह पैंशन का सिलसिला भी वर्ष 1977 में हमारी सरकार ने ही शुरू किया था। आपने इस बार इसमें आगे बढ़ने का थोड़ा प्रयास किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विधवाओं के लिए वह पैंशन बहुत कम है। मैं अपने क्षेत्र में कई जगह गया हूं और मैंने देखा है कि बहुत सी 22 साल या

24 साल की बच्चियां विधवा हो गई हैं। उनके साथ में एक-एक या दो-दो बच्चे भी हैं। अगर उनकी स्थिति देखें तो यह पैंशन कम है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पर पुनः विचार करे।

अभी माननीय सदस्य इन्द्रदत्त लखनपाल जी ने ठीक कहा कि आशा वर्कर्ज और आंगनवाड़ी वर्कर्ज के मानदेय में भी कुछ-न-कुछ वृद्धि की जाए, उनका भी ध्यान रखा जाए।

सत्ता पक्ष के लोग अभी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि कर्मचारियों के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ दे दिया। आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मेरा कहना है कि कर्मचारियों का इस सरकार ने शोषण किया है और कर्मचारियों के पक्ष में

17/03/2016/1745/MS/DC/3

कोई निर्णय नहीं लिया है। जो पंजाब सरकार ने वर्ष 2006 में स्केल दिए थे उसमें आपने 4-9-14 को भी पंजाब से डैफर किया। इतना ही नहीं जो अनुबंध पर लोग लगे हैं उनको आप पांच साल में रेगुलर कर रहे हैं। करूणामूलक आधार पर विडो या उसके परिवार के किसी सदस्य को यदि नौकरी पर लगाया जाता है तो उनको सात साल बाद आप नियमित करते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनको भी अनुबंध वालों की तरह पांच साल बाद नियमति किया जाए क्योंकि उसमें विधवा बहनें और विधवा बच्चियां या उनके परिवार के लोग हैं। इसलिए उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

आप लोग कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। आदरणीय बाली जी अभी सदन में नहीं है। परिवहन विभाग में जो कर्मचारी रिटायर हुए, उनको तीन-चार महीने से पैंशन नहीं मिली है। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन्हें मेडिकल बिल के पैसों का भुगतान आज तक नहीं मिला है। उनको रिटायर हुए एक से डेढ़ साल का समय हो गया है इसलिए उनके लिए अब अपने परिवार का गुजर-बसर करना मुश्किल हो चुका है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत उपलब्धियां की हैं। क्या ये उपलब्धियां हैं? मेरा सरकार से आग्रह है कि उनके बारे में चिन्ता की जाए। उनकी जो पैंशन है वह तुरन्त उनको दी जाए और उनके मेडिकल बिलों का भुगतान भी शीघ्र किया जाए। ऐसे ही अनेकों बहुत सी बातें हैं। मैं एक और निवेदन करूंगा। जैसे आपने विधवाओं की पैंशन को बढ़ाया है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1750/जेएस/डीसी/1

श्री गोविन्द राम शर्माः-----**जारी**------

वैसे ही मज़दूर सबसे निम्न स्तर का आदमी और दैनिक भोगी कौन है? दैनिक भोगी तो वही है जो करूणामूलक आधार पर लगे, वे विधावाएं हैं या दूसरे उनके परिवार के बच्चे हैं वे दैनिक भोगी हैं। बाकी तो दैनिक भोगी कोई नहीं लगता। उनके लिए केवलमात्र आप 20 रूपए बढ़ा रहे। उनके लिए कम से कम अगर बढ़ाना होता तो 50-100 रूपए बढ़ाते तो उनके लिए भी उनके परिवार के पालन-पोषण के लिए कुछ राहत मिलती इसलिए उस पर भी सरकार विचार करें। यहां पर अभी आई0पी0एच0 की बात कर रहे थे। आई0पी0एच0 विभाग में कल श्री इन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि जो गांवों में वॉटल सप्लाई की स्कीमें बनी उनके लिए फिल्टर भी बनें हैं । लेकिन किन्हीं कारणों से आपने प्राईवेट में दे दिए और प्राईवेट वाले फिल्टर के माध्यम से काम नहीं कर रहे हैं और कई जगह फिल्टर ही नहीं लगे। उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यही कारण है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। इससे पीलिया हो रहा है। इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टाफ की कमी आई0पी0एच0 विभाग में, विद्युत विभाग में, शिक्षा विभाग में और ट्रांसपोर्ट विभाग में तो बहुत ही कमी है। उसमें कर्मचारियों की और अधिकारियों की कमी है। श्री कौल सिंह ठाकुर जी यहां पर बैठे हैं इनके विभाग में भी डॉक्टर्ज और फार्मासिस्ट्स की बहुत ज्यादा कमी है। मेरे वहां एक दिग्गल बहुत ही इंटीरियर इलाका है। ठाकुर साहब से भी मैंने बात की थी कि वहां पर कोई भी डॉक्टर और फार्मासिस्ट नहीं है। केवल क्लास-IV वहां पर बैठे हैं बाकी कोई भी नहीं है। वैसे ही अर्की में है जब हमारी सरकार थी तो अर्की हॉस्पिटल में 9-9 डॉक्टर्ज़ होते थे। वहां पर आज केवल दो डॉक्टर हैं। ठाकुर साहब इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अर्की का विशेष ध्यान रखें और जो इंटीरियर इलाका दिग्गल है वहां पर भी डॉक्टर तुरन्त भेजें। मुकेश जी आपने भी एक ठगी की है। आपने ठगी यह कर दी कि जब

चुनाव आया तब तो आपने युवाओं को बोला कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप हमारे को वोट दो। नौज़वान आप लोगों के झांसे में आ गए, बहकावे में आ गए और आप लोगों को वोट दे दिया और

16.03.2016/1750/जेएस/डीसी/2

आपकी सरकार बना दी, लेकिन आपने उनके साथ ज्यादती कर दी। आपने वह बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उसके लिए आप मुकर गए। उस पर भी आपको चिन्ता करने की आवश्यकता है। पहले आपने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे तब सत्ता में आए। इस बार कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे तब सत्ता में आए। अगली बारी क्या होगा यह तो आपको पता है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें कहा गया कि हम वर्ष 2022 तक स्वच्छ पानी देंगे। फिर आपने कहा कि वर्ष 2022 तक 4 हजार सड़कों की मैटलिंग/टारिंग करेंगे। वह सड़कें आप स्टेट से करवाएंगे या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करवाएंगे। वह योजना आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। आज हमारे चुनाव क्षेत्र में जो काम चला है फील्ड में काम चला है उसमें स्टेट बजट से कुछ नहीं हो रहा है। उसमें तो केवल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही काम हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो भी काम चलें हैं वे काम आदरणीय अटल जी ने जो इस देश के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना लोगों को दी उसमें काम चले हैं। उसी से मैटलिंग/टारिंग हो रही है । उससे ही फेज़-। और फ़ेज-॥ का काम चला है । प्रदेश सरकार की तरफ से मैं समझता हूं कि जीरो काम हो रहे हैं। हमारा रामशहर से जो रोड़ आया उसके बारे में मैंने असैम्बली में प्रश्न किए और यहां पर कई दफ़ा कहा कि रामशहर से ज़ाबल तक का रोड़ बिल्कुल टूटा-फूटा है। उसमें 8 सालों से कोई मैटलिंग/टारिंग नहीं हुई। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्या यह आपकी भी है और हमारी भी है। इसमें कोई राजनीति भी नहीं है। इसमें हम आपको भी दोष नहीं दे सकते हैं। इसमें हम सभी को प्रयास करना चाहिए। बंदरों का और जंगली जानवरों का जो आतंक है उसमें बड़ी दिक्कत आ

रही है। आपको भी आ रही है और हम लोगों को भी आ रही है। उसके लिए कुछ न कुछ योजना बनाने की आवश्यकता है। बन्दर तो घरों से रोटी भी ले जाते हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

17.03.2016/1755/SS-DC/1

श्री गोविन्द राम शर्मा क्रमागतः

और ऐसे ही जंगली जानवर हैं जो फसल बीजते हैं उसको खराब कर देते हैं। इसलिए हमारे तो कई जगह किसानों ने फसल बीजनी छोड़ दी। मक्की, कनक बीजनी छोड़ दी। उसके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता है और कोई-न-कोई इसके लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम भी समर्थन कर सकते हैं। हम उसके लिए अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें हम सब को चिन्ता करने की आवश्यकता है।

एक जो हमारी सड़कें हैं उनकी डी0पी0आरज़0 पिछले तीन सालों में कहीं नहीं बनीं। अगर बन गईं तो इ0एन0सी0 ऑफिस तक है या प्लानिंग तक होंगी। लेकिन आज तक नाबार्ड से सैंक्शन नहीं हुई। सिंचाई की कोई स्कीम आज तक नहीं बनी जबकि अब मौसम चेंज हो रहा है। इसमें हम सब को चिन्ता करने की आवश्यकता है। बरसात का पानी हम सब लोग इकट्ठा करें। बड़े-बड़े डैम प्रॅपोज करें। हमने उसे एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में भी डाला। उससे एक तो वह पानी सिंचाई के काम आयेगा और दूसरे जब उसमें रिसाव रहेगा तो वह पीने के पानी के लिए भी हमारे लिए लाभकर होगा। अगर सरकार इस तरफ चिन्ता करेगी तो उसका लाभ हो सकता है। डी0पी0आरज़0 बनाएं, नाबार्ड से पैसा आये तो उससे किसानों को भी लाभ हो जायेगा और आपकी टैंशन भी खत्म होगी। बहुत-सी सड़कें जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में हैं या बीच में कोई एकाध सड़क ऐसी भी है जो नाबार्ड के तहत हमने एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डाली है उसमें फॉरैस्ट केस कई-कई वर्षों से लटके हुए हैं। उसमें विभाग कुछ काम करे। विभाग भी टाल-मटोल करता है। सरकार उसमें कोई दिशा-निर्देश दे, कोई हाई लेवल कमेटी बनाए जिसकी 15 दिन या एक महीने या तीन महीने में मीटिंग हो जाए चाहे वह चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर या चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में हो ताकि वह काम सुचारू रूप से हो सके तथा फॉरैस्ट केस की क्लीयरैंस मिल सके। एक बार मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से प्लानिंग की मीटिंग में कहा था कि ट्रांसपोर्ट नगर हमारे

अर्की के लिए दिये जाएं क्योंकि दो-दो उद्योग वहां हैं। एक जे0पी0 सीमेंट उद्योग है और दूसरा अम्बुजा है। ये हैं तो लुटेरे। इसमें कोई दो बात नहीं है। मुकेश जी, वहां बहुत बुरे हाल अम्बुजा ने किये हैं। लोगों से लैंड ली है आज तक उसके पैसे नहीं दिये हैं। 1994, 1995, 1996 में उन्होंने लैंड तो एक्वायर कर ली,

17.03.2016/1755/SS-DC/2

कागज़ों में सब कुछ हो गया लेकिन लोगों से पूछा तक नहीं गया, इसलिए लोगों ने जमीन नहीं छोड़ी। लेकिन जो अभी तक जमीन नहीं छोड़ रहे, जिनको उसके पैसे नहीं मिले उन लोगों पर पुलिस केस बनाकर अरैस्ट करवाया जा रहा है। एक तो मांगू का जो आज की डेट में उप-प्रधान है वह इलैक्टिड है। उस व्यक्ति को आपके डी0एस0पी0 ने तुरन्त अरैस्ट कर दिया। दूसरे दिन छोड़ा। ऐसा आतंक वहां फैलाया हुआ है। जो आपका डी0एस0पी0 वहां पर है वह अम्बुजा के लिए एक निजी नौकर की तरह काम कर रहा है। इसलिए चिन्ता करने की आवश्यकता है। वहां स्थानीय लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। उनको तंग किया जा रहा है। अगर ऐसे अधिकारी हैं तो उन पर ऐक्शन होना चाहिए। वहां उद्योग लगें हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन वहां की स्थानीय जनता की भी चिन्ता करनी चाहिए।

किसी भाई ने कहा, शायद बिक्रम सिंह जी बोल रहे थे कि एम0ओ0यू0 साइन हुए कि उद्योगों में 70 प्रतिशत हिमाचली नौकरी में लगेंगे। असलियत यह है कि वहां 30 परसैंट भी हिमाचली नहीं लगे हैं। उसके बारे में किसने चिन्ता करनी है। सरकार ने चिन्ता करनी है। अगर हिमाचली नहीं लगे तो उसका कारण क्या रहा? यह कारण नहीं है कि आपके पास आ गया, मिल गया, बैठ गया या बातचीत हो गई, कारण यह है कि जिस जनता ने आपको चुन कर भेजा है --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाईये। अभी लिस्ट में बोलने वाले पांच माननीय सदस्य और हैं। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन की बैठक एक घंटे के लिए और बढ़ा दी जाए? सात बजे तक बैठक बढ़ाते हैं और सभी माननीय सदस्यों को दस-दस मिनट का समय मिलेगा।

(माननीय सदन की बैठक 7:00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

गोविन्द राम जी, अब आप जारी रखें।

श्री गोविन्द राम शर्माः हम सब को जनता ने चुनकर भेजा है। अगर जनता के हितों की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते तो हमारा मंत्री या विधायक बनकर यहां बैठने का औचित्य क्या है? इसलिए वे भी हमारे भाई हैं। उनकी चिन्ता करना हम सब का कर्तव्य बनता है।

17.03.2016/1755/SS-DC/3

अब प्रदूषण की बात है। मुकेश जी, कभी आपने मेरे साथ चलना। एक बार ट्रांसपोर्टर्ज़ ने आपको निमंत्रण भी दिया था। लेकिन आपको उस दिन कोई काम पड़ गया उस वजह से आप नहीं आ सके। मैं वहां गया था। उस दिन हम चाहते थे कि आपको भी बताते कि अम्बुजा वाले व दूसरे लोग कर क्या रहे हैं? कितना प्रदूषण है। थोड़ा-सा पांच मिनट का पैदल चलने का रास्ता है वहां पर आपको चलाकर बताते कि कितने बुरे हाल हैं। बहुत बुरे हाल हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है। लोगों को पूछा नहीं जा रहा। ट्रक ऑपरेटरों की आज तक पेमैंट नहीं की जा रही है।

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1800/केएस/डीसी/1

श्री गोविन्द राम शर्मा जारी----

वह चाहे जे.पी. है चाहे अम्बुजा है। बहुत बुरी स्थिति है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप उद्योग मंत्री है, इस बारे में चिन्ता करें ताकि लोगों को लाभ मिल सकें।

उपाध्यक्ष जी, बसों की चिन्ता करने की आवश्यकता है । केन्द्र सरकार से आपको 800 बसें आई । मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं लेकिन हमारे यहां तो बसें जो पुरानी लगी थी वह भी बंद कर दी, नई बसें तो क्या मिलनी। सरकार से निवेदन है कि इस बारे में चिन्ता करें क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में बसों की बहुत कमी है। स्कूल कॉलेज के बच्चों को बसों की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में पिछली बार आदरणीय महेन्द्र सिंह जी परिवहन मंत्री थे। उन्होंने हमें अर्की के लिए एक सब डिपो दिया था। आज

मुकेश जी वहां पर यह स्थिति हो चुकी है कि वह डिपो भी बंद हो गया है ओर जो वहां पर एरिया मैनेज़र लगाया था, उसकी भी ट्रांसफर हो चुकी है। स्टाफ भी ट्रांसफर हो गया, मशीनरी भी ट्रांसफर हो गई और वह डिपो बन्द हो गया है। वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां पर बस स्टैंड भी अच्छा बने, डिपो भी दोबारा से खुले इस पर भी सरकार ध्यान दें।

उपाध्यक्ष जी, मुझे अच्छा लगा कि बहुत से स्कूल खोले जा रहे हैं और कईयों ने कहा कि ऐसे भी सकूल हैं जहां पर कोई बच्चा ही नहीं है, यह मुझे जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा हुआ होगा तो वह तो स्कूल खोलने वालों को देखना चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में घड़याच हाई स्कूल है मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी और उससे पहले भी जब-जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय अर्की आए, वहां भी अपना पक्ष रखा। उस स्कूल को प्लस टू करने का निवेदन किया था और प्लांनिंग की मीटिंग में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आप लिख कर दे दो तो मैंने उसी वक्त लिख कर भी दे दिया था। मेरा आपसे निवेदन है कि घड़याच स्कूल और लगदाघाट स्कूल, जहां-जहां आवश्यकता है, और भी ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो बहुत दूर-

17.03.2016/1800/केएस/डीसी/2

दूर हैं, हमारी बच्चियां वहां पढ़ने जाती है, उनको सुविधा हो जाए तो उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक दानोंघाट से दाड़लाघाट के लिए सड़क है, आप सभी वहां से जाते हैं। वह बहुत तंग रोड़ है। वहां तक तो अच्छा हो गया, उससे आगे उसको चौड़ा नहीं किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसमें भी तुरंत वाइडनिंग का काम हो। टैण्डर उसके हो गए थे, फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं मिली है ।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर हैंड पम्प की बात आई। अभी आपने 50 करोड़ उसके लिए रखा। आप बोल रहे हैं कि 2 हजार हैंड पम्प लगेंगें। मैं देख रहा था कि अगर ढाई सौ रुपये भी एक हैंड पम्प के लगते हो तो वह तो 1500-1600 के करीब भी नहीं बनते और जो

पुराने हैंड पम्प हैं वे मेरे चुनाव क्षेत्र में तो सारे के सारे खराब पड़े हैं बाकियों का मुझे पता नहीं। उनकी अगर रीपेयर हो जाए और नए हैंड पम्प ठीक ढंग से लग जाए तो पानी की आवश्यकता कुछ कम हो सकती है। एक 30 करोड़ रु0 की स्कीम थी, आदरणीय धूमल जी ने और रविन्द्र सिंह रवि जी उस समय मंत्री थे, इन्होंने उस समय उसका शिलान्यास किया था, चार साल हो गए अभी तक वह कम्पलीट नहीं हुई। मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरन्त उसका काम पूरा करें ताकि लोगों को उसका लाभ हो सके।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री गोविन्द राम शर्माः उपाध्यक्ष जी, मैंने तो अभी 18 मिनट ही बोला है और बाकी लोग तो आधा-आधा घण्टा भी बोल गए लेकिन आपका आदेश है तो कहना चाहूंगा कि यह बजट कर्मचारी विरोध बजट है, बागवान-किसान विरोधी बजट है, दिहाड़ीदार मज़दूर व अन्य लोगों का विरोधी बजट है इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अगले वक्ता अ0व0 की बारी में---

17.3.2016/1805/av/DC/1

श्री संजय रतन : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2016-17 के लिए इस मान्य सदन में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस मान्य सदन में 19वां बजट प्रस्तुत किया है। वे देश के चुनिन्दा मुख्य मंत्रियों में से हैं जिन्होंने वित्त विभाग को अपने पास रखा और जिनको मान्य सदन में बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला। मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं बावजूद इसके कि हिमाचल प्रदेश के साधन सीमित हैं। सीमित साधनों के होते हुए जिस तरीके से इन्होंने ये बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं वह काबिले तारीफ है। इसमें हर वर्ग को कुछ-न-कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है। हर क्षेत्र में मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश की है। यहां पर माननीय

सदस्यगण कह रहे थे कि इस बजट में बोलने के लिए कुछ नहीं है जबकि दिल से ये सारे इस बजट का समर्थन करते हैं क्योंकि इस बजट में गरीब इनसान से लेकर विधायक तक कुछ-न-कुछ दिया गया है। आगे भी उम्मीद है कि इनको भविष्य में भी कुछ-न-कुछ मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने विधायक विकास निधि को पिछले साल 50 लाख रुपये से 75 लाख रुपये किया और सभी विधायकों के आग्रह पर बिना किसी भेदभाव के इस बजट में उसको एक करोड़ रुपये किया। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक निधि जब वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनी तो शुरू की थी। पहले दो लाख रुपये फिर पिछले साल उसको 4 लाख रुपये किया तथा इस साल उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया है। इसके लिए मैं सभी विधायकों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवदेन करना चाहूंगा कि अगर बढ़ा सकें तो इसको 6 लाख रुपये कर दिया जाए क्योंकि पिछले साल भी आपने दो लाख रुपये से बढ़ाकर इसको 4 लाख रुपये किया था। अब सभी विधायक चाहते हैं कि इसको इस साल भी एक लाख रुपये की बजाय दो लाख रुपये बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जाए। राजा वीरभद्र सिंह

17.3.2016/1805/av/DC/2

जी इस बार छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं और इसको 6 लाख रुपये किया जाए, मेरा इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा।

कृषि के क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने बजट में जो आवारा पशुओं को रोकने के लिए मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना आरम्भ की है और इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि स्वागत योग्य कदम है।

टीसी द्वारा जारी

17.03.2016/1810/TCV/AS/1
श्री संजय रतन ---- जारी

खेतों में हम बीच तो बीजते हैं मगर उसका कटान नहीं कर पाते, आवारा पशु खेतों को ऊजाड़ देते हैं उस चीज को रोकने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक पहल की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ जब बाड़बन्दी होगी और हमारे कृषक खेती करेंगे/सब्जियां ऊगाएंगे तो मार्किट यार्ड बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10 करोड़ रूपये का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया है वह भी काबिले तारीफ हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए सुक्ष्म सिंचाई योजना जो राजीव गांधी के नाम से रखी गई है उसके लिए भी 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। सिंचाई योजनाओं में जो 50 प्रतिशत उपदान देने की बात की है वह भी एक बहुत अच्छी योजना है। हमारी कुछ सोशन ओब्लिगेशन्ज है और पहली बार इस बज़ट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बी0पी0एल0 के गरीब परिवारों के लिए जो स्वर्ण जाति से संबंध रखते थे, उनके लिए घर बनाने के लिए 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है वह भी बहुत ही काबिले तारीफ है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जहां विधायकों की विधायक निधि और ऐच्छिक निधि को बढ़ाया है और अभी हाल ही में पंचायतों के जो चुनाव हुए है, उन चुनावों में हमारे जो प्रतिनिधि जीत कर आये हैं, उनका भी मानदेय बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश में जो नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हमारे प्रतिनिधि चुनकर आये है, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंधित है उनका मानदेय को भी बढ़ाया है,उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 'मुख्य मंत्री सड़क योजना' का शुभारम्भ इस बजट के माध्यम से किया है और लगभग 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान इस वर्ष के लिए किया है। हर गांव को सड़क के साथ जोड़ने का प्रयास माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट के माध्यम से किया है, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। रज्जू मार्गों और सिनेमाघर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10 प्रतिशत कर करके उसको कम किया है, कुछ नये रज्जू मार्ग माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने

17.03.2016/1810/TCV/AS/2

हिमाचल प्रदेश के अन्दर लगाने की बात इस बज़ट के माध्यम से की है। मैं एक खास निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें ज्वालामुखी को भी शामिल किया जाये। ज्वालामुखी बस स्टैंड से अर्जुननागा मन्दिर तक और अर्जुननागा से टेढ़ा मन्दिर तथा टेढ़ा मन्दिर से तारा देवी मन्दिर तक रज्जू मार्ग को बनाया जाये। इनको भी इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जाये। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले सालों में एक "शिक्षा हब्ब" बनाने का प्रयास किया है। सैंकड़ों स्कूल जो भारतीय जनता पार्टी के समय में बन्द कर दिए गये थे, जैसे यहां पर जिक्र किया गया और कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत से स्कूल खोल दिए। स्कूलों में ताले लगे हैं, मास्टर नहीं है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर स्कूलों की आवश्यकता थी जैसे मेरा चुनाव क्षेत्र ज्वालामुखी है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस चुनाव क्षेत्र में एक भी स्कूल खोला/अपग्रेड नहीं किया गया। मैं ये बात सदन में बोल रहा हूं कि एक भी स्कूल नहीं खोला गया और न ही खबली स्कूल अपग्रेड किया गया। जब कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री केवल सिंह पठानियां जी होते थे, खबली स्कूल उस समय खुला। धवाला,अध्वाणी,धाटी,गुमर स्कूल को अपग्रेड करने की बात की मगर उसकी जब नोटिफिकेशन की गई तो नोटिफिकेशन में कहा गया कि these school will be start functioning w.e.f. April, 2013.

श्री गर्ग जी द्वारा ---जारी

17/03/2016/1815/RG/AS/1

श्री संजय रतन----क्रमागत

जब आपको पता था कि चुनाव दिसम्बर, 2012 में हो रहे हैं, आपकी सरकार नहीं बनेगी, तो वर्ष 2013 में स्कूल कैसे चलेंगे? आपने लोगों का बेवकूफ बनाया, एक भी स्कूल नहीं। आपके तत्कालीन विधायक उस चुनाव क्षेत्र से जो थे। उन्होंने एक स्कूल भी अपग्रेड नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब सरकार बनाई और ज्वालामुखी की जनता ने मुझे चुनकर अपनी रहनुमाई करने के लिए इस विधान सभा में भेजा, मैंने 32 स्कूल एक साल में माननीय मुख्य मंत्री जी से अपग्रेड करवाए और उन सभी स्कूलों में आज बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हमारे चुनाव क्षेत्र में हर गांव में बच्चे अपने घर की रोटी खाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमने माननीय

मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया और चंगर क्षेत्र में खुंडियां में डिग्री कॉलेज खुलवाया और ज्वालामुखी के डिग्री कॉलेज का जिस कॉलेज के ऊपर 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की। जब उस कॉलेज के सरकारीकरण के लिए वहां के बच्चों ने आंदोलन किया, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं। आपके दो-दो मंत्री उस समय वहां मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन पर लाठियां बरसाई गईं। उस कॉलेज को टेक ओवर नहीं किया गया। लेकिन उस कॉलेज को भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने टेक ओवर करने की घोषणा की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं।
उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बिना किसी भेदभाव के, यह ज्वालामुखी क्षेत्र की बात नहीं है, मेरे बड़े भाई श्री रविन्द्र सिंह जी यहां बैठे हैं, भाई बिक्रम सिंह जी यहां बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, इनके चुनाव क्षेत्रों में भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के विकास किया है। मैं इसके लिए किसी भी मंच पर बहस करने के लिए तैयार हूं। देहरा के विकास में एक-एक ईंट के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का नाम लिखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ये मुझे एक भी योजना बताएं, किसी भी एक योजना का नाम लें जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय देहरा में शुरू किया गया हो। अगर केन्द्रीय विश्वविद्यालय आपने खोलना होता, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप देहरा के हितैषी होते, तो आप देहरा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कक्षाएं लगाते, शाहपुर में न लगाते। आपने कक्षाएं देहरा में नहीं लगाईं, आपने ज्वालामुखी में कक्षाएं नहीं लगाईं। जहां पर

17/03/2016/1815/RG/AS/2

सैंकड़ों सराय उपलब्ध थीं और रैंट फ्री अकोमोडेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले थे। लेकिन आपने वहां कक्षाएं नहीं लगाईं। आपने एक राजनीति की। श्रीमती सरवीन चौधरी जी शांता कुमार खेमे में थीं, उनको वहां से तोड़ने के लिए उनको ओबलाईज करने के लिए आपने जाकर शाहपुर में कक्षाएं लगाईं। तत्कालीन विधायक जो देहरा से मंत्री थे उनको नीचा दिखाने के लिए आपने देहरा में कक्षाएं नहीं लगाईं। आपने इस मामले में राजनीति की। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय आपकी राजनीति का शिकार है। हमारी राजनीति का शिकार नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि

इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे को बहुत जल्दी खत्म किया जाए। जहां भी आप विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, जिला कांगड़ा में बनाएं, लेकिन देहरा का हिस्सा देहरा को दे दिया जाए और देहरा में भी विश्वविद्यालय का कोई-न-कोई हिस्सा जरूर बनाया जाए। मैं इस पक्ष में हूं। मैंने उस समय भी जब मैं विधायक नहीं था, उस समय जब टीम विजिट करने आई थी तब भी कहा था और आज जब मैं विधायक हूं, तब भी खुले मन से कहता हूं और इस माननीय सदन में भी कहता हूं कि देहरा का हिस्सा देहरा को जरूर मिलना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि देहरा का हिस्सा देहरा में जरूर मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। हमने कोई कॉलेज बंद नहीं किया, बिक्रम सिंह जी को तो माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी होना चाहिए कि इनके क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो-दो कॉलेज दिए हैं। एक डाडासिब्बा में दिया और दूसरा रकड़ में दिया। तीसरा तो इनका अपना कोर्ट केस है अगर जीत जाएंगे, तो खुल जाएगा और हार जाएंगे, तो डी-नोटिफाई हो जाएगा।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 'मुख्य मंत्री कन्यादान योजना' में जो 25,000/-रुपये को बढ़ाकर 50,000/-रुपये किया और जो हमारी बहिनें नारी सदन में रहती हैं उनकी शादी पर मिलने वाला अनुदान 25,000/-रुपये से बढ़ाकर 51,000/-रुपये किया। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1820/MS/DC/1

श्री संजय रतन जारी-------

कि पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 80 साल से ऊपर की आयु वाले बुजुर्गों को बिना किसी इन्कम क्राइटेरिया के पैंशन को जारी किया और इस बार उसको बढ़ाकर 1200/-रुपये प्रतिमाह किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 80 साल की आयु सीमा रखी है, इसको कम करके 75 साल किया जाए ताकि हमारे जो बुजुर्ग लोग इस पैंशन से वंचित हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके

और समाज में वे अपना जीवन ठीक तरीके से निर्वाह कर सके। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 280/-रुपये से 350/-रुपये किया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले साल माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने केवल-मात्र शिक्षा विभाग में ही 11,000 के लगभग पद भरे हैं या प्रमोशन्ज की हैं। इस बार 13,000 फंक्शनल पोस्ट्स भरने की बात की है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी माननीय गोविन्द जी कह रहे थे कि यह बजट कर्मचारी विरोधी है। मेरा कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कर्मचारियों को इतना दिया है जितना शायद आपकी सरकार ने नहीं दिया है। अभी भी इस बजट में कर्मचारियों को छः प्रतिशत डी0ए0 दिया है और पांच प्रतिशत अंतरिम राहत आने वाले पे स्केल के लिए दी है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय रतनः सबसे बड़ी बात, जो अनुबंध कर्मचारी 31 मार्च को पांच साल की सेवा पूरी करने पर नियमित होते थे, अब उनको 30 सितम्बर को भी नियमित किया जाएगा। इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पार्ट टाइम वर्कर्ज को भी नियमित करने की बात की है। मैं इसमें भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूलों में जो पार्ट टाइम वर्कर लगते हैं, वे आठ साल की सेवा पूरी करने के बाद डेली वेजर बनते हैं। उनको नियमित करने का जो पीरियड आपने सात साल रखा है उसको कम करके जैसे अनुबंध कर्मचारियों का पांच साल पीरियड रखा है, वैसे ही किया जाए। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री

17/03/2016/1820/MS/DC/2

महोदय ने ये जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं ये बहुत ही काबिले-तारीफ हैं। जब से यह चर्चा शुरू हुई है तब से विपक्ष के माननीय सदस्य बजट पर कम बोल रहे थे और चेयरमैन्ज और वाइस चेयरमैन्ज पर ज्यादा बोल रहे थे। मुझे लगता है कि ये सारे-के-सारे चेयरमैन्ज और वाइस चेयरमैन्ज द्वारा प्रताड़ित किए हुए हैं। यह लोकतन्त्र है और लोकतन्त्र में जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार होगी, अगर उसके कार्यकर्त्ता चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? क्या अधिकारी बनेंगे या जज बनेंगे? मैं माननीय मुख्य मंत्री

महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी पोस्ट्स चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की खाली पड़ी हुई हैं वे सारी भर दी जाएं। क्या आपके समय में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं थे? यहां बिक्रम जी बैठे हैं ये फॉरेस्ट कारपोरेशन के चेयरमैन थे। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्त्ताओं की पार्टी है और यह अपने कार्यकर्त्ताओं को काम करने का मौका देती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पोस्ट्स चेयरमैन्ज और वाइस चेयरमैन्ज की खाली पड़ी हैं उनमें कार्यकर्त्ताओं को लगाया जाए और उनको काम करने का मौका दिया जाए।

उपाध्यक्षः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय रतनः उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे कृषि मंत्री जी कल भी और आज भी बोल रहे थे कि विधायक की सैलरी 1 लाख 20 हजार रुपये है। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में विधायक की सैलरी अभी तक 30 हजार रुपये है। अगर 1 लाख 20 हजार रुपये विधायकों की सैलरी हो जाएगी तो विधायक तो मालामाल हो जाएंगे।

मैं एक और बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। यहां पर कई विधायकों ने कहा कि हमारी सड़कों की डी0पी0आर्ज0 नहीं बन रही हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सड़कों की डी0पी0आर्ज0 भी बनी हैं और जो लिमिट 50 करोड़ रुपये की फिक्स हुई थी, हमने उसको भी क्रॉस कर लिया है। हमने प्राइवेट जमीनें दी हैं। हमने फॉरेस्ट क्लीयरैंस एक हैक्टेयर तक क्लीयर करवाई हैं। आप भी थोड़ी सी कोशिश करो और अपनी डी0पी0आर्ज0 बनाओ। प्राइवेट जमीनें दिलाओ और करवाओ।

17/03/2016/1820/MS/DC/3

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय रतनः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सीलिंग 60 करोड़ रुपये की है इसको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाए। जो विधायक काम करवाना चाहते हैं उनको मौका दिया जाए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

16.03.2016/1825/जेएस/डीसी/1

श्री संजय रतनः------**जारी**-------

जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कई चुनाव क्षेत्रों में 100-150 करोड़ रूपया नाबार्ड का लग गया और जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें 10 करोड़ रूपया भी नहीं लगा। उनको बराबर में लाने के लिए इसका लिमिट 100 करोड़ रूपए तक किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसमें लिखा है किः

विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए

संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप आगे बढ़ें। पूरा प्रदेश आपके साथ है। आपने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया है, उसमें आप आगे बढ़ें। पूरा प्रदेश आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी से आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। यह लाख कोशिश करें। मुद्दई लाख कोशिश करें, होगा वही जो मंज़ूरे खुदा होगा। इन्होंने पिछले तीन सालों से हर चीज से कोशिश कर ली। ये लोग कोमा में थे। ये कहते थे कि सरकार कोमा में थी । सरकार तो जागरुक है। सरकार जागरुक हो करके काम कर रही है। आप कोमा में थे इसीलिए मिशन रिपीट आपका मिशन डिफीट में कन्वर्ट हुआ और आप यहां से वहां बैठे। आप कोमा में थे, आप सत्ता के नशे में चूर थे। अगर आप सत्ता के नशे में चूर नहीं होते तो आज आप वहां न होते। हम जागरुक हैं और हमारे प्रदेश की सरकार जागरुक है। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पुरी उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बीड़ा हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का उठाया है उसमें वे कामयाब होंगे और सातवीं बार भी मुख्य मंत्री बनेंगे। इसी विधान सभा में हम यहीं बैठेंगे और आप वहीं बैठेंगे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का पुरज़ोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

16.03.2016/1825/जेएस/डीसी/2

उपाध्यक्षः श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 8 मार्च को जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें लगातार चार दिन से चर्चा हो रही है। उसमें भाग लेने के लिए मुझे आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने बड़े विस्तृत रूप से बताया है। उसके बाद जो अन्य हमारे वरिष्ठ सदस्य थे उन्होंने भी विस्तृत रूप से बताया है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी बजट की प्रशंसा में कसिदे पढ़े हैं। बजट में कुछ भी तारीफ़ करने लायक नहीं है। सभी वर्ग इससे निराश हुए हैं। केन्द्र सरकार से जो हमारा सेन्ट्रल टैक्सिज का शेयर था वह 32 से बढ़ा करके 42 परसेंट किया गया। इसके साथ-साथ जो हमारी सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्ज थी उसमें जो शेयर था 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार ने किया। उसके बावजूद भी बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है जिसके लिए इन्होंने इलैक्शन के दौरान बड़ा वायदा किया था अपने मेनिफैस्टो में कि उनको रोजगार भत्ता देंगे। वह भत्ता आज तक नहीं दिया और इस बजट के साथ यह चौथा बजट हो गया है। इससे सभी पढ़े-लिखे युवा को निराशा मिली है। इसके साथ-साथ जो रिर्सोस मोबिलाईजेशन के लिए है उसके लिए भी कुछ नहीं है। जैसे कि आप टूरिज्म को ले लीजिए। सड़कों की हालत खराब है इसलिए टूरिज्म में गिरावट आई है। इसके अलावा जो हमारे हाईडल प्रोजैक्ट्स हैं उनमें भी जिस ढंग से काम होना चाहिए था उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर है उसमें भी बड़ी चिन्ता का विषय है। एग्रीकल्चर के बारे में भी जो जी0डी0पी0 है उसको जो कंट्रिब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की वह 21 से रिड्यूस हो

करके 10 परसेंट रह गई है। इसका मतलब यह है कि जो इसके मेन कारण है एक तो जैसे कि आवारा पशुओं के बारे में बताया गया। हरेक सदस्य ने इसके बारे में बताया। दूसरा जो मेन कारण है जो हमारा हिमाचल प्रदेश का सी0सी0ए0 है, कल्चरल एवं कमांड एरिया है वह लगभग 5.83 लाख हेक्टेयर है।

16.03.2016/1825/जेएस/डीसी/3

उसमें से 30 परसेंट इरिगेशन आज तक हो रही है। सबसे ज्यादा पोटैंशियल है हमारा एग्रीकल्चर बढ़ाने का वह इरिगेशन से हो सकती है। इरिगेशन के लिए आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि एवं सिचाई योजना चलाई है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एक साल तक हमारे वहां की एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट उसकी डी0पी0आर0 नहीं बना सका। अब एक साल हमारा बर्बाद हो गया और चार साल के लिए जो प्रोपोज़ल बनाया जा रहा है उसमें आनन-फानन में उसकी डी0पी0आर0 भेजी जा रही है। जिला परिषद के बी0डी0सी0 को उसमें उतना पता नहीं होता है और जो विधायक होते हैं उनके पास मैक्सिमम समस्याएं आती हैं। विधायक से उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी सामने बैठे हैं मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जितने भी डिप्टी डायरैक्टर्ज हैं क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बना है वह डायरैक्ट कन्सलटैंट को डी0सी0 के माध्यम से भेज रहे हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

17.03.2016/1830/SS-AG/1

श्री के0एल0 ठाकुर क्रमागतः

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसमें दोबारा विधायकों की जो सिफारिश है उन्हें डालें क्योंकि उनको पता है कि कौन-सी स्कीम कैसे बननी है। अगले चार साल इरीगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह 2020 तक बनना है। इसके लिए विधायकों की जो सिफारिशें हैं उसको उसमें ज़रूर लें अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। As per guidelines, जो डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनना है उसमें कंसर्नड विधायक और एम0पी0 से कंसल्ट करना जरूरी है। उनकी कंसैट बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सभी डिप्टी डायरैक्टर्ज़ को दोबारा कहें कि अगर कोई विधायक उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कोई स्कीम देना चाहते हैं तो उसको ज़रूर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नई इरिगेशन के लिए डी0पी0आरज़0 नहीं बन पाईं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारा आई0पी0एच0 का वर्तमान सिस्टम है वह उसे नहीं बना पायेगा। क्योंकि कल ही आदरणीय इन्द्र सिंह जी का एक प्रश्न था, उसमें फिल्टर बैडस के बारे में पूछा था कि वाटर सप्लाई की कितनी स्कीमों के फिल्टर बैडस नहीं बने हैं और जो बने हुए हैं उनमें से कितने फंक्शनल नहीं हैं। जवाब दिया गया कि 600 नहीं बने हैं और 300 फंक्शनल नहीं हैं। मुझे यह रिप्लाई भी गलत लग रहा है। इस रिपोर्ट को दोबारा से फील्ड से लें। मेरे ख्याल में ऐसे केसिज़ ट्रिपल होंगे। सच बताने में गुरेज़ नहीं होना चाहिए। सच बताने में कोई बुराई नहीं है। एक बार उन सबका प्लान बना कर दोबारा से उन्हें बनाएं ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं वे न फैलें। अगर फिल्टर बैड ठीक नहीं होंगे तो बीमारियां फैलने का अंदेशा आगे भी बना रहेगा। अभी बहुत ज्यादा स्कीमों में पानी के इन्टेक्स भी प्रोटैक्टिड नहीं होंगे। मतलब यह कि उनकी डायरैक्ट एक्सैस पशुओं के लिए नहीं होगी। ऐसे इन्टेक्स भी बहुत होंगे। सैडीमैंटेशन टैंक्स ज्यादा नहीं बने होंगे। इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जगह-जगह पीलिया फैला हुआ है। इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आई0पी0एच0 के जो ऑफिसर्ज़ हैं, इंजीनियर्ज हैं, वे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ तो अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भागते हैं, सीवरेज़ के लिए भागते हैं तो दूसरी तरफ उनके पास फ्लड कंट्रोल भी है। फिर रूरल वाटर सप्लाई है। इरिगेशन है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने किसानों

को जस्टिस देना है तो किसानों के लिए इरीगेशन की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। तब किसानों को जस्टिस मिलेगा। ह्यूमन लाइफ के लिए पानी का पानी तभी होगा जब हम

17.03.2016/1830/SS-AG/2

वाटर सप्लाई पर ध्यान देंगे। अगर शहरों के साथ-साथ हमने रूरल एरिया को भी पानी देना है तो अर्बन वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड अलग बनाना पड़ेगा। रूरल वाटर सप्लाई अलग बनेगी और इरीगेशन अलग बनेगी। इसकी ट्राइफरकेशन करनी जरूरी है। तभी ये जितने अधिकारी/जीनियर हैं इसका सही से काम कर पायेंगे।

इसके अलावा हम फॉरैस्ट को लें। फॉरैस्ट का सरवाइवल रेट बहुत कम है। सबसे बड़ी सड़कों की बात है। पूरे प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। नालागढ़ कांस्टीचुऐंसी में और ज्यादा बुरा हाल है। हमारा एन0एच0-21 है, इसके बारे में मैंने बहुत बार विधान सभा में मुद्दा उठाया। विधान सभा के साथ-साथ लोगों में भी गया। इसके सैंटर गवर्नमैंट से लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे फंड ले आये हैं। लगभग एक साल हो गया है, न तो स्टेट गवर्नमैंट इसकी लैंड एक्विजिशन की पेमैंट कर पाई है और न ही कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी वर्क हो रहा है। जितना काम होता है वह साथ-साथ टूट जाता है। कंट्रैक्टर ने कोर्ट से स्टे ले ली है। गवर्नमैंट अभी अरली हीयरिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं दे पाई। इस प्रकार एन0एच-21 का हाल है। इसके अलावा दूसरी सड़कें जो लिंक रोडस हैं उनके भी हाल बहुत बुरे हैं। आज तक नालागढ़ कांस्टीचुऐंसी के लिए सी0आर0एफ0 में या इंटरस्टेट कनैक्टिविटी या वर्ल्ड बैंक फंडिंग से कोई भी सड़क नहीं बनी। तो मैं सरकार से रिक्वैस्ट करता हूं कि नाबार्ड के अलावा जो हमारी नौ सड़कें हैं इसको either inter-state connectivity या फिर वर्ल्ड बैंक फंडिंग का जो फेज-2 आना है उसमें रिक्मेंड करें। सड़कों का ब्योरा इस प्रकार है:-

1. Dherowal-Nalagarh-Ramshehar-Kunihar-Jubharhatti Road;
2. Soban Majra-Baruna-Bagheri-Khatiwala Road;
3. Ramshehar-Sunna-Doli-Nerli Road;
4. Panoh-Barian-Alyan-Danoghat Road;
5. Ambwala-Chanoberi-Vaid Ka Johad-Pehnood-Tambrodu Road;

6. C/o Bridge on Kundlu Khad between Village Kotla and Palahi;

7. C/o Link Road Ambwala-Retar-Rajwain-Jagli-Bara-Khuhi-Siras;

17.03.2016/1830/SS-AG/3

8. C/o Link Road for Bhini Johri-Pathled-Papler; and

9. Construction of Link Road Gujjarhatti-Purla-Kantrooghat.

Contd by KS in Hindi . . .

17.03.2016/1835/केएस/एजी/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी----

ये 9 सड़कें है जिनकी कॉस्ट लगभग 75 करोड़ रु0 के आसपास होगी। या तो इसको इंटरस्टेट कनैक्टिविटी मिले या फिर वर्ल्ड बैंक से फंड मिले।

इरिगेशन के बारे में कहना चाहूंगा कि हमने एक डी0पी0आर0 फल्ड कंट्रोल की बनाई है, विधायक प्राथमिकता में तीन साल पहले डाली थी1 Channelization of all rivers in Nalagarh Valley including construction of small dams wherever feasible. तीन साल हो गए अभी तक उसकी स्टडी नहीं हो पाई। यह हमने स्वां की तर्ज पर बनानी है और इसके लिए समस्या यही है कि स्टाफ की कमी है । ट्राईफरकेशन की बात है और मैं समझता हूं कि इसमें समय लगेगा क्योंकि फाईनैंशियल इम्पलीकेशन्ज़ हैं परन्तु फिर भी आपको इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम सभी किसानों के साथ और लोगों के साथ न्याय कर सके।

उद्योग मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बी.बी.एन. के लिए हमने कई बार इनसे आग्रह किया है । इसमें लगभग 60 या 65 प्रतिशत एरिया नालागढ़ चुनाव क्षेत्र का है और 35 से 40 प्रतिशत दून चुनाव क्षेत्र का है। तो आज तक जो फंडिंग हुई है, वह उल्टा है। मैंने बार-बार सिफारिश की है परन्तु कुछ नहीं होता । इसके लिए तीन साल से बहुत कम फंडिंग हुई है

तो मेरा आग्रह है कि इसमें फंडिंग पंचायतों की संख्या और पॉपुलेशन के आधार पर की जाए। सुबह ही दभोटा इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात हुई है उसके लिए भी जहां तक हमारी जरूरत होगी हम काम करेंगें और जमीन देने की कोशिश करेंगें परन्तु मुख्य डियूटी राज्य सरकार की होती है क्योंकि सरकार फैडरल सिस्टम है और हम सीधे सैंटर गवर्नमैंट के पास नहीं जा सकते। तो राज्य सरकार के माध्यम से ही जा सकते हैं अगर इसके लिए लैंड चाहिए तो इसमें इनिशिएटिव आपने लेना, हमने सिर्फ आपको असिस्ट करना है। हमारे उद्योगों में वर्कर्ज़ की लगभग हर जगह ही समस्या है, नालागढ़ में भी समस्या है।

17.03.2016/1835/केएस/एजी/2

मुझे नहीं लगता कि 70 प्रतिशत हिमाचली किसी भी जगह होंगें। बाहर के वर्कर्ज़ हैं और इसके लिए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से चाहूंगा, ये तो वहीं से गुजरते हैं, कभी चैक करें । इसके अलावा उद्योगों में जो दूसरे काम होते हैं, वह भी बाहर के लोगों को ही दिए जाते हैं। तो जो बेरोज़गार हिमाचली युवक हैं, उनको वहां पर नौकरियां भी मिले तथा साथ ही जॉब वर्क में इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए।

बिजली विभाग के बारे में मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नालागढ़ में पिछले एक साल से फ्रीक्वैंट पावर कट लग रहे हैं। वहां पर सिस्टम ऑगमैंट करना पड़ेगा। तो कृपया इसका पता कराइए ताकि लोगों को फ्रीक्वेंट पावर कट्स से छुटकारा मिल सके।

शिक्षा के बारे में सभी वक्ताओं ने बताया और शिक्षा का स्टेट में वैसे ही बुरा हाल है। नालागढ़ में तो उससे भी बुरा हाल है क्योंकि नए स्कूल खुले हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी से यही आग्रह है कि जो स्कूल खोले हैं, उनमें स्टाफ लगाए वरना शिक्षा की क्वालिटी ज्यादा स्कूल खोलने से इम्प्रूव नहीं होगी बल्कि और भी डाऊन हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन में एक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे स्कूल में प्ले ग्राऊंड हो और दूसरी सुविधाएं हो, क्वालिफाईड स्टाफ हो और जो भर्तियां हैं वह

एस.एम.सी. की बजाय सर्विस सलैक्शन बोर्ड से हों। मैं मानता हूं कि एस.एम.सी. में जो भर्तियां हो वह एमरजैंसी केसिज में हो But it should not be in routine. हो क्या रहा है कि जो सर्विस सलैक्शन बोर्ड से भर्तियां है वह 10 परसेंट भी नहीं हो रही है और मेजर भर्तियां बैकडोर एंट्री से हो रही है तो इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आंगनबाड़ी वर्कज़ के बारे में कहना चाहूंगा उनका भी ऑनरेरियम बढ़ना चाहिए क्योंकि 3 हजार 35 सौ रुपये बहुत ही कम है। इसी तरह से गौशाला के लिए जो गौ-सम्बर्द्धन बोर्ड बनाया है यह वैल्कम स्टैप है, बहुत अच्छी बात है

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2016/1840/av/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर क्रमागत

परंतु जो 10 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है यह बहुत कम अमाउंट है। इसको थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि 10 करोड़ रुपये से तो कुछ नहीं हो पायेगा।

जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है। वहां बद्दी में माननीय कलराज मिश्र, लघु उद्योग मंत्री जी आए थे और हमारे मंत्री जी भी साथ थे। वहां पर जो डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत से टैक्नोलोजी सैंटर बनना है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। पहले यह छोटा सा टूल रूम था और 20-25 करोड़ रुपये का बनना था। मगर अब यह टैक्नोलोजी सैंटर के रूप में डेढ़ सौ करोड़ रुपये से बनना है तथा इसके लिए सारी फंडिंग सैंटर गवर्नमैंट करेंगी। इस चीज से पता चलता है कि केंद्र सरकार का हमारे प्रदेश के प्रति कितना पॉजिटिव ऐटिट्यूड है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए एक साल के लिए 10 नेशनल हाई-वे स्वीकृत हुए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र दो पार्ट्स में है उसमें एक पहाड़ी एरिया है तथा दूसरा प्लेन एरिया है। प्लेन

एरिया में तो हमारे सिंचाई का साधन ट्यूब वैल हैं मगर पहाड़ी एरिया में हम चाहते हैं कि वहां पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाकर इरिगेशन करें। वैसे भी रामबुशहर के पहाड़ी एरिया में लोग ऑफ सीजन सब्जियां काफी उगाते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि वहां के लिए सरकार स्टेट सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर में वैजिटेबल प्रोसैसिंग प्लांट लगाये तो अच्छा रहेगा। उससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। नालागढ़ में डिसपर्स ट्राइब की पोपुलेशन लगभग 12000 हैं। इनके लिए जो बजट होता है, वह बढ़ना चाहिए। इस बारे में मैंने पिछले साल भी कहा था। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए गृह निर्माण की जो राशि बढ़ाई गई है यह अच्छी बात है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो 75 हजार रुपये की राशि रखी गई है यह बहुत कम है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसको 75 हजार रुपये की बजाय एक लाख रुपये कर दिया जाए। 75000 रुपये में जो घर बनता है मुझे

17.3.2016/1840/av/2

लगता है कि वह रहने लायक नहीं होगा। इसमें राशि बढ़ाई जाए चाहे गृह निर्माण का नम्बर कम हो। आज की डेट में वैसे एक लाख रुपये भी कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जो सड़कों की एनुअल रिपेयर करते हैं तो उसमें 20 एम0एम0 प्रीमिक्स डालते हैं और मुझे लगता है कि यह सबकी प्रोब्लम है। यह 20 एम0एम0 जल्दी टूट जाती है इसलिए इसको 32 या 40 एम0एम0 किया जाए। इससे सड़कों की लाइफ बढ़ेगी और लोगों में जो गलत मैसेज जाता है वह भी नहीं होगा। सरकार ने स्टूडैंट को हायर स्टडी के लिए जो 10 लाख रुपये का 4 प्रतिशत की दर से लोन देने का निर्णय लिया है यह भी अच्छी बात है। इससे हमारे हायर स्टडी करने वाले बच्चों को फायदा होगा। यहां पर पक्ष की तरफ से बार-बार ब्लैक मनी की बात होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ने यह कहा हो कि आपकी जेब में 15-15 लाख रुपये आ जायेंगे। वह 15 लाख रुपये विकास के लिए आने थे। उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है और वह पैसा जब भी आयेगा यहां विकास के लिए आयेगा। उसके बारे में आप लोग न तो कोई उम्मीद रखो और न ही प्रदेश की जनता को गुमराह करो।

उपाध्यक्ष जी, मैं यहां पर अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

समाप्त

17.3.2016/1840/av/3

श्री बलदेव सिंह तोमर : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 मार्च, 2016 को जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यहां बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए, वैसे तो उसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है। उससे पूरे प्रदेश ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी,

टीसीद्वारा जारी

17.03.2016/1845/TCV/AS/1
श्री बलदेव सिंह तोमर ---- जारी

लेकिन बजट में न किसान/बागवान/मजदूर के लिए और न कर्मचारियों के लिए इस बज़ट में कुछ भी नहीं था। सबसे गरीब वर्ग मजदूर होता है लेकिन उसकी दिहाड़ी मात्र 20 रूपये बढ़ाई गई। आजकल दिहाड़ी में अगर आप अपने घर में कोई काम करवाएंगे तो 300 और 400 रूपये से कम कोई मजदूर नहीं मिलेगा। फिर 200 रूपये दिहाड़ी में मजदूर कहां से मिलेगा? यहां पर माननीय विधायक के0एल0 ठाकुर जी जैसा कह रहे थे कि हमारे साथी बैंकों में 15 लाख रूपये आने की बात कही, जब 3 साल पहले विधान सभा के चुनाव इस प्रदेश में हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा प्रचार पूरे प्रदेश में किया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और बेरोजगार नौजवानों ने भी बैंकों में खाते खोले थे कि सरकार बनते ही हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन वे ठग्गे रह गये और कोई भी पैसा सरकार के द्वारा बेरोजगारों को नहीं दिया जा रहा है,केवल मात्र उनको गुमराह किया जा रहा है। दूसरा, बेरोजगारों के लिए जो प्राईवेट इंडस्ट्रीज हैं, माननीय इंडस्ट्री मिनिस्ट्र यहां पर बैठें हैं, 70 परसेंट बेरोजगारों को इंडस्ट्रीज में रोजगार देने की बात की जाती है लेकिन क्या कभी विभाग ने जाकर देखा है? क्योंकि मेरे जिला में भी पांवटा साहिब और काला अंब इंडस्ट्रियल एरिया हैं लेकिन वहां पर हमारे जिले के जो बेरोजगार है जब वे उन फैक्टरियों में काम करने के लिए जाते हैं तो उनको मात्र ठेकेदार के माध्यम से काम पर

लगाया जाता है। इस तरह से कई-कई सालों तक उनका शोषण किया जाता है और उसके बाद भी उनको फैक्टरी में रेगुलर नहीं किया जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है और मैं माननीय मंत्री जी को निमंत्रण देता हूं कि आप हमारे जिला में आईए और हमारे जिले की हालत देखिए, क्योंकि उस जिला में इंडस्ट्री है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में चुने के पत्थर का बहुत बड़ा कारोबार है लेकिन आज 3 साल से वह कारोबार कहां पहुंच गया है? वहां पर सैंकड़ो ट्रक खड़े हैं और जो उसमें ड्राईवर/कंडैक्टर है, उनको परिवार पालना मुश्किल हो गया है क्योंकि सरकार ने माईनें बन्द की हुई है। मैंने यहां पर एक प्रश्न लगाया था, प्रश्न संख्याः 2714 उसमें कहा गया कि जिला सिरमौर के अन्दर 6 चुना पत्थर की खानें चल रही है। इनमें 4 खानों के पास

17.03.2016/1845/TCV/AS/2

पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है और मैं उनसे जानना भी चाहता हूं कि हमारे जिला में जितनी माईनें हैं सभी लोगों ने यहां पर ई0आई0ए0 के लिए आपके विभाग में अप्लाई किया हुआ है तो ये मात्र 2 माईनें क्यों चल रही है? क्योंकि ये देहरादून के लोगों की माईनें हैं। जो हमारे 27 लोग हैं उनको अभी तक परमिशन नहीं मिल रही है जिसके कारण हमारे जिले में अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन के कारण जब से विधान सभा सत्र चल रहा है, उससे पहले मैं बोलता रहा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई,लेकिन जैसे ही सत्र चला पुलिस भी हरकत में आई और माईनिंग विभाग भी हरकत में आया। मेरे पास समाचार पत्रो से कुछ कटिंगन्ज है, डी0एस0पी0 सहित पुलिस को ट्रक से कुचने का प्रयास, पुलिस अधिकारियों पर किया पत्थराव अंधेरे का फायदा उठाकर भागा चाल,अवैध खन्न पर कस्सा शिकंजा,ट्रक और 6 ट्रैक्टरों के चालान,अवैध खन्न वालों से वसूला 10 लाख 56 हजार रूपये, सिरमौर में अवैध खन्न के 24 मामले पकड़े, खन्न विभाग ने की कार्रवाई 24 हजार रूपये जुर्माना वसूल, मिन्स-सैंज खड्ड में अवैध खन्न।

श्री गर्ग जी द्वारा ---जारी

17/03/2016/1850/RG/DC/1

श्री बलदेव सिंह तोमर----क्रमागत

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अवैध खनन के लिए जिनको पकड़ना चाहिए उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग वहां काम करने वाले हैं उनको परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों एक क्रशर के ऊपर 60-70 पुलिस वाले गए और सुबह 6.00 बजे वहां छापा मारा गया। जबकि उसके सारे कागज़ात देखे गए, तो सभी कागज़ात सही पाए गए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा था और आश्वासन भी चाहता हूं कि आप जल्दी-से-जल्दी जिला सिरमौर का दौरा करिए और मेरे विधान सभा क्षेत्र का दौरा करिए। वहां की परिस्थिति देखिए। आपने सुबह यहां एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमने जिला सिरमौर के लिए कुछ खानों को ऑऊटसोसिाग पर लीज पर देने का कार्यक्रम बनाया है और यहां प्रस्ताव पास हुआ है। ऐसी कोई योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो चूना पत्थर की खानें हैं वह खाली रेत, बजरी के लिए आपने प्रावधान किया है। चूना-पत्थर की जो हमारी खानें हैं उनके लिए भी वह प्रावधान किया जाए ताकि वे भी लीज पर दी जाएं जिससे वहां अवैध खनन न हो और लोगों को उसमें रोजगार भी मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी यहां से चले गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उनसे संबंधित था। मैंने यहां एक प्रश्न संख्या 1256 लगाया था जिसके द्वारा मैंने पूछा था शिलाई विधान सभा क्षेत्र में कितने अस्पताल, कितने सी.एच.सी., कितनी पी.एच.सी. और कितने स्वास्थ्य उप-केन्द्र हैं? जवाब में कहा गया कि एक सी.एच.सी. है जिसमें 40 पद स्वीकृत हैं और मात्र 23 पद भरे हुए हैं, डॉक्टर्ज मात्र दो हैं, 300 की वहां ओ.पी.डी. है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक अस्पताल ऐसा है जहां पर कि लोग आकर अपना इलाज कराते हैं, लेकिन वहां दो डॉक्टर है, उसमें से भी एक डॉक्टर छुट्टी पर जाता है और एक ही वहां रहता है। आखिर वह एक डॉक्टर क्या करेगा? 8 पी.एच.सीज़ हैं। एक भी डॉक्टर उनमें नहीं हैं। आठों-की-आठ पी.एच.सीज़ बंद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब डॉक्टर्ज नहीं हैं, तो पी.एच.सी. खोलने की क्या आवश्यकता है? लगातार संस्थान खोलने की क्या आवश्यकता है? 26 स्वास्थ्य उप-केन्द्र हैं और 10 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों में एक में भी कोई कर्मचारी नहीं है। ऐसी परिस्थति हमारे विधान सभा क्षेत्र की है। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कोई भी निजी

17/03/2016/1850/RG/DC/2

अस्पताल नहीं है। शहरों में यदि डॉक्टर नहीं होता है, तो निजी अस्पताल होते हैं और लोग अपना इलाज वहां करा लेते हैं। लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है। मेरा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। अगर दो महीने के अंदर-अंदर वहां डॉक्टर्ज नहीं आए, तो मुझे कोई-न-कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए माननीय मंत्री जी जिम्मेवार होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं शिक्षा के बारे में बात करूं, तो यहां कहा गया कि बहुत सारे संस्थान खोले गए। अच्छी बात है कि संस्थान खोले गए, लेकिन उनमें स्टाफ का भी प्रावधान करना चाहिए। इस प्रदेश में किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। भाई संजय जी यहां कह रहे थे कि समग्र विकास इस प्रदेश में हो रहा है और कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मेरे पास ये कुछ कागज़ हैं। 5-12-2014 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पार्ट टाईम वाटर कैरियर की यहां पोस्टिंग की थी। उन्होंने ऑर्डर दिए थे, अप्रूवल ऑर्डर थे जो यहां से गए। ऑर्डर को लेकर उप निदेशक ने आगे ऑर्डर किए, लेकिन जो उस स्कूल के मुख्य अध्यापक हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल, पोका, वहां उसको नियुक्ति नहीं दी जाती है। लगातार एक महीने हमने प्रयास किया, लेकिन वह नियुक्ति नहीं मिली। क्योंकि उनके ऊपर दबाव था। उसके बाद ये कोर्ट में जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी 5-12-2014 को ये आदेश दिए हैं कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। उप निदेशक, नाहन ने मुख्य अध्यापक को ऑर्डर किए कि आप इनके पूरे कागज़ लेकर इनको ज्वाइनिंग दो, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे से पहले ये ऑर्डर हुए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। ये ऑर्डर 5-12-2014 के हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऑर्डर किए हैं उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस प्रदेश में भेदभाव किया जा रहा है?

एम.एस. द्वारा जारी

17/03/2016/1855/MS/DC/1

श्री बलदेव सिंह तोमर जारी-------

दूसरा हमारे स्कूलों में स्टाफ नहीं है। स्कूलों में एस0एम0सी0 की भर्तियां हो रही हैं और उन एस0एम0सी0 की भर्तियों में धांधलियां हो रही हैं। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी सदन में बैठे नहीं हैं। उनके पास राजस्व विभाग भी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव से पहले SDM कार्यालय खोला गया। स्वास्थ्य मंत्री जी आ गए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपसे संबंधित बहुत सारे विषय हैं। आपने वर्ष 2014 में मेरे वहां SDM कार्यालय खोला, हमने सरकार का बहुत धन्यवाद किया लेकिन दो साल हो गए हैं, SDM शिलाई में मात्र छः महीने ही बैठा। क्या पूरे प्रदेश में SDM की कमी पड़ गई है या वहां जान-बूझकर SDM नहीं भेजा जा रहा है? उपाध्यक्ष जी, शिलाई तहसील के अंदर जो तहसीलदार है, शायद यह पूरे प्रदेश में पहला ही मामला होगा, वह उसी विधान सभा क्षेत्र से संबंध रखता है। शिलाई विधान सभा क्षेत्र में उसका घर है। उसके पास SDM का चार्ज पिछले डेढ़ साल से है। मात्र छः महीने वे वहां पर रहे और अब वे एस0एम0सी0 की भर्तियां कर रहे हैं। शिलाई और रौनहाट में नायब तहसीलदार नहीं है। उन दोनों का जार्च भी उनके पास ही है। उस विधान सभा क्षेत्र में वे भेदभाव से कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि आप उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई करेंगे? उस विधान सभा क्षेत्र का ही तहसीलदार SDM का कार्यभार भी देख रहा है और एस0एम0सी0 की सारी भर्तियां भी कर रहा है। वह जिसको चाहता है, उसको लगा देता है। हमारे फोन तक नहीं सुने जाते हैं और हम किसी भी कार्य के लिए वहां जाते हैं तो हमें बात तक नहीं करने दी जाती है। क्या ऐसे इस प्रदेश को आप चलाना चाहते हैं? दूसरे, माननीय सदस्य संजय रतन जी ने बात कही कि समग्र विकास पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज ही इस विधान सभा के अंदर मेरा एक अतारंकित प्रश्न संख्याः 1272 लगा था जिसके द्वारा जिला सिरमौर के अंदर पैसों का प्रत्येक विधान सभावाइज क्या-क्या आबंटन हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि

17/03/2016/1855/MS/DC/2

हमारे जिले में किस तरह से आबंटन हुआ है। शिलाई विधान सभा क्षेत्र में लगभग 2.00 लाख रुपये, पौंटा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1.15 लाख रुपये, पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में

लगभग 2.70 लाख रुपये, नाहन विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1.41 लाख रुपये और रेणुकाजी विधान सभा क्षेत्र जहां से हमारे सी0पी0एस0 साहब है वहां के लिए 8.30 लाख रुपये है। यानी चारों विधान सभा क्षेत्र का जो पैसा है उससे भी ज्यादा पैसा रेणुकाजी में खर्च हुआ है। आखिर किस प्रकार का ये समग्र विकास इस प्रदेश में कर रहे हैं?
परिवहन मंत्री जी सदन में नहीं है। परसों मेरा एक प्रश्न संख्याः 1238 लगा था जिसमें पूछा गया था कि प्रदेश में ऐसी कितनी सड़कें हैं जो पास हो चुकी हैं लेकिन उनमें बसें नहीं चल रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र दो बसें परिवहन निगम की जाती हैं और पूरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर कोई भी रात्रि ठहराव परिवहन निगम की बस का नहीं है। वे बसें भी मात्र उधर से गुजरती हैं। जब मैं उस जवाब को पढ़ रहा था तो उसमें सर्कलवाइज जानकारी थी कि कहां कितनी सड़कें रह गई। कुल मिलाकर 186 सड़कें ऐसी हैं जोकि पास हुई हैं लेकिन वहां बसें नहीं चल रही है। परन्तु नाहन सर्कल की एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जोकि पास हुई है और उसमें बस न चल रही हो। जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सड़कें ऐसी हैं जो हमारी सरकार के समय महेन्द्र सिंह जी ने पास की थी लेकिन उनमें बसें नहीं चल रही हैं। जिनमें लिंक रोड बेला,

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट के लिए बैठिए। अभी दो माननीय सदस्य और चर्चा में भाग लेने हेतु शेष हैं। क्या वे आज ही बोलना चाहेंगे या कल बोलेंगे?

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष जी, कल तो मुख्य मंत्री जी सिर्फ चर्चा का जवाब देंगे।

उपाध्यक्षः ठीक है। फिर पांच मिनट अभी बलदेव तोमर जी बोलेंगे और आधा घण्टा दो माननीय सदस्य बोल लेंगे।

अब इस मान्य सदन की बैठक सांय 7.30 बजे तक बढ़ाई जाती है।

17/03/2016/1855/MS/DC/3

श्री बलदेव तोमरः धन्यवाद। जिनमें लिंक रोड बेला, लिंक रोड कूंठ और लिंक रोड बड़वास है। परन्तु जो विधान सभा के अंदर जवाब दिए जा रहे हैं उन जवाबों में भी सूचना

सही नहीं आ रही है। आखिर यह सरकार क्या बताना चाहती है और क्या छिपाना चाहती है? मैं यह भी जानना चाहता हूं। दूसरा सड़कों की डी0पी0आर्ज0 की बात है। मुझे विधायक बने हुए तीन साल हो गए हैं लेकिन आज तक एक भी डी0पी0आर0 मेरे विधान सभा क्षेत्र की,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1900/जेएस/एजी/1

श्री बलदेव सिंह तोमरः .....जारी---------

आज तक एक भी डी0पी0आर0 मेरे विधान सभा क्षेत्र की एम0एल0ए0 प्रायोरिटी की एक भी नहीं बनी है। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? जानबूझ कर एम0एल0ए0 प्रायोरिटी की डी0पी0आर0 नहीं बनाई जा रही है क्योंकि हमसे भेदभाव किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे इस मामले में संरक्षण चाहते हैं कि आप भी यह मामला देखें। जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है जिला सिरमौर के अन्दर कानून-व्यवस्था भी कोई अच्छी नहीं है। परसों ही लगभग 4.00 बजे पांवटा साहिब में एक शिक्षिका थी। उसको प्राईवेट स्कूल से छुट्टी होती है । लगभग 3.30 बजे शाम को वह अपने घर के पास गाड़ी से सड़क पर उतरती है और उसके बाद 5.00 बजे उसका शव झाड़ियों में मिलता है। ऐसी घटनाएं रोज़ सुनने को जिला सिरमौर के अन्दर मिली है और यहां पर इसका ज़वाब भी आया था, उसमें सभी घटनाएं थी। आखिरकार हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था को हम किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। वह भी एक चिन्ता का विषय है। यह ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के अन्दर एम0एल0ए0 को जो फंड है उसको बढ़ाया है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। मैंने आपको बताया कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। हम लोगों के पास केवल एम0एल0ए0 फंड है, बाकि तो आपके देख लिया है कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए उसको कम से कम डेढ़ से दो करोड़ रूपए तक किया जाए। जो हमारी

ऐच्छिक निधि है जो कि 4 लाख से 5 लाख की गई है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन वह भी कम है। उसको भी कम से कम 6 लाख तक किया जाए। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि यहां पर मैंने बात रखी और बजट के अन्दर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसके समर्थन में कुछ कहूं, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.03.2016/1900/जेएस/एजी/2

उपाध्यक्षः श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमारः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट 8 मार्च को प्रस्तुत किया मैं भी उसमें बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने लगभग साढ़े तीन घंटे बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण यहां पर दिया। पिछले तीन वर्षों में उन्होंने इस प्रकार से बताने का प्रयास किया कि उन्होंने अथाह विकास किया है। किस प्रकार से आने वाले वर्षों में कहां इस प्रदेश को लेकर जाएंगे, इस ओर उन्होंने यहां पर अपना बजट प्रस्तुत किया। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इन तीन वर्षों के दौरान मेरा मानना है कि किसी भी तरह का विकास हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। जहां तक तो विकास की बात है, हां मैं मानता हूं कि विकास उन लोगों का हुआ जैसे कि भाई संजय रतन जी यहां पर कह रहे थे। जो अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की लम्बी-चौड़ी फौज़ इस प्रदेश में खड़ी की गई है। करोड़ों रूपया उनके वेतन व भत्तों पर लुटाया जा रहा है और उनके पास मात्र एक ही काम है केवल उदघाटान और शिलान्यास करना। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। पिछले तीन वर्षों में अनेक ऐसे उद्घाटन हुए जिनके काम भी पूरे नहीं हुए । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा मैंने अभी इस सत्र में ही एक प्रश्न अपने विधान सभा क्षेत्र का लगाया था और मैंने पूछा था कि गत् तीन वर्षों में पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में कितने उद्घाटन हुए? जिसमें मुझे ज़वाब मिला कि 21 योजनाओं के उद्घाटन किए गए, जिसमें 18 योजनाएं कम्पलीट हो गई थी और 3 योजनाओं का कार्य पूरा नहीं हुआ था।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

17.03.2016/1905/SS-AG/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागतः

जब किसी योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसका उद्घाटन करने का क्या औचित्य है? दूसरा, एक पीने के पानी की लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम थी, जिसकी टैस्टिंग भी नहीं हुई, उसके बावजूद उसका उद्घाटन कर दिया गया। इस प्रकार के उद्घाटन और शिलान्यास पिछले तीन वर्षों में हुए हैं। ईवन जिनको मैंने अपनी विधायक प्राथमिकता में डाला ऐसी स्कीमों के भी शिलान्यास किये जा रहे हैं। जबकि जिनको वहां का वाइस-चैयरमैन बनाया, उन्होंने अपने समय में इन स्कीमों को विधायक प्राथमिकता में नहीं डाला। जब मैंने विधायक प्राथमिकता में डाला, उसकी डी0पी0आर0 बनवाई तो उसके बाद उसका पैसा स्वीकृत हुआ। लेकिन विडम्बना यह है कि जब शिलान्यास की बारी आई, इंवीटेशन तो दूर इंटीमेशन भी विधायक को नहीं दिया गया। इस प्रकार से एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। मैं एक सड़क की बात करना चाहूंगा, जिसको मैंने विधायक बनते ही एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डाला। मैटलिंग टारिंग ऑफ लिंक रोड डिंगर-किन्नर-बघानघाट। उसके लिए 3 करोड़ 82 लाख स्वीकृत हुआ। लेकिन जब शिलान्यास की बारी आई तो वहां का जिन्हें वाइस-चेयरमैन बनाया है वे उसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे। शिलान्यास भी नहीं एक नयी टर्म शुरू की - "भूमि पूजन"। जब मैंने पता किया कि क्या है? 3 दिसम्बर, 2015 को उसका भूमि पूजन किया गया। इंओगरेशन नहीं बल्कि भूमि पूजन किया गया। जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि यह तो केवल भूमि पूजन हुआ है।

इसी प्रकार से एक पीने की पानी की लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम, दाड़ोदेवरिया है। उसको भी मैंने एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डाला। उसके लिए भी साढ़े 42 लाख रुपया स्वीकृत हुआ। जब शिलान्यास की बारी आई तो उसमें भी वैसे ही किया गया। समय एक बजे रखा गया लेकिन उसका 10 बजे ही शिलान्यास कर दिया गया। जो वाइस-चेयरमैन साहब थे वे वहां से रवाना हो गये। उनको खतरा था कि कहीं विधायक वहां न पहुंच जाएं। ऐसे अनेकों काम पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए और जो यह लम्बी चौड़ी फौज जिला सिरमौर में है पांच अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वे करोड़ों रुपये की घोषणाएं प्रतिदिन करते हैं।

लेकिन अगर आप सिरमौर की हालत देखें तो बहुत ही बदतर है। हां, एक जगह का विकास हुआ जैसे विनय जी कह रहे थे कि सारी मशीनरी, सारा बजट चाहे

17.03.2016/1905/SS-AG/2

एस0डी0पी0 का है या चाहे दूसरे फंडस हैं, सारा जिला सिरमौर का बजट एक ही विधान सभा क्षेत्र में खर्च हो रहा है। बाकी जो दूसरे विधान सभा क्षेत्र हैं उनमें नाममात्र का पैसा मिल रहा है। जो नाममात्र का पैसा मिल रहा है उसमें भी जो वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके कहने से नहीं बल्कि जो हारे हुए व्यक्ति हैं उनके कहने पर यह पैसा दिया जा रहा है। इस प्रकार से यह सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया। उसमें उन्होंने दूसरे ही पैरे में स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कहा। मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विकास किया है। लगभग एक हजार स्कूल खोले। मैं मानता हूं कि स्कूल खुले। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अनेक स्कूल खुले। कई स्कूलों का दर्ज़ा बढ़ाया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अच्छी बात है। स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल भी खुलने चाहिएं लेकिन स्थिति यह है कि स्कूल तो खुल गये, दर्ज़े भी बढ़ गये लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है। मिडल स्कूलों में भी एक बच्चा है और एक बच्चे के लिए कभी एक स्कूल से डैपुटेशन किया जाता है तो कभी दूसरे स्कूल से किया जाता है। ऐसी स्थिति है। जो बात रोहित जी एस0एम0सी0 की कर रहे हैं उसकी भर्ती में भी भाई-भतीजावाद हो रहा है। पहली बात यह है कि जो इंटरव्यू होते हैं उसमें भाई-भतीजावाद हो रहा है। दूसरा, इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए भी जहां नेता जी कहेंगे केवल वहीं पर इंटरव्यू कॉल किये जायेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1910/केएस/एएस/1

श्री सुरेश कुमार जारी----

जो पंचायतें, जो स्कूल, जिनमें की भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जिन क्षेत्रों में हैं उन स्कूलों में एस.एम.सी. के इंटरव्यू भी नहीं करवाए जाते। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेकों ऐसे स्कूल है, मैंने इस बारे में इस बार विधान सभा में एक प्रश्न भी लगाया था, प्रश्न संख्या 2658, मैंने पूछा था कि कितने स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है तो 22 ऐसे

मिडिल स्कूल हैं, 11 प्राईमरी स्कूल है और अध्यापकों की स्थिति तो आज पूरे प्रदेश में बहुत ही बद्तर है। अनेकों ऐसे स्कूल हैं, अभी महेश्वर सिंह जी ने इस बारे में इसी सत्र में प्रश्न लगाया था प्रश्न संख्या- 1184, जिसमें पूछा गया था कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहां सिंगल टीचर हैं तो इसके जवाब में कहा गया था कि प्रदेश में 982 सिंगल टीचर स्कूल हैं और 16 स्कूल ऐसे हैं जहां पर डैपुटेशन पर टीचर जाता है। जहां तक बच्चों की संख्या की बात है, 15 ऐसे स्कूल थे जिसमें एक अध्यापक, एक बच्चा है और एक स्कूल तो ऐसा था जिसमें अध्यापक है लेकिन बच्चा ही नहीं है । भाई जगजीवन पाल जी कह रहे थे कि हम पी.ई.टी. और डी.पी.ई. भर्ती कर रहे हैं तो जिन स्कूलों में एक टीचर और एक बच्चा होगा तो क्या बच्चे और टीचर आपस में कबड्डी खेलेंगे? आज पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। यहां पर कॉलेजों की बात की गई है कि प्रदेश में 28 कॉलेज खोले गए। मेरे चुनाव क्षेत्र में पहले आदरणीय धूमल जी ने वर्ष 2012 में सराहां में कॉलेज खोला था इस सरकार ने आते ही बन्द कर दिया। उस कॉलेज के लिए भूमि का प्रबन्ध भी कर दिया गया था, बजट का भी प्रबन्ध किया था लेकिन उसके बावजूद सरकार ने आते ही उसको बन्द कर दिया। उसके बाद 29 सितम्बर, 2013 को दोबारा से मुख्य मंत्री जी वहां पर सरांह में मेले के समापन पर गए थे, वामन द्वादशी मेले में वहां उन्होंने इस कॉलेज को दोबारा खोलने की घोषणा की। साथ ही मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि मैं इसके लिए 4 करोड़ रुपया स्वीकृत करता हूं। मैं थोक का व्यापारी हूं और छोटी-मोटी घोषणाएं नहीं करता। चार करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत करने की बात की। उसके लिए दोबारा भूमि का चयन हुआ क्योंकि पहले धूमल जी ने शिलान्यास किया था, उसके बाद 22 सितम्बर, 2015 को उसका दोबारा शिलान्यास किया गया। दोबारा मुख्य

17.03.2016/1910/केएस/एएस/12

मंत्री जी गए थे और इन्होंने दूसरी बार फिर थोक के व्यापारी ने 13 करोड़ की घोषणा वहां पर की । मैं इस सदन में बताना चाहूंगा कि मैंने इस विधान सभा में प्रश्न लगाया था प्रश्न संख्या-2918, जिसमें मैंने पूछा था कि सरांहा कॉलेज के लिए क्योंकि केन्द्र सरकार ने इसको मॉडल कॉलेज करने की घोषणा की थी और इसके लिए 12 करोड़ रु0 स्वीकृत भी किए थे, मैंने पिछले सत्र में इसके बारे में प्रश्न लगाया था और सरकार ने बताया था कि 12

करोड़ रु0 केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं । इस बार जब मैंने पूछा कि क्या सरांहा में मॉडल कॉलेज बनाने के लिए केन्द्र की ओर से कोई बजट स्वीकृत किया गया तो मुझे उत्तर मिला कि शून्य। मैंने पूछा कि इस कॉलेज के भवन का निर्माण कब तक किया जाएगा तो जवाब मिला कि उक्त महाविद्यालय के भवन का निर्माण केन्द्र सरकार से धनराशि उपलब्ध होने के उपरांत ही किया जाएगा। तो जब मुख्य मंत्री जी ने पहले चार करोड़ रु0 की घोषणा की, उसके बार 13 करोड़ रु0 की घोषणा की और जो थोक की घोषणाएं हुई थी, वह पैसा कहां चला गया? इस प्रकार से इस सदन में बड़ी संवेदनहीनता से उत्तर दिए जाते हैं और बड़े अचरच की बात है कि एक बार मुख्य मंत्री जी ने एक बार चार करोड़ रु0 की घोषणा की और दूसरी बार 13 करोड़ की की फिर वह बजट कहां चला गया? इस प्रकार से तीन वर्ष के विकास के बारे में जो यहां पर बात की गई , राजगढ़ कॉलेज की बात करना चाहूंगा । वर्ष 2005 में उसका कार्य शुरू हुआ था और आज 2016 है एक दशक से ज्यादा का समय हो गया , आज तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2016/1915/av/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागत

आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब वर्ष 2012 में माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने उसका शिलान्यास तब किया था। उस समय भवन निर्माण की कॉस्ट कितनी थी और वर्ष 2016 में 11 वर्षों के बाद वह कॉस्ट कहां पहुंच गई। इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद उसका काम आज भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे अनेक संस्थान हैं जैसे आई0टी0आई0 राजगढ़ और आई0टी0आई0 सराहं हैं जो कि प्राइवेट भवनों में चल रही हैं। इस प्रकार से एक साइड बात होती है कि इन तीन वर्षों के दौरान अथाह विकास हो गया। आप अगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जाएं तो आपको वहां पर विकास नाम की कोई चीज नजर नहीं आयेगी। अगर पीने के पानी की बात करें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी अनेकों ऐसी

स्कीमें हैं जिनमें कि वॉटर फिल्टर बैड नहीं हैं। यहां पर पीलिया की बात हुई जो कि यहां पूरे प्रदेश में फैला है। यहां पर पहले शिमला फिर सोलन और उसके बाद सिरमौर में पीलिया का प्रकोप हुआ। पीलिया से ग्रस्त अनेकों लोगों को अपना इलाज आई0जी0एम0सी0, सोलन होस्पिटल और पी0जी0आई0 में करवाना पड़ रहा है। मैं अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। वहां की एक महिला की मौत आई0जी0एम0सी0 में पीलिया की वजह से हुई है। आज भी पीलिया से ग्रस्त लोग पी0जी0आई0 और आई0जी0एम0सी0 में हैं। मैं कल ही अपने विधान सभा क्षेत्र में गया था, वहां लोगों ने बताया कि ओछघाट में कोई व्यक्ति झाड़-फूंक का काम करता है। उसके पास पीलिया वालों की इतनी लम्बी-लम्बी लाइन है कि तीन-तीन घंटे तक वहां पर नम्बर नहीं आता। अभी भी लोग पीलिया से इस प्रकार पीड़ित है जबकि यहां पर सरकार आंकड़े पेश कर रही है कि अब यह खत्म हो गया है। शिमला शहर जिसको हमारी सरकार के समय में बैस्ट हिल स्टेशन का अवार्ड मिला था अब वह शिमला बैस्ट पीलिया स्टेशन बन गया है। इन तीन वर्षों में ऐसा विकास मिला। मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकतर स्कीमें तो ग्रेविटी वॉटर सप्लाई की हैं। कुछ लिफ्ट वॉटर सप्लाई स्कीमें हैं। उनमें पानी को फिल्टर करने की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी को सीधा खड्ड से उठाकर लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों की हालत तो और भी खराब है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी अनेकों सड़कें हैं जिनकी हालत अति दयनीय है। अगर आप

17.3.2016/1915/av/2

लोक निर्माण विभाग का कारनामा देखेंगे तो हैरान रह जायेंगे। वहां पर सड़कों में पड़े गड्ढों में जे0सी0बी0 के साथ मिट्टी बिछाई है। पहले लोक निर्माण विभाग सड़कों में पड़े गड्ढों को भरकर उसका काम ढंग से करवाता था। मगर इस बार उनमें जे0सी0बी0 से मिट्टी बिछाई गई। जब वर्षा हुई तो वह सड़कें कीचड़ में तबदील हो गई और आज वे सड़कें पानी के तालाब बन गये हैं। अनकों सड़कें चाहे सराहां-चंडीगढ़ की बात करे, सोलन मिन्स की बात करें, ओछघाट-नेरीपुल सड़क की बात करें। बागथन-राजगढ़ रोड की बात करें; वहां सभी सड़कों की हालत एक जैसी है। लिंक रोड की तो और भी बुरी हालत है। इसी तरह से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में बिजली की बात करना चाहता हूं। मैंने अभी प्रश्न लगाया था कि

कितने ऐसे गांव हैं जहां पर लो वोल्टेज की समस्या है। उसके जवाब में बताया गया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 34 गांव हैं। मैंने पूछा था कि क्या इस बारे में सर्वे करवाया गया है तो बताया गया कि सर्वे के उपरांत वहां पर 34 ऐसे गांव हैं। मैंने इस विषय पर विभाग से बार-बार बात की और हर बार एक ही जवाब मिला कि ट्रांसफॉर्मर लगना है और उसका ऐस्टिमेट भेजा है।

टीसी द्वारा जारी

17.03.2016/1920/TCV/AS/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागत

लेकिन 3 साल बीत गये उस ट्रांस्फार्मर के एस्टीमेट ही अभी तक अप्रूव होकर नहीं पहुंचे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर चाहे किसी भी विभाग की बात है, लोक निर्माण,विद्युत,आई0पी0एच0 विभाग इनमें अनेकों पद खाली पड़े हैं। राजगढ़ सब-डिविजन में आई0पी0एच0 में जे0ई0 के 4 पद खाली है। वहां पर एक एस.डी.ओ. है जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और कहा कि मोबाईल घर पर रह गया था। उनकी पत्नी ने जब मेरा फोन पीक किया तो कहा कि उन्हें डा0 ने फोन न सुनने की सलाह दी है। वहां पर एक ही एस.डी.ओ. है और वह पूरे सब डिविजन का कार्य देख रहा है। स्वास्थ्य विभाग में अनेक ऐसी पी.एच.सीज है जहां डा0 नहीं है। जिला सिरमौर को 16 एम.बी.बी.एस. डाक्टर मिले यह खबर मैंने अखबार में पढ़ी। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन वह डाक्टर जिला सिरमौर में नहीं पहुंचे, पता नहीं कहां चले गए। आज अनेकों पी.एच.सीज हैं, चाहे पी.एच.सीज चलोग, बागथन,नारंग,धामला, डिम्बर, कोटी पधोग है और सी0एच0सी0 सराहां में भी डाक्टरों की कमी है। यह स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र की है। शायद इस तरफ के विधायकों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के साथ जो भेदभाव हो रहा है वहां डाक्टर नहीं है, टीचरों की कमी है, सड़कों की हालत खराब है उस ओर सरकार ध्यान दें। इस बजट में मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती कि जिसका मैं समर्थन करूं। उपाध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

17.03.2016/1920/TCV/AS/2

उपाध्यक्षः श्री विजय अग्निहोत्री

श्री विजय अग्निहोत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे अब यह वक्त सुनने का नहीं, सहन करने का है। बजट अनुमान और जो बज़ट पुस्तिका हमें दी गई इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। इन आंकड़ो को पढ़कर बहुत से प्रश्न पैदा हुए और उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह कि हमने पिछली बार जो बुक पढ़ी थी और जिस पर चर्चा की थी, उसके बारे में हम कहां तक पहुंचे यह बात देखने वाली बात है।

श्री गर्ग जी द्वारा----जारी

17/03/2016/1925/RG/DC/1

श्री विजय अग्निहोत्री----क्रमागत

और ऐसा कई वर्षों से चलता आ रहा होगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारी स्थिति वह हो गई है कि 'चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास।' सोचते हम कुछ और हैं, होता कुछ और है और वह नहीं हो रहा है जो हम करना चाहते हैं। हम result oriented कोई चीज शुरु नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कहां जाना चाह रहे हैं और हम कहां पहुंचे हैं? यह बजट सत्र, इसमें पूरे साल का लेखा-जोखा होता है, हम पिछले साल कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं, कहां पहुंचना चाहते थे और आगे आने वाले दिनों में हम कहां पहुंचेंगे? इन सारे विषयों के बारे में चर्चा हो और हम जहां तक पहुंच गए, उस बारे में वास्तविकता हमारे सामने आए। हमने बजट के अनुमान रख दिए सड़कों के लिए इतना, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य के लिए इतना, हैण्ड पम्प्ज के लिए इतना, कृषि के लिए इतना, युवा खेल के लिए इतना, बाकी अन्य चीजों के लिए इतना, लेकिन हम कहां गए? हम पहुंचे कहां हैं, हमने प्राप्त क्या किया? सड़कों के बारे में सोचें, तो सड़कों की हालत कैसी है, माननीय मुख्य मंत्री जी को स्वयं बोलना पड़ा कि मैं डिमोट कर दूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ ही श्री इन्द्रदत्त लखनपाल जी का चुनाव क्षेत्र भी लगता है, मैं कई बार वहां जाता हूं और सोचता हूं कि शायद इनकी हालत अच्छी होगी? लेकिन वहां भी वही हाल है। जो पैसा हम इस बुक में आबंटित करते हैं और बजट पास करते हैं, तो वह जाता कहां है?

इस विषय के ऊपर सोचने की आवश्यकता है। जब कोई बजट बुक या कोई भी बुक बनाता है, लिखता है, तो वह अपनी कोशिश करता है कि मैं अच्छी-से-अच्छी चीज इसमें रखूं। जब गीता बनी, गीता का उपदेश हुआ, तो भी सारा ठीक था, किसी ने कोई कटाक्ष आज तक नहीं किया, कुरान का और बायबल का भी यही हाल है। असल में जो फर्क पड़ता है वह इससे पड़ता है कि उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उसके अनुयायी क्या कर रहे हैं, वे उसको कैसे इलोबोरेट कर रहे हैं, उसको कैसे मैनीपुलेट कर रहे हैं, यह उनके ऊपर है। वही बात इसमें भी है। मैंने जब कृषि के बारे में आदरणीय कृषि मंत्री जी से सुना, इसमें पढ़ा कि कृषि को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए बहुत चिन्ता हुई। इस सदन में जब मैं पहली बार आया था और मैंने पहली बार बोला था, तो मैंने कहा था कि यह जो आवारा पशु हैं इनसे बचने के लिए खेतों में बाड़ लगाई जाए। क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में एक पंचायत कुलूर है जिसमें वहां लोगों ने मिलकर बाड़ लगाई थी, तो उसको रोका गया था। उसकी वजह से चिंता हुई, उसके लिए बजट दिया। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जैसे पहले होता

17/03/2016/1925/RG/DC/2

रहा, वैसे ही होता रहेगा क्या? उस बाड़ में जब हम कहीं जाएंगे, बंदर या आवारा पशु आएंगे, तो बजट बुक ही दिखानी पड़ेगी कि भाई हमने तो लगा दिया है, बजट पास कर दिया है और वे अनपढ़ हैं पढ़ते नहीं हैं, पता नहीं क्या होगा? हम जो भी योजना बनाए, उसका पूरी तरीके से क्रियान्वयन कैसे हो और उसका परिणाम कैसे सामने आए, उस विषय में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। हम बाड़ लगाने के लिए 25 करोड़ रुपये रख देंगे, हम कहेंगे कि चुनाव क्षेत्रवार बांट दो, तो 25-25 या 30-30 लाख रुपये आ जाएगा। उसमें हमने 60:40 की रेशो रखी है कि पब्लिक पर्टिसिपेशन उसमें होगा। जहां नहीं होगा, वहां नहीं लगेगी। जहां हम बजट आबंटित कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए क्या होगा, तो वह ऐसे थोड़ा-थोड़ा बंदर के प्रसाद की तरह बांट देंगे। उससे यह होने वाला नहीं है। इसके लिए प्रमाणित योजना बनाने की आवश्यकता है कि हम इस साल में इतने गांवों को, इतनी भूमि को सींचित करेंगे और बाकी चीजें टच नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे बांटने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हम इसका परिणाम सामने लाकर रखेंगे। चाहे हम कम-से-कम करें, लेकिन उसका परिणाम हमारे सामने हो, उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सबकी चिंता है। आपकी भी चिंता है, हमारी भी चिंता है, बाहर जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, सबकी चिंता है और चिंता यही है कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं? हमारे बच्चों को खेत और खेल के बारे में चिंता ही नहीं है। छोटे से बच्चे के पास चले जाओ, मैंने एक बच्चे से पूछा कि क्या खेलते हो? उसने कहा कि मैं कार रेसिंग करता हूं, मैंने कहा कि इतने छोटे से हो ओर कार रेसिंग करते हो, तो उसने कहा कि नहीं मैं कम्प्युटर पर करता हूं। वैसे ही गेमें चली हैं। आज पसीना बहाने के लिए या जिसमें परिश्रम करना पड़े या उसको कोई जील पैदा हो, उस चीज की कमी हो गई है। हर जगह कमी हुई है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट आप बैठिए। अब माननीय सदन का समय 15 मिनट के लिए 7.45 बजे अपराह्न तक बढ़ाया जाता है।

एम.एस. द्वारा जारी..

17/03/2016/1930/MS/DC/1

श्री विजय अग्निहोत्री : उनको खेत में कैसे पहुंचाया जाए या खेल के मैदान में कैसे पहुंचाया जाए, इन दो चीजों के बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए केवल बजट की जरूरत नहीं है, बजट उसमें एक माध्यम है। उसके लिए कैसे हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको वहां जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और क्या-क्या इन्सेंटिव्ज दे सकते हैं, यह सोचने की जरूरत है। कृषि विभाग के बारे आदरणीय वीरेन्द्र कंवर जी ने विस्तृत कह दिया है। हमारे कृषि विभाग में एग्रीकल्चर एक्सटैंशन ऑफिसर्ज हैं, एग्रीकल्चर इन्सपैक्टर्ज हैं, एस0एम0एस0 हैं या ऊपर तक के जितने भी लोग हैं, वे यहां से बीज भेजते हैं और बीज वहां सैक्शन ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां से जिसकी सरकार होती है उसके चार कार्यकर्त्ता आते हैं और उनको क्विंटलों के हिसाब से बीज दे दिया जाता है। कई तो अदरक को धो-धोकर उसको चाय में भी पीते हैं। जो हम बीज दे रहे हैं उस बीज से क्या आ रहा है, क्या यह जानने के लिए कृषि विभाग के लोग कभी वहां गए? क्या उन्होंने लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित किया या पूछा कि उनको किस चीज की जरूरत है? कृषि मंत्री महोदय, आज इस बात की जरूरत है कि हम उस विभाग के लोगों को उस पर्टिकुलर सैक्शन के अंदर यदि 20 गांव हैं तो 10 गांव की

जिम्मेदारी दें कि इस साल इन 10 गावों में ये खेती होनी चाहिए। आपको ये बीज और खाद दी जा रही है और इसमें ये-ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहते हैं उनको रहने दो। इस तरह आप उनसे आउटपुट लो। विभाग लोगों को बताए कि ये-ये चीजें पैदा हो सकती हैं और इससे आपको रोजगार मिल सकता है। इससे उस नौजवान की एक पहचान बनेगी और इससे उसका सोशल स्टेट्स बनेगा। तब वह नौजवान खेतों में जाएगा, नहीं तो वह नहीं जाएगा। क्योंकि जो नौजवान खेत की तरफ जाएगा, उसके मैट्रिमोनियल प्रौस्पैक्ट्स नहीं रहते हैं। उसका समाज में आदर नहीं होता है। आज इन सारी चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसके पीछे एक और बात भी है। जैसे अब हमारे परिवार छोटे हो गए हैं। अब मां-बाप के एक बच्चा होता है और हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तुझे कमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरे लायक हमने कमा दिया है। फिर बच्चा नहीं कमाता है।

उससे भी आगे, जो यहां नशे की बात चली, उसके लिए बजट में कोई ऑथेंटिक प्रावधान नहीं है और बजट में उसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके लिए सरकार की विल पावर और जिल चाहिए कि हम इसको दूर करना चाहते हैं। आज नशे का जो अवैध व्यापार चल रहा है और नशे के जो सौदागर वहां बैठे हुए हैं उन

17/03/2016/1930/MS/DC/2

लोगों के ऊपर लगाम कसने की जरूरत है। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा में भी कहा था कि मेरे गांव के तीन लोगों को पिछले दो सालों में नशा निवारण केन्द्र में भेजना पड़ा। उनमें से दो तो लगभग ठीक हैं लेकिन एक की हालत खराब है और एक लड़के की ज्यादा डोज की वजह से मृत्यु हो गई है। ऐसा सभी जगह है। हम चाहे फिर एस0पी0 के पास जाएं या एस0एच0ओ0 के पास जाएं। हम नाम लेकर उनको बताते हैं कि फलां दुकानदार ऐसा काम कर रहा है। हमने उनको सिर के ऊपर शराब की पेटियां ढोते हुए देखा लेकिन पुलिस वालों ने आज तक कुछ नहीं किया। वह इच्छा-शक्ति कहां से आएगी? आज आवश्यकता यह है कि इस बजट को इम्प्लीमैंट करने के लिए हमारी जो मशीनरी है और उसके पीछे जो अधिकारी/ कर्मचारी लगने वाले हैं उनकी जिल क्या है, वे उनको करना चाहते हैं या नहीं, यह बात मायने रखती है।

यहां अवैध खनन और अवैज्ञानिक तरीके से खनन की बात बहुत दिनों से चल रही है और कई बार यहां चर्चा भी हुई है। हमारे आसपास दो खड्डे हैं और दोनों खड्डों पर क्रशर लगे हैं। वे क्रशर रिवर बैड पर लगे हैं और कई बार इस बारे में शिकायतें भी हुईं और लोग कोर्ट तक गए लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। मैं पिछले साल की एक बात ध्यान में लाना चाहती हूं। मेरी पंचायत के बेहा गांव के कुछ 15-20 महिला और पुरुष डी0सी0 साहब से मिलने गए। कांगू में रेवेन्यु ऑफिसर्ज की मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि यहां पर जे0सी0बी0 से अवैध खनन हो रहा है। मैं भी वहां गया था। अखबार में खबर और फोटो दोनों छपी कि ऐसे-ऐसे लोग खनन और शराब माफिया के विरोध में डी0सी0 से मिलने गए और डी0सी0 ने आश्वासन दिया कि मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। मजे की बात यह है कि उस दिन रेवेन्यु ऑफिसर्ज की जो मीटिंग वहां कांगू में थी, उसके बारे में हमें शाम को पता चला कि जिस ठेकेदार के विरोध में हमने मेमोरेंडम दिया, उसी व्यक्ति ने उस मीटिंग का लंच होस्ट किया।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1935/जेएस/एजी/1

श्री विजय अग्निहोत्रीः------**जारी**-----

ऐसी जब बातें होंगी, ऐसी जब काम होंगे तब कैसे इन चीजों को रोका जा सकेगा? कैसे आप किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं कि आप नशा न करो जब आपको ड्रग घर में मिल रही है। आपको 5 रूपये की शराब गांवों में मिलती है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे वहां तो उसको शराब ही नहीं बोलते है। वह नाम से लेकर फलां जल, नीलम जल कोई किरण जल। अगर इन चीजों से आप युवाओं को नहीं बचाएंगे तो आप जितना मर्ज़ी बजट देते रहो लेकिन बजट से बातें बनने वाली नहीं है। उसके पीछे इम्प्लिमेंटेशन, उसके पीछे ज़ील, उसके पीछे विल पॉवर और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसे ही खेलों के बारे में और इस बार के बजट में प्रोत्साहन राशि बढ़ाई, ईनाम राशि बढ़ाई और बाकी चीजें बढ़ा दी, लेकिन बजट कम कर दिया। चलो जो आपके पास बजट होगा उसके हिसाब से किया होगा। क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि जो-जो हमने उपक्रम चला रखे हैं,

जो स्पोर्टस होस्टल हमने चला रखे हैं, उन होस्टल्ज की क्या हालत है? वहां बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं? मेरे चुनाव क्षेत्र नादौन में स्पोर्टस होस्टल हॉकी का है। नादौन में हॉकी का ग्राऊंड नहीं है। जिस होस्टल में वे बच्चे रहते हैं और उनसे मैं भी एक दिन मिलने गया वहां पर 10 मिनट भी कोई आदमी खड़ा नहीं रह सकता है। वहां पर सफोकेशन और अंधेरे कमरें हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब बच्चा आप स्पोर्टस होस्टल में भेजेंगे तो वहां पर रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, वहां पर लाईट ठीक नहीं है और वहां पर सफोकेशन है। ऊना के बारे में सुबह वीरेन्द्र कंवर जी ने कहा। पपरोला का जो बास्किट बॉल का होस्टल है उसमें बास्किट बॉल का कोच नहीं है। सुन्दरनगर में जो ब्वायज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो स्पोर्टस होस्टल है उनके पास ग्राऊंड नहीं है। जो वहां पर कॉलेज एम0एल0एस0एम0 है वे उसके ग्राऊंड का प्रयोग करते हैं। इस तरह की सुविधाएं देनी की आवश्यकताएं हैं। उन खिलाड़ियों के पीछे जान लगाने की आवश्यकता है। उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है। उनको ग्राऊंड तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जब आपने वहां पर हॉकी का कोच रखा है तो वे क्या करेंगे? वे जाते हैं और खेल कर आ जाते हैं अगर कोई भर्ती हो गया तो

16.03.2016/1935/जेएस/एजी/2

ठीक है और नहीं तो फिर बेचारा वहीं पर धक्के खा रहा है। हम जो कर रहे हैं और जो हमारे पास है कम से कम उसको तो ठीक कर लें। जहां तक बजट को बढ़ाने की बात है वहां पर साथ-साथ इसकी पुरी मॉनिटरिंग और इम्प्लिमैंट किया जाए। कोच कहां चाहिए और कहां नहीं चाहिए, यह भी तय होना चाहिए। जरूरत ऊना में और कोच शिमला में। अगर कोई भी सरकार युवाओं को ये दो चीजें खेत और खेल का मैदान इस तक पहुंचा देगी तो वह आने वाली पीढ़ियों पर बड़ा एहसान करेगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत है। उसमें वोट पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की जरूरत है। वोट पॉलिटिक्स के कारण से शिक्षा के विषय में बहुत चर्चा हुई, बहुत स्कूल अपग्रेड हुए, बहुत स्कूल नए खुले और बहुत से कॉलेजिज़ आपने शुरू किए। यह बहुत अच्छी बात है, करने

चाहिए। लेकिन क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं वोट पॉलिटिक्स करके बोलता हूं, क्योंकि हम राजनीतिक लोग है हमारे पास कोई आएगा और कहेगा कि हमें स्कूल चाहिए और हम दे देंगे। लेकिन उसकी क्या फीजिबिलिटी है, उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है ऐसी चीजों के बारे में सोचना भी हम लोगों का काम है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पिछली सरकार के समय में एक बात शुरू हुई कि जिन स्कूलों में बच्चे कम है वे स्कूल बन्द हो जाएंगे। मेरे वहां पर पड़ौस में भी एक स्कूल बन्द हो गया। उस गांव के जी0पी0एस0 मगरा उसके सारे के सारे 15-20 लोग मेरे घर पहुंच गए कि आप धूमल जी से बात करो कि हमारा स्कूल बन्द करो। हम ऐसे ही बैठे थे और चाय पीते-पीते मैंने उनसे पूछा कि आपके घर से प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और आपके कितने पढ़ते है और उस स्कूल में कितने पढ़ते हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

17.03.2016/1940/SS-AS/1

श्री विजय अग्निहोत्री क्रमागतः

तो 15 लोगों में से 12 लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। सिर्फ दो या तीन लोगों के बच्चे गवर्नमैंट स्कूल में पढ़ते थे। अब वे स्कूल की पुनः मांग रहे हैं। वे क्यों मांग रहे हैं कि पड़ोसियों के बच्चे वहां पढ़ें और मेरे तो अकैडमी में ही पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा कि आप बच्चों की संख्या 15 कर देंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। उन्होंने एफिडेविट दिये। बाद में स्कूल शुरू हुआ और अब वह चल रहा है। परन्तु उसमें बच्चों की संख्या 15 या 18 ही है। लेकिन इन सब विषयों के बारे में सोचने का काम यहां बैठे हुए लोगों का है। स्कूलों को क्लब करो। अब मैं हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। प्राईमरी एजुकेशन को बचा लो। प्राईमरी स्कूल बंद हो जायेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। जी0पी0एस0 अमरोह मेरी कांस्टीचुऐंसी में तीन साल से बंद है। उसमें किसी बच्चे की एडमिशन नहीं हुई। स्टाफ को शिफ्ट कर दिया।

बिल्डिंग खड़ी है और विभाग के पास इतना समय नहीं है कि उसका कोई ऑल्टरनेट यूज़ कर लिया जाए। उसमें गाय और जानवर रहते हैं। उसका कोई वैकल्पिक यूज़ नहीं है। कोई सामुदायिक केन्द्र बना दो, गांव वालों को ही दे दो, कोई भी अन्य यूज़ कर लो लेकिन उसका अभी तक कोई प्रयोग नहीं हो पा रहा है।

उच्चतर शिक्षा में रूसा के बारे में कई बार बोल चुका हूं। अब कितनी बार बोलना? इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर उसकी इम्प्लीमैंटेशन ठीक नहीं है और उसमें चेंज करने की आवश्यकता है तो अवश्य करना चाहिए क्योंकि हमने बिना तैयारी के ही उसको शुरू किया है। आज बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रही है। मैं परसों एच0पी0 यूनिवर्सिटी में गया था, वह भी पुराने मानकों के हिसाब से रूसा से आये हुए व्यक्तियों को एडमिशन नहीं दे सकती। जब हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रही है तो बाहर कैसे मिलेगी? इसलिए इस विषय के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षा क्वालिटेटिवली कैसे इम्प्रूव हो उसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा कि जहां बड़ा इंटीरियर क्षेत्र है उसमें आपको एक बोर्डिंग स्कूल खोलना चाहिए। उसमें पूरा स्टाफ, आया, अटैंडेंट सारी चीज़ें दो। वहां पर बच्चों को पढ़ाओ। कम्पीटिशन स्पिरिट तब होगी जब वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। एक बच्चा न कबड्डी खेल सकता है। न बॉलीबॉल खेल सकता है। न बैडमिटन खेल सकता है। यहां तक गोलियां भी नहीं खेल सकता, जिसको

17.03.2016/1940/SS-AS/2

हम कंचे कहते हैं। एक सिंगल बच्चा खेलेगा तो वह कम्प्यूटर पर ही खेलेगा और कम्प्यूटर पर खेल कर आपके बच्चे में रजिस्टैंट पैदा नहीं होगी। इस करके युवा, खेत, खेल तथा शिक्षा के बारे में मास्टर प्लान बनाकर उसे क्रियान्वित करने की ज़रूरत है। कोई भी जो हार्ड स्टैप लेगा, वोट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखो तो लोग आपको रिकोग्नाईज़ करेंगे। आपको लोग दिल से दुआएं देंगे कि आपने इसमें कोई चेंज लाई, नहीं तो जैसे चले हैं वैसे चलने दो। अगर प्रवासी मजदूर न हों तो आज की डेट में सारे प्राईमरी स्कूल्ज़ फेल हैं। इस करके इस विषय में बहुत गहन चिन्तन करने की आवश्यकता है। उसके लिए कोई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। ऐसा मैं शिक्षा के विषय में बोलना चाहता हूं। शिक्षा के विषय में बहुत से लोगों का मानदेय बढ़ाया है। लेकिन अगर मिड डे मील वर्कर्ज़ को भी थोड़ा-सा इंसैटिव मिल जाता तो अच्छा रहता। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनका

इंसैटिव भी बढ़ाया जाए। कम्प्यूटर टीचर के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। उसके बारे में भी चिन्ता करने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ उद्योग भी इस प्रदेश में कम हो रहे हैं। जैसे पीछे चर्चा में आया कि 67 उद्योग परवाणू में और कितने ही अन्य जगह जिन्होंने बिजली के कनैक्शन्ज़ कटवा दिये हैं वे उद्योग बंद पड़े हैं। --(व्यवधान)-- मेरे टाइम में भी बंद हुए होंगे तो भी कोई चक्कर नहीं, वह तो हमारी और आपकी कॉलैटिव रिस्पोंसिबिलिटी है। मेरा बोलना का मतलब यह है कि इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। सोचने की आवश्यकता इस करके है क्योंकि जब तक हम इन उद्योगों को सबसिडी दे रहे हैं,

जारी श्रीमती के0एस0

17.03.2016/1945/केएस/एएस/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी---

उनको टैक्स में एग्ज़म्पशन दे रहे हैं तब तक तो वे टिक रहे हैं लेकिन जब हम नहीं दे रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही हाल हो गया है। चाहे आपका कौशल विकास भत्ता है, चाहे बेरोज़गारी भत्ता है चाहे आप लोगों को और इन्सैंटिव्ज़ देने की बात कर रहे हैं। कौशल विकास भत्ता जो आप दे रहे हैं यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, ऐसा नहीं है कि आप उस फंड की मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? हम किसको दे रहे हैं ? हमारे पास जो क्वालिफाईड और स्किल्ड लोग हैं आई.टी.आई. है, बी.टैक है, हम उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नए लोगों को स्किल डवैल्प करके क्या दे रहे हैं? हम उनको भत्ता दे कर सिर्फ सरकारी पैसा खाने की आदत डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम बेरोज़गारी भत्ते की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो रोज़गार की मांग कर रहे हैं। आप इम्प्लॉयमैंट जैनरेट करो चाहे प्राईवेट सैक्टर में हो, एग्रिकल्चर सैक्टर में हो चाहे गवर्नमैंट सैक्टर में हो, आप यूथ को काम में लगाओ। हम नहीं चाहते कि आप उनको मुफ्त में खाना सिखाओ। लेकिन उसके लिए आपने कमिटमैंट की थी कि हम

आपको बेरोज़गारी भत्ता देंगें, वह आपने गलत किया था उसके लिए आप क्षमा मांगों, आप बोलो कि हमने भावना में बहकर वोट के लालच में आकर यह कर दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहता। अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में एक-दो बातें करना चाहूंगा। व्यवस्था सुधारने की बात है। यहां पर संजय रतन जी बोल रहे थे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करना चाहिए यह अच्छी बात है लेकिन उसको कमज़ोर करने की बात नहीं करनी चाहिए। यहां पर कहा गया कि हमारे यहां चेयरमैन ने, वाईस चेयरमैन ने उद्घाटन कर दिया, मेरे यहां तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने ही कर दिया। पिछले कल उप तहसील कांगू का उद्घाटन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने कर दिया। लडशाई के डिपो का उद्घाटन कर दिया और यह किस क्षमता में कर रहे हैं, उस बारे में सरकार को सोचने की जरूरत है। अगर ऐसे ही

17.03.2016/1945/केएस/एएस/2

परम्पराएं चली तो यह लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन वे किस क्षमता में कर रहे हैं? अब तो वह हालत हो गई है कि

कैसे-कैसे मंजर सामने आने लगे हैं कि गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं,

अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारों, इसमें तो कमल भी मुरझाने लगे हैं।

इन चीजों को आप बदलो। मैंने इस बार के बजट में कहा है कि विधायक प्राथमिकता में हैंड पम्प लग सकते हैं। मैंने पिछले साल एक प्रश्न किया था कि नदौन चुनाव क्षेत्र में जो हैंडपम्प लगे, उसमें किन जन-प्रतिनिधियों की रीकमैंडेशन थी? तो उस समय 80 प्रतिशत प्रदेशाध्यक्ष की थी। अगर उन्हीं से चलाना है तो क्यों लोकतंत्र की बातें करते है? आपने अगर सुधार ही करवाना है तो उनको चेयरमैन बना दो, करवा दो। उनको

कंस्टिच्यूशनल पोस्ट दे दो, करवा दो लेकिन आप एक पार्टी के किसी पदाधिकारी को ऑथोराईज़ कर रहे हैं या वह मनमानी कर रहा है, सरकार चुप बैठी है?

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिए।

श्री विजय अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, बस समाप्त ही कर रहा हूं। हमारी विधायक प्राथमिकता की मीटिंग होती है । उसमें रोड्ज़, आई.पी.एच. की स्कीमें आती है। कुछ हमारे से बिल्डिंग्ज़ के बारे में भी हमारे से मांगा जाता है कि स्कूलों की, स्वास्थ्य संस्थानों की बिल्डिंगे बना दी जाए। बजट बुक में वे आती ही नहीं है, उसके बारे में भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वह भी उस बुक में छपें और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.3.2016/1950/av/1

श्री विजय अग्निहोत्री क्रमागत

आज तक क्यों नहीं छपी, इसमें जिसकी गलती है उनकी भी ऐक्सप्लेनेशन हो। जैसे पूरे प्रदेश का हाल है वैसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। मैं उनके नाम यहां पर कई बार गिना चुका हूं तथा अब और गिनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर वही पूछ रहा हूं कि आपने जा बजट अलॉट किया है वह लग कहां रहा है? उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। रिपेयर और मैंटीनैंस में पैसा आता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है। वहां पी0एच0सी0 कांगू और सी0एच0सी0 नादौन की बिल्डिंगें कई सालों से बन रही है। मैंने पीछे एक प्रश्न किया था कि कांगू की बिल्डिंग कब तक दे दी जायेगी? उन बिल्डिंग्ज को जल्दी-से-जल्दी हैंड ओवर कर दिया जाए। इसमें धनेटा-बंगाणा टनल की कोई चर्चा नहीं हुई। पता नहीं आपकी इस बारे में क्या मंशा है? धौलासिद्ध प्रोजैक्ट की इसमें कोई बात नहीं हुई। स्पाइस पार्क की कोई चर्चा नहीं हुई। मैं यहां पर एक बात बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि

गलोड़ में कॉलेज खोला जाए। मैं उसकी मांग करता हूं। बाकी चीजों के साथ-साथ मैं यह चाहता हूं कि नदौन निर्वाचन क्षेत्र भी आगे बढ़े और आप लोग उसकी चिन्ता भी करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि बैठ जाओ तो मैं बैठ जाता हूं। मैं अब एक शेर बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

कौन समझेगा यहां दिल की जुबां,
यही सोचकर बेजुबां हो गया हूं।

17.3.2016/1950/av/2

उद्योग मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर माल्वा कॉटन मिल की बात की है। उस मिल पर 1500 करोड़ रुपये का कर्ज है। उस पर डैट का केस है। जिसके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है उसको औद्योगिकीकरण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। 1500 करोड़ रुपये का कर्ज है तो पैसा उसको देना है। यहां पर माननीय धूमल जी ने भी बात की थी और हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं तथा पूर्व मुख्य मंत्री है इसलिए मैंने उस पर दोबारा बात करनी नहीं चाही। कहा कि परवाणू में 63 कनैक्शन्ज कटे हैं। ऐसे वर्ष 2008 से 2013 तक परवाणू में 113 बिजली के कनैक्शन कटे हैं। हमारे यहां 46 हजार कारखाने हैं और उसमें 60 कटे, 200 कटे; यह कोई बहुत बड़े आंकड़े नहीं हैं। कुछ लोग कारखाने शिफ्ट कर लेते हैं और कुछ लोग बिजली का दोहन नहीं करते। इसलिए 63 के आंकड़े को जिस तरह पेश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह 46000 की सूची में ज्यादा मायने नहीं रखते। वर्ष 2008 से 2013 तक जो 173 कटे उसकी सूची मेरे पास है और मैं इसको सभा पटल पर रखता हूं। यह कहना कि यहां से कोई पलायन हो रहा है तो यह गलत है। यहां पर उद्योगों के लिए बैस्ट पॉसिबल ऐनवायर्नमैंट दिया जा रहा है। बिजली सबसे सस्ती दी जा रही है और बिजली फ्रीज की गई है। कभी किसी राज्य ने बिजली फ्रीज नहीं की मगर यहां हिमाचल ने की है। बिजली ड्यूटी सस्ती की गई और इस बार टैक्स भी कम किया गया। इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर सारी सुविधाएं दी हैं। यहां से कोई उद्योग

पलायन नहीं कर रहे हैं। उद्योगों को बचाकर रखने और इनवाइट करने के लिए यहां पर मुहिम छेड़ी गई है।

17.3.2016/1950/av/3

उपाध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमलाः171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांक 17.3.2016 **सचिव।**